R.N.I. NO.HIN/2002/8718 M.P./BHOPAL/642/2021-23

• वेंटिलेटर पर मप्र का उद्योग जगत • कृषि उत्पादों के निर्यात की जरूरत

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

www.akshnews.com

नई रणनीति... बड़ी चेतावनी

वर्ष 19, अंक-16 16 से 31 मई 2021 पृष्ठ-48 मूल्य 25 रूपये

सांसों की सौदेबाजी

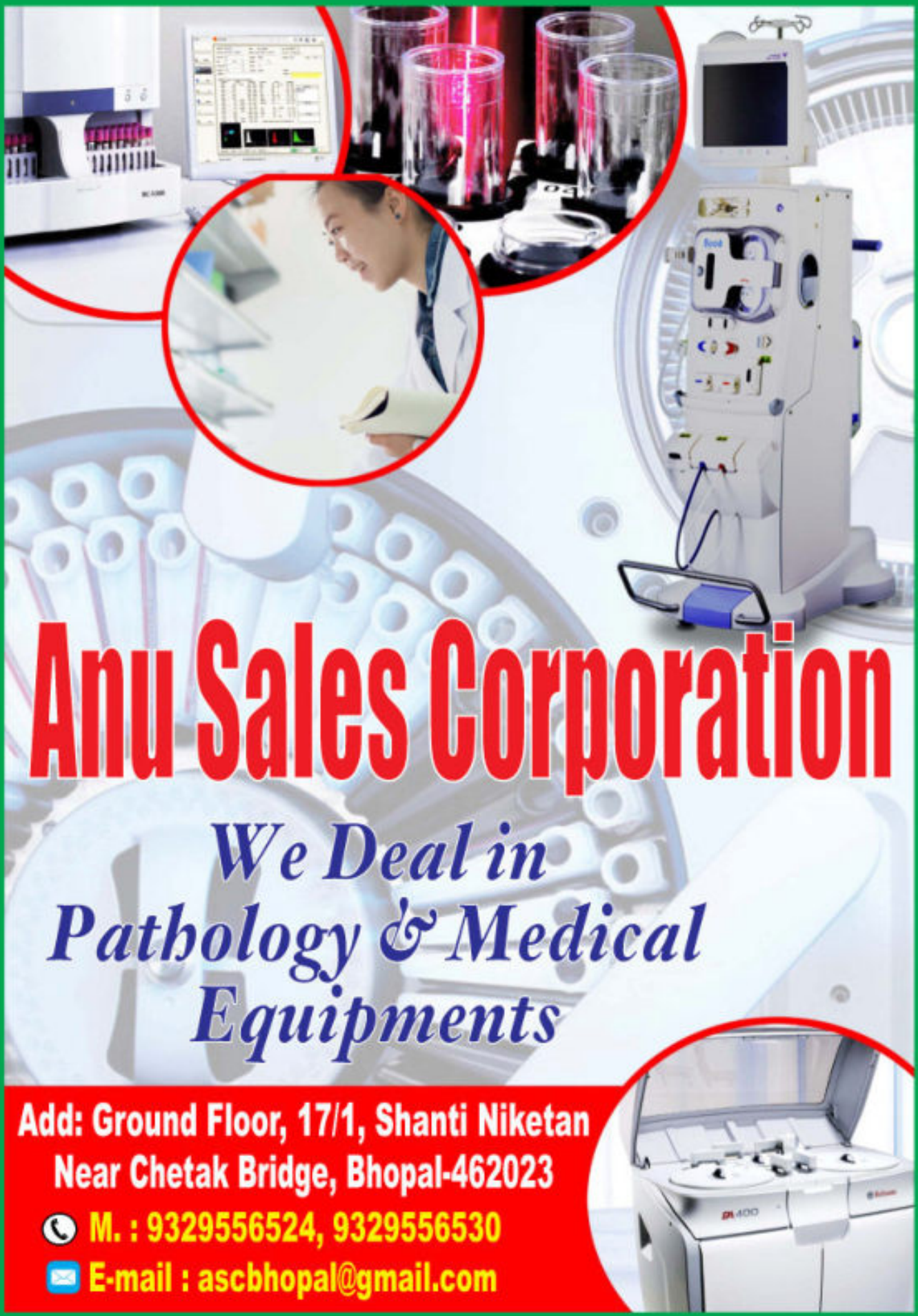
Anu Sales Corporation
We Deal in
Pathology & Medical
Equipments
Add: Ground Floor, 17/1, Shanti Niketan
Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
M. : 9329556524, 9329556530
E-mail : ascbhopal@gmail.com

इस अंक में

राजपाट

9 | राहत भी... भार भी

प्रदेश पहले से ही कर्ज में डूबा है, उस पर कोरोना संक्रमण ने अर्थव्यवस्था को पूरी तरह चरमरा दिया है। इस स्थिति में सरकार की कोशिश है कि वह राजस्व के लिए कमाई वाले विभागों को सक्रिय करे। इसके लिए प्रदेश सरकार...

राजपथ

10–11 | नई रणनीति... बड़ी चेतावनी

भाजपा को पार्टी विथ डिफरेंस कहा जाता है। अब पार्टी ऐसा करके दिखाने भी लगी है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने भाजपा की राजनीति ही बदल डाली है। असम में हिमंता बिस्वा सरमा को मुख्यमंत्री...

मुनाफाखोरी

14 | मुनाफाखोरी ने बढ़ाई समस्या

ऑक्सीजन मनुष्य के लिए प्राणवायु है। वातावरण में मौजूद जिस ऑक्सीजन के जरिए हमारी सांसों की डोर चलती है, उसके लिए हमें न तो पैसे खर्च करने पड़ते हैं और न ही कतार लगानी पड़ती है। शायद इसीलिए ऑक्सीजन के प्रति...

भर्राशाही

19 | खाद बिगाड़ेगी खेती का गणित

कोरोना महामारी के बीच किसानों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। कभी मंडी में बारदानों के कमी के कारण गेहूं की खरीदी में रुकावट, कभी भुगतान में देरी, तो कभी हम्मालों की कमी...। किसान आए दिन ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। अब सरकार के एक निर्णय ने उन्हें आर्थिक मार...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

देश में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने के बाद जब पहली बार लॉकडाउन किया गया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की थी कि यह समय आपदा को अवसर बनाने का है। सरकार भले ही आपदा को अवसर नहीं बना पाई, लेकिन कालाबाजारियों ने इसे जमकर भुनाया। दूसरी लहर में जिस तरह ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और अन्य दवाओं की कालाबाजारी हुई, उससे मानवता तार-तार हो गई। लालची कालाबाजारियों ने सांसों की जमकर सौदेबाजी की।

राजनीति

30–31 | ममता पर दांव लगाने का वक्त

5 राज्यों में संपन्न विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जिस तामझाम और दल-बल के साथ बंगाल चुनाव लड़ा था उसके अनुसार परिणाम नहीं मिले। यानी भाजपा की रणनीति और नीति पर ममता बनर्जी हावी रहीं। ऐसे में बंगाल चुनाव परिणाम ने विपक्ष को इसका संकेत दिया है...

महाराष्ट्र

36 | मराठा आरक्षण की जरूरत किसको?

सुप्रीम कोर्ट ने मराठा समुदाय को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण देने वाले महाराष्ट्र के कानून को 'असंवैधानिक' करार दे दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र की 'सियासी चाय' में एक नया उबाल आने के संकेत मिलने लगे हैं। एंटीलिया केस और 100 करोड़...

बिहार

38 | पप्पू पास हो गए...

कोविड महामारी की चपेट में आई हर नजर पप्पू यादव की तरफ आखिरी उम्मीद से देख रही थी, बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने पूर्व सांसद और जन अधिकारी पार्टी के नेता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जाहिर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही...

6-7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

आखिर कितनी गंदगी ढोएगी गंगा...?

किसी कवि की पंक्तियां हैं...

खुद को मैली देखकर, गंगा हुई उदास।
निर्मल जलधारा नहीं, पहले जैसी पास।।

पतित पावनी गंगा का यह आर्तनाद भले ही किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन आज उसे पूरा विश्व देख रहा है। कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, बक्सर, उन्नाव के गंगा घाटों पर रेत में दबे और किनारों पर उतराते शवों का अंबार हर एक व्यक्ति का मन विचलित कर रहा है। सवाल भी उठने लगे हैं कि आखिर कितनी गंदगी ढोएगी गंगा? दरअसल, कोरोना महामारी में सारा देश त्रस्त है। व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा चुकी हैं। संघीय व्यवस्था कागजों में भले ही हो, लेकिन राजधानी दिल्ली से लेकर सुदूरवर्ती गांव तक एक जैसा ही कोहराम है। जो भयावह स्थिति भारत में बन गई है उससे अधिक दुखदाई मानव सभ्यता के लिए और क्या हो सकता है। वैसे मृतकों को मुखाग्नि देकर जल प्रवाहित करना भारत में लोग करते रहे है, लेकिन अब जब से अंधाधुंध मौतों का सिलसिला इस महामारी में शुरू हुआ है उसमें ऐसी भयावह स्थिति बन गई है कि अब तो मुखाग्नि देने भी अपने परिवार के सदस्य मृतक के पास नहीं होते। क्योंकि इस महामारी के लिए देखा यह गया है कि जो भी कोरोना के मरीज के आसपास होता है, उस पर विषयुक्त कीटाणु टूट पड़ता है। अब जो स्थिति बन गई है उसमें भारत में प्रतिदिन लाखों व्यक्ति इसके शिकार होते हैं। हजारों में उनकी मौत होती है जिसके कारण श्मशान और कब्रिस्तान में स्थान कम पड़ गए है। परिणाम स्वरूप उन्हें मुखाग्नि दिए बिना अथवा मुखाग्नि देकर बड़ी-छोटी नदियों के हवाले कर दिया जाता है, जिसे चील, कौवे और कुत्ते अपना उपयुक्त आहार बनाते हैं। जिस गंगा नदी को साफ करने के लिए सरकार ने एक मंत्रालय बनाया अरबों रुपए गंगा को साफ करने में लगाए उस गंगा की यह दुर्दशा कैसे होती रही और सरकारी महकमा उसकी सुरक्षा के लिए कहां गायब रही यह बात समझ में नहीं आती। सबके मन में यह सवाल है और मन दुखी भी है कि आखिर, गंगा कितनी गंदगी को साफ करेगी और कब तक? जो विभत्स फोटो कई टीवी चैनलों तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं, उसे देखकर मन खिन्न हो जाता है और सरकार की लापरवाही पर उन्हे कोसना पड़ता है। आखिर नदियों की पूज्य मानने वाले ग्रामीणों के मन में यह क्यों नहीं कौंधा कि वे इस तरह शव बहाकर घोर अनर्थ कर रहे हैं और इससे उनकी और उनके क्षेत्र के साथ देश की भी बदनामी होगी? क्या यह माना जाए कि ग्रामीण इलाकों में एक वर्ग ऐसा है, जो अभी भी नदियों की शुद्धता की परवाह नहीं करता? ये वे गंभीर सवाल हैं, जिनका जवाब तलाशा ही जाना चाहिए। बेहतर हो कि इसकी कोई जांच हो कि किन कारणों से गंगा में शव बहाए गए? इसी के साथ इसकी कोई ठोस व्यवस्था होनी चाहिए कि भविष्य में कोई भी इस तरह नदियों से खिलवाड़ न कर सके। यह ठीक है कि कुछ ग्रामीण इलाकों में शवों को नदियों में बहाने या फिर उनके तटों पर दफनाने की परंपरा है, लेकिन कम से कम अब तो सबको यह समझ आ जाना चाहिए कि यह एक खराब और बेहद हानिकारक परंपरा है। इसे हर हाल में रोका जाना चाहिए। एक ऐसे समय और भी, जब नदियों को दूषित होने से बचाने के लिए व्यापक अभियान चलाए जा रहे हैं। परंपराओं या फिर मजबूरी के नाम पर नदियों को दूषित नहीं होने दिया जा सकता। प्रकृति में बढ़ते प्रदूषण का ही परिणाम आपदा है। इसलिए अब समय है कि गंगा सहित अन्य नदियों को गंदा होने से बचाना होगा।

- राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 19, अंक 16, पृष्ठ-48, 16 से 31 मई, 2021

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
मुंबई :- ऋतेन्द्र माथुर, **कोलकाता:-** इंद्रकुमार,
जयपुर:- आर.के. बिन्नानी, **छत्तीसगढ़:-** संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी, टी.पी. सिंह, **लखनऊ :-** मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
098934 77156, (विदिशा) ज्योत्सना अनूप यादव

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी-फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : 39 श्रुत्रि सिलटर निपानिया, इंदौर मोबाइल - 7000123977

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

भूमाफिया पर शिकंजा

मप्र में इन दिनों माफिया की दुनिया में शासन-प्रशासन का खौफ दिखाई दे रहा है। प्रदेश में भूमाफिया, गुंडा तत्वों और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों पर पुलिस-प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। सरकार एक-एक माफिया से सरकारी जमीनों को मुक्त करवा रही है।

● **कुसुम मीणा,** ग्वालियर (म.प्र.)

किसानों का हित

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के किसानों के हित में खेती को लाभप्रद बनाने और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। प्रदेश के किसानों को सरकार से मिल रहे संबल से किसानों ने प्रमुख रूप से गेहूं उत्पादन में रिकार्ड कायम किया।

● **पुरुषोत्तम शर्मा,** इंदौर (म.प्र.)

संकट में बाघ

मप्र में बाघों पर संकट केवल अवैध शिकार की वजह से नहीं है। विकास के नाम पर खत्म हो रहे जंगल भी उनके अस्तित्व के लिए बड़ा संकट है। पन्ना टाइगर रिजर्व में हाल के कुछ वर्षों में बाघों की संख्या तेजी से बढ़ी है, ऐसे में इस परियोजना से बाघों पर विपरीत असर पड़ना तय है।

● **रूपाली दीक्षित,** जबलपुर (म.प्र.)

किस हद तक गिर सकते हैं मानवता के दुश्मन

कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने देशवासियों को झकझोर दिया है। इस कठिन समय में लोगों की सांसें डरी और सहमी हुई हैं। इस त्रासदी में बड़ी संख्या में लोगों का महाप्रयाण बेहद पीड़ादायक है। ऐसे भीषण समय में जब समूची मानवता कराह रही है, लुटेरों, चोरों और ठगों द्वारा मौत से जूझ रहे लोगों और उनके परिजनों को ठगने का काम बेरोकटोक जारी है। जब लोग मौत से जूझ रहे हों तब जीवन रक्षक दवाई रेमडेसिविर की चोरी बेहद दुखदाई है। इन लुटेरों को लोगों की मौतों में भी कमाई का अवसर दिख रहा है। मानवता के दुश्मन ये लोग अपनी जेबें भरने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं।

● **संतोष पांडे,** भोपाल (म.प्र.)

बदल रही है देश की राजनीति

देश की राजनीति बदल रही है, मगर यह परिवर्तन इतना धीरे-धीरे होता है कि समझ में नहीं आता। कई वर्षों बाद यह परिवर्तन स्पष्ट होता है, तब जाकर वास्तविकता समझ में आती है। एक समय था जब एक ही पार्टी का शासन पूरे देश में होता था। फिर धीरे-धीरे दूसरी पार्टियां सामने आईं। उन्होंने समाजवाद की बात की लेकिन वह ज्यादा समय तक सफल नहीं हो पाईं। फिर दलित पार्टियां भी विकल्प बनकर आईं, वह भी कुछ दिन कुछ राज्यों में सफल रहीं। अब फिर एक पार्टी 'सबका साथ सबका विकास' के नाम पर पूरे देश में फैलती जा रही है।

● **राजेश पुरोहित,** सीहोर (म.प्र.)

मजदूर की मजबूरी

पन्ना जिला मप्र के उन कुछेक जिलों में आता है जहां बच्चों और महिलाओं में कुपोषण और एनीमिया सबसे अधिक है। खदानों में काम करने वाली महिलाएं सामान्यतः एनीमिया से ग्रसित हैं। यानी खून की कमी से। पर्यावरण के सख्त नियमों की वजह से वैध खदान बंद हो रहे हैं। रोजी-रोटी के लिए कुछ मजदूरों को अवैध खदानों में वन विभाग और पुलिस की कार्रवाई के खतरों के बीच काम करना पड़ता है।

● **लिदा खान,** पन्ना (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

अब सकारात्मकता भरोसे सरकार-संघ

कोरोना की मार से त्रस्त देश का अब केंद्र सरकार और भाजपा से मोहभंग होने लगा है। भाजपा शासित राज्यों में हालात इतने भयावह हैं कि स्थानीय भाजपा नेताओं तक ने अपनी ही सरकारों के खिलाफ स्वर बुलंद करने शुरू कर दिए हैं। उप्र में योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली से खफा कई सांसद, विधायक खुलकर सरकारी इंतेजामात पर टीका-टिप्पणी कर रहे हैं। केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने अपने गृह क्षेत्र बरेली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर न केवल योगी को खत लिखा, बल्कि उसे सार्वजनिक भी कर डाला। कर्नाटक में भी येदियुरप्पा सरकार की विफलता के चलते भाजपा विधायकों में भारी बेचैनी पसर चुकी है। गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की कार्यशैली पर वहां के स्वास्थ मंत्री मोर्चा खोल चुके हैं। ऐसे में भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मदद से 'सकारात्मक सोच' का माहौल बनाने की तैयारी कर रहा है ताकि केंद्र और भाजपा शासित राज्यों की सरकारों पर पड़ रहे दबाव को कम किया जा सके। खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत भाजपा और सरकार को बचाने के लिए मोर्चा संभालने वाले हैं। चर्चा जोरों पर है कि केंद्र सरकार और भाजपा नेतृत्व सबसे ज्यादा परेशान सोशल मीडिया से है जो सच्चाई छुपाने के सारे प्रयासों को धता बताने का काम कर रहा है।

फिर राज्यपाल की शरण में भाजपा

भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व बंगाल में मिली करारी हार को स्वीकार नहीं पा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की जी-तोड़ मेहनत, केंद्रीय जांच एजेंसियों का भरपूर सहारा, तृणमूल कांग्रेस में सेंधमारी आदि सबकुछ आजमाने के बाद भी पार्टी राज्य में 100 सीटों का आंकड़ा तक पार नहीं कर पाई। इस हार से तिलमिलाई पार्टी अब बंगाल के राज्यपाल को मोहरा बनाकर ममता बनर्जी को घेरने में एक बार फिर से जुट गई है। ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण बाद राज्यपाल जगदीश धनखड़ ने तृणमूल के तीन विधायकों के खिलाफ सीबीआई को मुकदमा दर्ज करने संबंधी सहमति पत्र दे डाला। इन तीनों विधायकों का नाम शारदा स्टिंग मामले में सामने आया था। 2016 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले सामने आए इस स्टिंग ऑपरेशन पर कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद से ही मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। अब भाजपा की चुनावों में करारी हार के बाद राज्यपाल के इस कदम ने नाना प्रकार की चर्चाओं को जन्म दे डाला है। संविधान विशेषज्ञों के अनुसार राज्यपाल के पास विधायकों के खिलाफ इस प्रकार की संस्तुति का अधिकार है ही नहीं। यह अधिकार राज्य विधानसभा के अध्यक्ष का होता है। जानकारों की मानें तो भाजपा किसी भी सूरत में ममता बनर्जी सरकार को अस्थिर करना चाहती है।

दागियों की शरणस्थली

अपने चाल और चरित्र पर नाज करने वाली, देश को 'भय, भूख और भ्रष्टाचार' से निजात दिलाने का दावा करने वाली भाजपा हर प्रकार के दागियों की शरणस्थली बन चुकी है। जैसे-जैसे पार्टी का विस्तार होता गया, भ्रष्टाचार और आपराधिक मामलों के महारथी इसमें शामिल होते चले गए हैं। ताजा उदाहरण पश्चिम बंगाल और असम हैं जहां शारदा चिट फंड घोटाले के आरोपी शुभेंदु अधिकारी, दिनेश त्रिवेदी समेत कइयों ने ईडी, सीबीआई आदि के भय से निजात पाने के लिए तृणमूल का दामन झटक भाजपा में शरण ले ली। असम में भाजपा की जड़ें जमाने वाले पूर्व कांग्रेसी नेता हिमंता बिस्वा सरमा ने भी ठीक इसी प्रकार शारदा चिट फंड एवं लुइस बर्जक स्कैम में नाम आने के बाद भगवा होने में ही अपनी भलाई समझी। पूर्वोत्तर के सातों राज्यों में भाजपा की जड़ें सरमा ने ही फैलाई। इसका ईनाम भी उन्हें बंपर मिला है। निवर्तमान मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनेवाल के स्थान पर उन्हें भाजपा आलाकमान ने राज्य की गद्दी सौंप दी है। भाजपा सूत्रों की मानें तो आलाकमान के इस फैसले से खांटी भाजपाइयों में खासा असंतोष पनप रहा है। विशेषकर सर्वानंद सोनेवाल की पैरवी कर रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हिमंता बिस्वा सरमा की ताजपोशी कतई नहीं सुहा रही है।

सिन्हा या पीके राज्यसभा में

दिल्ली के सत्ता गलियारों से लेकर कोलकाता की रायटर्स बिल्डिंग तक इस बात की खासी चर्चा है कि ममता दीदी अपने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और तृणमूल कांग्रेस में हालिया शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को राज्यसभा भेजने जा रही हैं। राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा ने तृणमूल के गढ़ में सेंधमारी कर पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेद्री को पार्टी में शामिल करवा डाला था। त्रिवेदी तृणमूल के राज्यसभा सांसद थे। उन्होंने पाला बदलने के बाद राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। उनकी सीट के अभी चार बरस बाकी हैं। चर्चा जोरों पर है कि ममता बनर्जी यशवंत सिन्हा या प्रशांत किशोर में से किसी एक को इस सीट से राज्यसभा भेजने का मन बना रही हैं। ज्यादा संभावना यशवंत सिन्हा की बताई जा रही है। सिन्हा का कद और अनुभव तृणमूल के लिए खासा फायदेमंद साबित हो सकता है। इतना ही नहीं उनको राज्यसभा भेजने से तृणमूल को बिहार और झारखंड में भी अपनी जड़ें मजबूत करने में मदद मिलेगी।

मित्रता की ओर पुलिस

उत्तराखंड पुलिस का धेय वाक्य है, 'मित्र पुलिस।' उत्तराखंड पुलिस के पिछले दिनों बने नए महानिदेशक अशोक कुमार इस वाक्य के साथ कदमताल करने की कोशिश में हैं। पुलिस महानिदेशक बनने से पहले भी वे पुलिस की छवि सुधारने के लिए कई मानवीय प्रयोग करते रहते थे। कुंभ मेले में उन्होंने इस अभियान को जमीन पर उतारा। भिक्षा मांग रहे युवकों की पहचान कर उन्हें नए कपड़े दिए और उनकी सेहत ठीक करने पर ध्यान दिया। उन्हें हरिद्वार के बड़े होटलों में खानसामे का प्रशिक्षण दिया गया। कुंभ मेले में पुलिस की रसोइयों में उन्हें बकायदा नौकरी दी गई। इसके साथ ही पुलिस ने कोरोना मरीजों की मदद के लिए 'मिशन हौंसला' अभियान की शुरुआत की। उन्होंने पूरे प्रदेश में हर जिले में पुलिस के शिविर लगवाए और एंटीबॉडी जन टेस्ट करवाए। पुलिसवालों का प्लाज्मा कोरोना के जरूरतमंद मरीजों को देने का अभियान शुरू किया गया। जो मरीज घर में ऑक्सीजन की जरूरत महसूस कर रहे हैं पुलिस उन तक ऑक्सीजन पहुंचा रही है।

7 साल बाद खुशी का अहसास

राज्य पुलिस सेवा के सबसे सीनियर एक दर्जन अफसरों को सुपर सीनियर सिलेक्शन ग्रेड दिए जाने का रास्ता धीरे-धीरे साफ होता जा रहा है। प्रस्ताव की फाइल गृह विभाग के बाद अब वित्त विभाग तक पहुंच गई है। इस श्रेणी के वेतनमान को पाने के लिए पिछले सात साल से एसपीएस एसोसिएशन लगातार प्रयास कर रही है, इसके बाद भी अब तक सरकार ने उनके इस वेतनमान को स्वीकार नहीं किया है। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर कोई भी अफसर फिलहाल कुछ बोलने को तैयार नहीं है। राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को वर्ष 2012 में राज्य शासन ने चार से बढ़ाकर पांच ग्रेड पे कर दिए थे। जबकि राज्य पुलिस सेवा के अफसरों को अब तक सिर्फ चार ग्रेड पे ही तय हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को वेतन की पांच श्रेणी करने के बाद से ही एसपीएस भी चार से बढ़कर पांच ग्रेड पे चाह रहे हैं। इसके तहत एसपीएस एसोसिएशन के लंबित पड़े प्रस्ताव पर ठीक एक साल पहले गृहमंत्री ने अनुमोदन कर दिया था। इसके बाद कई महीनों तक यह फाइल गृह विभाग में अटकी रही, गृह विभाग ने अब इस फाईल को वित्त विभाग को भेज दिया है। फिलहाल अब प्रस्ताव वित्त विभाग के पास लंबित है। यदि यह प्रस्ताव मंजूर हुआ तो एक दर्जन अफसरों को इसका लाभ मिलेगा। उन्हें सुपर सीनियर सिलेक्शन ग्रेड में शामिल करते हुए उनका वेतनमान 8900 रुपए की श्रेणी में आ जाएगा।

सारी खुदाई एक तरफ

सारी खुदाई एक तरफ... यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी। लेकिन राजधानी के एक नामी अस्पताल के संचालक को इस कहावत का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सत्ता के करीब होने का फायदा उठाकर डॉक्टर साहब ने भोपाल की लाइफलाइन की गोद में बड़ा अस्पताल तो बनवाया ही है, साथ ही कोरोना महामारी में सबसे कमाऊ अस्पताल भी बना है। बावजूद इसके डॉक्टर साहब की कमाई करने की लालसा थमी नहीं है। आलम यह है कि डॉक्टर साहब के साले और साले के बेटे भी उसी लाइन पर चल रहे हैं। विगत दिनों साले के बेटे ने आयुष्मान योजना के तहत इलाज कराने की गुहार लगाते एक मरीज के परिजन को अस्पताल के बाहर उठाकर फेंकने का निर्देश दिया। इसका विरोध जमकर वायरल हुआ और राजनीति से लेकर प्रशासनिक वीथिका में जमकर चर्चा हुई। इससे पहले डॉक्टर साहब के साले का भी एक ऑडियो वायरल हुआ था। जिसमें अस्पताल में होने वाली मौतों को लेकर भयावह स्थिति बताई गई थी। अपने साले के ऑडियो को लेकर डॉक्टर साहब कई दिनों तक परेशान रहे। अब साले के बेटे के वीडियो ने उन्हें परेशानी में डाल दिया है। हालांकि डॉक्टर साहब के लिए राहत की बात यह है कि सरकार के एक मंत्री ने पूरे विवाद पर यह कहकर पर्दा डाल दिया है कि डॉक्टर साहब ने साले के बेटे के बयान का खंडन कर दिया है।

बंगाल में हार से खुश भाजपाई दिग्गज

पश्चिम बंगाल में तमाम तरह की पैंतरेबाजी के बाद भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। भाजपा की इस करारी हार से जहां विपक्षी दल उत्साहित हुए हैं, उनसे कहीं अधिक भाजपा के भीतर खुशी की खबरें आ रही हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस हार से एक राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री को सबसे ज्यादा राहत महसूस हो रही है। दरअसल, बंगाल में दीदी को हराने के लिए हृदयप्रदेश के दो कद्दावर नेता मोर्चा संभाले हुए थे। इनमें से एक तो भाजपा के मिशन बंगाल का चेहरा ही थे। वहीं दूसरे नेता जो अपने प्रदेश की सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने भी खूब मेहनत की। पार्टी इन्हें अपना शुभंकर मानती है। इसकी वजह यह है कि अभी तक इन्हें जिन राज्यों में जिन सीटों को जिताने की जिम्मेदारी दी गई है, उसमें इन्होंने सफलता पाई है। लेकिन दीदी के जादू के आगे किसी की नहीं चली। यदि बंगाल में पार्टी को जीत मिलती तो इन दोनों नेताओं का कद खासा बढ़ जाता। कहा तो यह भी जा रहा था कि जीत के ईनाम के रूप में इनको सत्ता का मुखिया बना दिया जाता। लेकिन इनकी मंशा पर पानी फिर गया। वहीं उन नेताओं की बांछे खिल गई हैं, जो अभी सत्ता और संगठन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जानकारों का दावा है कि कई पुराने दिग्गज भाजपाई भी खासे प्रसन्न हैं। खबर है कि इन दिनों मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए गए आडवाणी और जोशी के घर ऐसे नेताओं की आवाजाही बढ़ने लगी हैं।

मेहनत का मिलेगा ईनाम

कोरोना संक्रमणकाल में कई अधिकारियों ने रातदिन मेहनत करके सरकार के मुखिया का मन जीत लिया है। ऐसे ही अफसरों में 1998 और 2001 बैच के दो आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं। इन दोनों में कई समानताएं हैं। ये दोनों अधिकारी सीधी भर्ती के आईएएस हैं। दोनों अधिकारी ग्वालियर और इंदौर के कलेक्टर रहे हैं। दोनों अधिकारियों की योग्यता पर सरकार के मुखिया को भरोसा है। यही कारण है कि पिछले दिनों कोरोना आपातकाल में इन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी। बताया जाता है कि दोनों अधिकारियों ने मुखिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। जिसका परिणाम यह है कि प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में आ गया है। अब जैसे-जैसे कोरोना के मामले ढलान पर हैं, इन दोनों अधिकारियों के काम का मूल्यांकन शुरू हो गया है। सूत्र बताते हैं कि आने वाले दिनों में सरकार इन्हें ईनाम के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। गौरतलब है कि दोनों अफसर हर पदस्थापना में अपनी छाप छोड़ जाते हैं। इसलिए संभावना जताई जा रही है कि सरकार इन्हें कोई चुनौतीपूर्ण काम सौंपेगी।

करोड़ों की हवेली

प्रशासनिक सेवा हो या पुलिस की सेवा, इसमें आते ही अधिकारियों का सबसे पहला प्रयास होता है एक आलीशान मकान बनाने का। हर एक की कोशिश होती है कि कम से कम राजधानी में तो उसका एक बड़ा आशियाना तो हो ही। राजधानी पुलिस के एक अफसर को शहर का मौसम रास आ गया है। दो साल से वह अपने रहने के लिए एक शानदार लोकेशन पर हवेलीनुमा घर ढूंढ रहे थे। जिसकी तलाश पूरी हो गई है। साहब ने शाहपुरा की प्राइम लोकेशन पर एक शानदार कॉलोनी में दो प्लाट के भूखंड पर हवेली तैयार करवाई है। इसका काम लगभग पूरा हो चुका है। साहब इस हवेली में रहने जाने वाले ही थे। जयपुर से आए झूमर लगाए जा रहे थे। उसी समय कोरोना आ गया और काम को बंद कराना पड़ा। खैर, साहब को उनकी नई हवेली के लिए बहुत-बहुत बधाई। चर्चा है कि साहब की टीम ने उनकी इस हवेली में जयपुर के झूमर और किशनगढ़ का पत्थर लगवाने में काफी मदद की है। साहब के पास आने वाले भारी लिफाफे अब झूमर वाले के पास पहुंच रहे हैं, जिससे किसी को शक नहीं हो पाए।

कोरोना महामारी की इस आपदा में भी केंद्र सरकार कमाई का अवसर नहीं छोड़ रही है। वैक्सीन के साथ ही कोरोना महामारी से निपटने के लिए जरूरी चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी वसूला जा रहा है। केंद्र सरकार इसे जल्द खत्म करे।

● **गौरव वल्लभ**

कांग्रेस कोविड-19 के खिलाफ जारी देश की लड़ाई में लोगों को गुमराह और भयभीत कर रही है। राहुल गांधी सहित कांग्रेस के नेताओं का व्यवहार छल-कपट और ओछेपन वाला है। यह स्थिति ऐसे समय में पैदा की गई, जब देश संकट में जूझ रहा है और वह भी सदियों में एक बार आने वाली महामारी से। जनता कांग्रेस की इस नीयत का जवाब देगी।

● **जेपी नड्डा**

भारतीय क्रिकेट टीम वाकई में लाजवाब है। आईसीसी ने टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए बीच में नियम बदले, पर हमारे लड़कों ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर चुनौतियों का बहादुरी से सामना किया है। टेस्ट में नंबर-1 का ताज एक ऐसी चीज है, जो टीम इंडिया के लड़कों ने निष्पक्ष तरीके से जीता है। मुझे अपनी टीम पर गर्व है।

● **रवि शास्त्री**

मेरी सभी पोस्ट या तो इंसानियत के लिए या फिर देश के लोगों के लिए होती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मुझे कंगना जैसे लोगों जिनका अकाउंट नफरत फैलाने की वजह से सस्पेंड किया जा चुका है, वे मुझे सुना रही है।

● **इरफान पठान**

बॉलीवुड में एंट्री करने से पहले, हर कोई मुझसे कहता था कि मैं अपनी मां की तरह दिखती हूं। फिर यहां आने के बाद ही मुझे पता चला कि मैं कैटरीना जैसी भी दिखती हूं और ये बॉलीवुड में मेरी एकमात्र पहचान बन गई है। लोगों को मेरे बारे में अपनी राय बनाने का मौका नहीं दिया गया, क्योंकि वीर की रिलीज से पहले ही लोगों के दिमाग में कैटरीना-एंगल बैठ गया था। बॉलीबुड में डुप्लीकेट के साथ कोई काम नहीं करना चाहता। स्नेहा उल्लाल, जिन्हें सलमान खान ने फिल्म लकी में लॉन्च किया था। उनको उस समय ऐश्वर्या राय की डुप्लीकेट कहा जा रहा था और इसने उनके कैरियर को बर्बाद कर दिया था। अमीषा पटेल को अमृता सिंह से मिलता-जुलता कहा गया था और हरमन बावेजा को ऋतिक रोशन के डुप्लीकेट का टैग दिया गया था। कोई भी बॉलीवुड में किसी की डुप्लीकेट बन कर नहीं रहना चाहता है और फिल्म मेकर्स भी डुप्लीकेट के साथ काम नहीं करना चाहते हैं।

● **जरीन खान**

वाक्युद्ध

मेडिकल रिसर्च जर्नल द लेसेंट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो टिप्पणी की है, वह इस बात का संकेत है कि केंद्र सरकार किस तरह कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर रोकने में नाकाम रही है। देश में मौत के आंकड़े बढ़ने के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। फिर भी भाजपा विपक्ष पर राजनीति का आरोप लगा रही है।

● **रणदीप सुरजेवाला**

देश में एक लोकतांत्रिक सरकार है और वह अच्छे तरीके से महामारी से निपटने में लगी हुई है। लेकिन विपक्ष को आपदा में भी राजनीति सूझ रही है। सरकार किस तरह काम कर रही है, इसके लिए भाजपा को किसी विदेशी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मेरे देश की जनता काबिल है। यह बात कांग्रेस को कब समझ में आएगी।

● **संबित पात्रा**

राहत भी... भार भी

450 करोड़ रुपए की आय का अनुमान

नई शराब नीति के मसौदे को कैबिनेट में मंजूरी तो जरूर मिल गई लेकिन अब देखना यह है कि सरकार के इस फैसले में कितने दुकान संचालक दिलचस्पी दिखाते हैं। क्योंकि सरकार ने यह भी तय कर दिया है कि यदि कोई शराब दुकानदार बढ़ी हुई फीस नहीं देगा तो सरकार नए सिरे से टेंडर बुलाकर दुकान नीलाम कर देगी। कोरोनावायरस काल के कारण सरकार को शराब से होने वाली आय में करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा है। अब उम्मीद जताई है कि अगर नई नीति पर अमल होता है तो सरकार को इससे करीब 450 करोड़ रुपए की आय होगी। अब शराब ठेकेदारों और आबकारी विभाग को इस नई नीति के कारण अवैध और मिलावटी शराब के धंधे से भी निपटना होगा। अफसरों का कहना है कि दाम बढ़ जाने के कारण मध्यमवर्गीय व निचले तबके का व्यक्ति सस्ती शराब खरीदना चाहेगा। इससे अवैध और मिलावटी शराब की बिक्री बढ़ेगी। इस समस्या से निपटने के लिए विभाग के पास पर्याप्त स्टाफ व बल भी नहीं है। सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में चौकसी बरतनी होगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में देसी व कच्ची शराब का धंधा ज्यादा चलता है।

प्रदेश पहले से ही कर्ज में डूबा है, उस पर कोरोना संक्रमण ने अर्थव्यवस्था को पूरी तरह चरमरा दिया है। इस स्थिति में सरकार की कोशिश है कि वह राजस्व के लिए कमाई वाले विभागों को सक्रिय करे। इसके लिए प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति बनाकर कमाई का रास्ता निकाला है। नई आबकारी नीति के तहत शिवराज सरकार ने प्रदेश की शराब दुकानों के ठेके अगले 10 महीनों के लिए लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ देने का फैसला किया है। यह ठेके एक जून 2021 से 31 मार्च 2022 तक के लिए होंगे। इन दस माह में सरकार को नवीनीकरण से 8,809 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व मिलने की संभावना है। दरअसल, सरकार की कोशिश यह है कि वह कोरोना के इस संक्रमणकाल में ठेकेदारों पर अधिक भार न डाले। लेकिन ठेकेदार 10 फीसदी बढ़ोत्तरी को भी भार मान रहे हैं। ठेकेदारों का कहना है कि पहले ही हम कर्ज में डूबे हुए हैं। ऐसे में 10 फीसदी बढ़ोत्तरी भी हमारे लिए घाटे का सौदा होगी।

कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने इस बार ऐसी आबकारी नीति लागू की है, जिसमें आमदनी अधिक हो और ठेकेदारों पर बोझ न पड़े। यही वजह है कि जिन ठेकेदारों के पास शराब दुकानों के ठेके हैं, उन्हें लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर अगले 10 महीनों के लिए ठेके देने का निर्णय लिया है। जिन जिलों में ठेकेदार 10 प्रतिशत की वृद्धि से सहमत नहीं होंगे, वहां छोटे-छोटे ग्रुप में टेंडर कराए जाएंगे। 11 मई को पिछली बैठक में लाइसेंस फीस 5 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव था, लेकिन गृहमंत्री ने यह तर्क देकर विरोध किया था कि शराब से कारोबारी खूब कमाते हैं, इसलिए लाइसेंस फीस ज्यादा बढ़ाई जानी चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को टाल दिया था। वाणिज्यिक कर विभाग के एक अफसर ने बताया कि चूंकि प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते शराब की दुकानें 10 अप्रैल से बंद हैं, अभी जल्दी खुलने की संभावना भी कम है। ऐसे में मौजूदा हालातों और कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए नई नीति लागू करने के बजाय वर्तमान लाइसेंस फीस में 5 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए कैबिनेट में भेजा गया जिसे टाल दिया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा गया, जिसे मंजूरी दे दी गई है।

मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि 10 प्रतिशत लाइसेंस फीस बढ़ाकर बड़े ठेकेदार तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि शादी-ब्याह का सीजन निकल चुका है। अब शेष 10 महीने के लिए 10 प्रतिशत फीस बढ़ाना न्यायोचित नहीं है। बता दें कि प्रदेश में शराब की नई नीति 1 अप्रैल से लागू होना थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते वर्तमान ठेकेदारों को लाइसेंस फीस में 5 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 31 मई तक के लिए लागू किया गया था। पिछले साल कोरोना के चलते सरकार को शराब से करीब 2500 करोड़ का नुकसान हो चुका है। इसकी एक वजह यह भी है कि पिछले साल अप्रैल में टोटल लॉकडाउन के कारण शराब दुकानें बंद रही। इसके बाद मई में ठेकेदारों ने दुकानें खोलने से इंकार कर दिया था, क्योंकि टेंडर के समय तय दुकान खुलने का समय कम कर दिया गया था। इस पर जून माह में आबकारी विभाग ने शराब दुकानें खोली थीं। इसमें सरकार को 2500 करोड़ राजस्व घाटा हुआ था।

प्रदेश में साल दर साल शराब की खपत बढ़ रही है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2002-03 में 7 करोड़ 40 लाख लीटर शराब की खपत थी। यह वर्ष 2019-20 में बढ़कर 32 करोड़ 20 लाख लीटर हो गई। खपत औसतन 21 प्रतिशत की दर सालाना बढ़ रही है। सरकार का अनुमान है कि शराब के रेट में कम वृद्धि होने से खपत बढ़ेगी। विभाग के एक अफसर ने बताया कि चूंकि प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते शराब की दुकानें 10 अप्रैल से बंद हैं और अभी जल्दी खुलने की संभावना भी कम है। मप्र लिकर एसोसिएशन के प्रवक्ता रामस्वरूप शिवहरे कहते हैं कि कोरोना आपदा के चलते कारोबार काफी घाटे में हैं और आगे भी फिलहाल कुछ ठीक होने की स्थिति नहीं है। हम जल्द ही वृद्धि कम करने के लिए मंत्री एवं सीएस से मुलाकात कर निवेदन करेंगे, उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। वहीं शासन 10 फीसदी वृद्धि को कम करने के लिए तैयार नहीं है। यदि ठेकेदार 31 मई तक नवीनीकरण नहीं कराते तो शासन ऐसी दुकानों के लिए ओपन टेंडर प्रक्रिया से भी ठेके दे सकता है। विगत वर्ष भी शासन ने वृद्धि कम नहीं की थी तब ठेकेदारों ने उच्च न्यायालय में याचिका पेश की थी।

● **राकेश ग्रोवर**

असम में भाजपा ने पूर्व कांग्रेसी नेता हिमंता बिस्वा सरमा को सूबे की कमान सौंप तथा पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को विपक्ष का नेता बनाकर उस मिथक पर पूर्ण विराम लगा दिया है, जिसके तहत कहा जाता था कि कांग्रेस अथवा बाहर से आए बागी, भाजपा में विधायक, सांसद, मंत्री तो बन सकते हैं, मगर किसी भी हालत में कांग्रेसी या बाहरी नेता को सीएम की कुर्सी नहीं मिल सकती। लेकिन अब नई भाजपा ने अपनी रणनीति में परिवर्तन करते हुए भाजपा में शामिल होने वाले बागी नेताओं को पार्टी अब सूबे का मुखिया भी बना सकती है।

नई रणनीति... बड़ी चेतावनी

भाजपा को पार्टी विथ डिफरेंस कहा जाता है। अब पार्टी ऐसा करके दिखाने भी लगी है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने भाजपा की राजनीति ही बदल डाली है। असम में हिमंता बिस्वा सरमा को मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी ने जहां अपनी नई रणनीति का खुलासा किया है, वहीं अपनों को बड़ी चेतावनी भी दी है। भाजपा की इस रणनीति ने मप्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बड़ी संभावना का द्वार भी खोल दिया है। यानी भविष्य में सिंधिया को पार्टी राज्य या देश में बड़ी जिम्मेदारी दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। गौरतलब है कि भाजपा में शामिल होने के बाद से ही कांग्रेसी सिंधिया को कोस रहे हैं कि भाजपा में उन्हें वह सम्मान नहीं मिलेगा, जो कांग्रेस में मिलता था। लेकिन हिमंता बिस्वा सरमा मामले ने दूसरी पार्टियों से भाजपा में आए नेताओं के लिए बड़ा संदेश दे दिया है।

हिमंता बिस्वा सरमा उन नेताओं के लिए रोल मॉडल बन गए हैं, जो अपनी मातृसंस्था छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं या फिर जहां भी हैं वहीं से ऐसा करने की सोच रहे हैं। वकालत के पेशे से 15 साल कांग्रेस और 5 साल भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहने के बाद असम के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने जा रहे, हिमंता बिस्वा सरमा सपनों के उड़ान का खुशनुमा एहसास लगते हैं, सपनों को हकीकत में बदलने वाली कामयाबी की दास्तां लगते हैं और अपने जैसे तमाम नेताओं के लिए उम्मीदों की नई किरण बिखेर रहे हैं।

हिमंता बिस्वा सरमा निराश हो चुके मुकुल रॉय और टॉम वडक्कन जैसे नेताओं का आत्मविश्वास बढ़ाने वाली शख्सियत बन गए हैं। शुभेंदु अधिकारी और हाल फिलहाल भाजपा ज्वाइन करने वाले नेताओं के लिए वो आशा की किरण नजर आ रहे होंगे और बकाये के भुगतान का बेसब्री से इंतजार कर रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेताओं के लिए सकारात्मक सोच की वजह बन गए हैं। ऐसा भी नहीं कि हिमंता बिस्वा सरमा को बैठे बिठाए अच्छे कर्मों को फल मिल गया है, बल्कि उसके लिए सरमा ने साम, दाम, दंड और भेद जैसे सियासी हथियारों और औजारों की बदौलत अपना हक और हिस्सा हासिल किया है।

मान लेते हैं कि देर से ही सही, हिमंता बिस्वा सरमा को भाजपा से एक्सचेंज ऑफर में ही मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली है, लेकिन भाजपा भी कोई कच्ची गोटी तो खेलती नहीं, कुछ भी करने से पहले सौ बार सोच-विचार करती है और तब कहीं जाकर तमाम पेंच फंसाते हुए ऐसे फैसले लिए जाते हैं जिनसे प्रभावित होने वाले को फायदा मिले न मिले एक उम्मीद जरूर बन जाए कि कभी न कभी फायदा मिल तो सकता ही है। ऐसा लगता है हिमंता बिस्वा सरमा, भाजपा के अच्छे दिनों... के लेटेस्ट वर्जन वाले पॉलिटिकल-टूल-किट के सैंपल के

दूसरों के लिए अपनों पर नकेल

सिंधिया प्रकरण के बाद नवंबर 2020 में हुए विधानसभा उपचुनाव में यह बात देखने को भी मिली थी जब सिंधिया समर्थक 22 विधायकों में से अधिकांश दोबारा जीतकर आ गए थे। तमाम आशंकाओं के बावजूद मोटे तौर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका वैसा विरोध नहीं किया था और वैसा भितरघात भी नहीं हुआ था जैसा सब सोच रहे थे। तब उस जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं की पार्टी के प्रति निष्ठा और पार्टी को ही सर्वोपरि मानने की भावना को दिया गया था। हालांकि उस समय भी भाजपा ने अनुशासन पर कोई समझौता नहीं किया था। उस समय भी पार्टी ने कई दिग्गज नेताओं के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की थी। दिग्गज नेता, पूर्व मंत्री और प्रतिपक्ष के नेता रह चुके डॉ. गौरीशंकर शेजवार और उनके बेटे मुदित शेजवार को पार्टी विरोधी गतिविधियों पर नोटिस जारी किया गया था, जबकि उनके विधानसभा क्षेत्र सांची से तो भाजपा जीत गई थी। इसी तरह मुरैना जिले में पूर्व विधायक गजराज सिंह सिकरवार और उनके बेटे एवं पूर्व विधायक को भी ऐसे ही नोटिस दिए गए थे।

तौर पर पेश किए गए हैं। अब तो ये भी लगता है कि मोदी-शाह के नए एक्शन प्लान से भाजपा विरोधी राजनीतिक दलों में नए सिरे से भारी तोड़-फोड़ की आशंका तेज रफ्तार पकड़ने वाली है।

दरअसल, मप्र में जब सिंधिया 22 समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए थे, तब से ही पार्टी की रणनीति बदल गई है। वह दूसरी पार्टी से आने वालों को महत्व देने लगी है। पूर्व में 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव और उसके बाद दमोह उपचुनाव में बाहरी का विरोध देखने को मिला। लेकिन विरोध करने वालों के खिलाफ भाजपा ने कदम उठाने में भी देर नहीं की। राहुल लोधी 2018 के चुनाव में दमोह से कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए थे और उन्होंने भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री जयंत मलैया को हराया था। लेकिन कांग्रेस से भाजपा में आने की भगदड़ और पार्टी बदलने पर भारी पुरस्कार मिलने की संभावना को देखते हुए लोधी ने अचानक विधायकी से इस्तीफा दे दिया। जाहिर तौर पर कारण यह बताया कि भाजपा ही उनके विधानसभा क्षेत्र का विकास कर सकती है। और पहले से ही लिखी जा चुकी स्क्रिप्ट के तहत लोधी को न सिर्फ मप्र वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाया गया बल्कि उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दे दिया गया। बाद में लोधी के ही इस्तीफे से खाली हुई दमोह सीट पर पूर्व कांग्रेसी लोधी को भाजपाई लोधी के रूप में उपचुनाव में उम्मीदवार बनाकर उतारा गया।

लोधी यह उपचुनाव कांग्रेस के अजय टंडन से हार गए और यह हार भी कोई छोटी-मोटी नहीं सत्रह हजार से अधिक वोटों से हुई। हार के बाद लोधी ने अपनी शिकस्त का ठीकरा उन्हीं जयंत मलैया के सिर फोड़ा जिन्हें हजार से भी कम वोटों से हराकर वे 2018 में विधानसभा पहुंचे थे। उन्होंने मलैया पर भितरघात का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर डाली। पार्टी ने भी न सिर्फ लोधी की सुनी बल्कि आनन-फानन में मलैया को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए दमोह में मलैया के पुत्र सिद्धार्थ मलैया सहित 5 मंडल अध्यक्षों को पार्टी से निलंबित कर दिया।

जाहिर है यह बात दमोह में भाजपा का पर्याय बन चुके दिग्गज नेता जयंत मलैया को खलनी ही थी। पार्टी में अपनी खास पहचान और पकड़ रखने वाले मलैया 2018 का चुनाव राहुल लोधी से मात्र 798 वोटों से हारे थे। दमोह सीट पर मलैया की पकड़ और रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे इस सीट पर 1984 से 2013 तक, सिर्फ 1985 का चुनाव छोड़, बाकी सारे (सात) चुनाव जीते। 1990 के बाद से 2013 तक तो वे लगातार छह बार यहां के विधायक रहे। पार्टी की ओर से की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के बाद मलैया सवाल उठा रहे हैं कि हार के लिए सिर्फ वे ही जिम्मेदार कैसे हैं जबकि विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार की कमान खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने संभाल रखी थी। उन्होंने यह भी सवाल किया है कि राहुल लोधी जब खुद अपने ही वार्ड में हारे, वे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के वार्ड में भी हारे, तो फिर अकेले में ही हार के लिए कैसे जिम्मेदार हुआ? यहां यह जानना भी जरूरी है कि राहुल लोधी और उनसे पहले उनके रिश्तेदार प्रद्युम्न लोधी को कांग्रेस से भाजपा में लाने के पीछे पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और वर्तमान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का हाथ माना जाता है। इस हिसाब से यह मामला लोधी समुदाय की जातिगत राजनीति से भी जुड़ा है। उधर दमोह की राजनीति में मलैया और प्रहलाद पटेल के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की बात भी किसी से छिपी नहीं है। नई परिस्थिति में पार्टी के लिए दिक्कत यह हो गई है कि बाहर से आने वालों के लिए अपनों को धकियाने के चलन के खिलाफ अब नेता मुंह खोलने लगे हैं। दमोह मामले में भी यही हुआ। पूर्व मंत्री और जबलपुर से विधायक अजय विश्नोई ने भी यह सवाल पूछते हुए ट्वीट किया कि क्या टिकट बांटने वाले और चुनाव प्रभारी भी जिम्मेदारी लेंगे? दमोह मामले में पार्टी के ही कई नेता इस राय के हैं कि सिंधिया प्रकरण के समय तो कांग्रेसी विधायकों को सिर पर बैठाना, सरकार बनाने के लिए पार्टी की मजबूरी थी, लेकिन दमोह में तो ऐसा कुछ नहीं था। राहुल लोधी के भाजपा में आने या न आने से सरकार की सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था फिर यह फैसला क्यों किया गया? जहां तक दमोह का सवाल है वहां का उपचुनाव शुरू से ही भाजपा के पक्ष में दिखाई नहीं दे रहा था। अंदरूनी खबरें कह रही थीं कि इस बार भाजपा के लिए वहां मुश्किल होगी। ऐन वक्त पर कोरोना की लहर तो एक कारण थी ही लेकिन अंदर ही अंदर इस तरह के दलबदल के प्रति मतदाताओं के मन में उपजी नाराजगी भी थी। जातिगत समीकरण ने भी वहां बड़ा काम किया और स्थानीय लोगों के अनुसार यह चुनाव लोधी बनाम अन्य समुदाय हो गया था। दमोह में जैन समुदाय बड़ी संख्या में है, जयंत मलैया इसी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, मलैया की नाराजी का असर इस समाज के वोटों पर भी हुआ। कुल मिलाकर अभी भले ही भाजपा ने दल के प्रति निष्ठा और अनुशासन को सर्वोपरि मानते हुए मलैया और उनके समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई की हो, लेकिन आने वाले दिनों में यह मुद्दा पार्टी के भीतर मंथन का सबब जरूर बनेगा। इस सवाल को नेतृत्व ज्यादा दिन तक टाल नहीं पाएगा कि बाहर से आने वाले लोगों की कीमत पार्टी में बरसों बरस काम करने वाले लोगों को कितनी और कब तक चुकानी पड़ेगी।

● **कुमार राजेन्द्र**

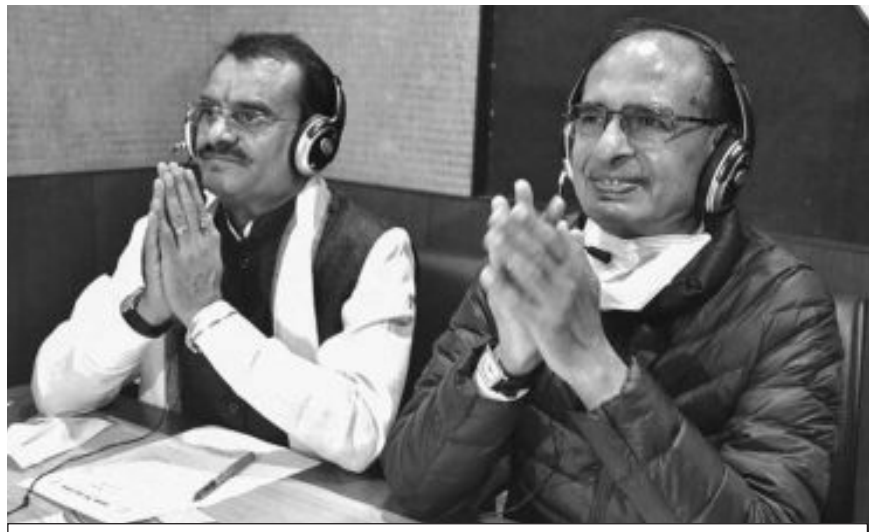

बाहरी बनाम भीतरी का टकराव बड़ी चुनौती

दरअसल पार्टी में बाहरी बनाम भीतरी का टकराव अब भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। भाजपा की असली ताकत उसका संगठन और कार्यकर्ताओं का अनुशासन है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मजबूरी यह है कि उन्हें सभी को साधना भी है और पार्टी के सांगठनिक और अनुशासन वाले चरित्र की रक्षा भी करनी है। भाजपा में कार्यकर्ता नहीं संगठन सर्वोपरि होता है और अब तक होता भी यही आया है कि संगठन ने जो फैसला कर लिया, कार्यकर्ताओं या नेताओं की भले ही उससे कोई राजी नाराजगी रही भी हो तो भी वे पार्टी को समग्रता में नुकसान पहुंचाने की हद तक नहीं जाते।

संकट में राहत की बारिश

कोरोना की महाविकट, महाघातक बीमारी से जंग के दौर में बेसहारा लोगों का सहारा बनने और अनाथ बच्चों का नाथ बनने की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की पहल राहत का बड़ा डोज साबित होगी, बशर्ते उनकी घोषणाओं पर अमल हो जाए। हर बेसहारा को 5-5 हजार की पेंशन, राशन, अनाथ बच्चों को पढ़ाई से लेकर सारी सुविधाओं की जिम्मेदारी लेने वाला मप्र देश का पहला राज्य बन गया है। प्रवासी बेरोजगार मजदूर हों या वकील अथवा पत्रकार सबके इलाज, मदद, अन्न, रोजगार के लिए ब्याजमुक्त कर्ज राज्य सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदम मुसीबत की इस घड़ी में बेहद मददगार साबित होंगे। शिवराज सरकार के घोर आलोचक पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी बेसहारा, बच्चों के लिए इस पहल की सराहना की है।

कोरोना महामारी के इस पूरे दौर में वो तमाम जनप्रतिनिधि गायब हैं या केवल मदद के नाम पर मुंह दिखाई कर रहे हैं, जिन्हें जनता ने वोट देकर नगर निगम, पालिका, विधानसभा या संसद तक पहुंचाया था। मंत्री विजय शाह एक निजी अस्पताल के आईसीयू का फीता काटकर उद्घाटन करते नजर आते हैं। तो पर्यटन, संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर यज्ञ चिकित्सा और हनुमान चालीसा का जाप कर कोरोना को हराने जैसी बातें करती हैं और कहती हैं कि यज्ञ में आहुतियां डालने पर कोरोना की तीसरी लहर छू भी नहीं पाएगी। पश्चिम बंगाल के चुनाव में प्रचार करने वाले गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा मप्र में कोरोना संक्रमण फैलने के लिए महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे कांग्रेस शासित राज्यों को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो सारे नियम कायदे ताक पर रख मंत्री तुलसीराम सिलावट भीड़ भरी प्रेस कांफ्रेंस करते दिखते हैं। अपने ऐसे मंत्रियों की फौज के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मोर्चा संभाले हुए हैं। उन्होंने कोरोना से लड़ने और परेशान जनता को राहत देने के लिए हाल ही में कुछ फैसले किए।

बेसहारा परिवारों के लिए: कोरोना ने जिन परिवारों को बेसहारा किया है और पालन-पोषण करने वाला छीना है, सरकार ने उन सभी परिवारों को 5 हजार रुपए मासिक पेंशन और राशन देने का ऐलान किया है।

अनाथ बच्चों के लिए: महामारी में अपने पालकों को खो चुके बेसहारा बच्चों को मुफ्त शिक्षा, अन्य सुविधाओं के साथ उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी लेने का ऐलान शिवराज सरकार ने किया है। बेसहारा बच्चों की जानकारी देने के लिए टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं, ताकि ऐसे बच्चों को माता-पिता की छोड़ी गई चल-अचल संपत्ति मिल सके। बाल आयोग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। बता दें कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर सहित राज्य के अनेक स्थानों पर कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां माता-पिता दोनों की मौत हो गई और बच्चे बेसहारा हो गए। यह योजना गत दिनों लागू कर दी गई है और इसे लागू करने वाला मप्र देश का पहला राज्य बन गया है। बता दें कि अनाथ बच्चों के भविष्य को लेकर लंबे अरसे से बात भी हो रही थी।

गरीबों के लिए: 5-5 महीने का राशन देने का ऐलान किया गया है, राशन कार्ड, आधारकार्ड की अनिवार्यता नहीं होगी। पात्रता नहीं होने पर भी राशन मिलेगा।

ब्लैक फंगस के शिकार मरीजों के लिए: ब्लैक फंगस याने म्यूकरमाइकोसिस से पीड़ित मरीजों का इलाज भी सरकार मुफ्त कराएगी।

वकीलों के लिए: वकीलों को कोरोना के इलाज के लिए 5 करोड़ की चिकित्सा सहायता मंजूर की गई है। संक्रमित वकीलों के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। दिवंगत वकीलों के परिवारों को 1-1 लाख की सहायता का निर्णय लिया गया है। बता दें कि अब तक 40 वकीलों की कोरोना से मौत हो चुकी है।

मीडिया के लिए: शिवराज सरकार ने मीडिया के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल के सभी सदस्य अधिमान्य और गैर अधिमान्य पत्रकारों, कैमरामैन, फोटोग्राफर्स का इलाज अपने खर्च पर कराने का ऐलान किया है। उनके परिवारों के इलाज का भी सरकार ध्यान रखेगी।

यह तमाम फैसले हैं जो हर वर्ग को बड़ी राहत दे सकते हैं, इन फैसलों पर अमल हो जाए तो मुसीबत के दौर में परिवारों का संबल बन सकते है। शिवराज सरकार के घोर आलोचक पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने भी महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों को मुफ्त शिक्षा और 5 रुपए की राशि प्रतिमाह देने के फैसले को सराहा और स्वागतयोग्य कदम बताया है।

● **जितेंद्र तिवारी**

सरकारी दावों में कोरोना काबू की ओर

राज्य सरकार के दावों पर भरोसा किया जाए, तो मप्र में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से घट रहे हैं। पॉजीटिविटी दर 12-13 फीसदी तक आ पहुंची है, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ इशारा किया है कि 17 मई तक जिन शहरों में पॉजीटिविटी रेट 5 फीसदी तक हो जाएगी, वहां कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। इन हालातों में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रतलाम, धार, उज्जैन, रीवा, दमोह, शहडोल, दतिया और शिवपुरी जैसे शहरों में कर्फ्यू खुलने की संभावनाएं बेहद कम हैं। बता दें कि देश में 3.62 लाख संक्रमण के नए मामलों के मुकाबले मप्र में करीब 9 हजार नए संक्रमित मिले हैं। शहरों में कोरोना संक्रमित अब कम मिल रहे हैं, जबकि गांव में इनकी संख्या बढ़ी है। जबकि इसके उलट सरकार के बुलेटिन और सरकार के पोर्टल दोनों में मौतों के आंकड़ों में 10 गुना से भी ज्यादा का अंतर है। सरकारी बुलेटिन कहता है कि पिछले 13 दिन में 81 मौतें हुई हैं, वहीं सरकार का ही सार्थक पोर्टल 883 मौतों की पुष्टि करता है। बुलेटिन और पोर्टल का यह अंतर इशारा करता है कि संक्रमितों, मौतों की सही जानकारी जनता के सामने नहीं आने दी जा रही है।

कोरोना की पहली लहर में सबसे अधिक प्रभाव उद्योग धंधों पर पड़ा था। दूसरी लहर में भी सबसे अधिक यही प्रभावित है। इस कारण मप्र में लाखों लोग बेरोजगारी की कगार पर पहुंच गए हैं। फिलहाल उद्योग धंधों की हालत वेंटिलेटर पर पड़े मरीज जैसी है।

वेंटिलेटर पर उद्योग जगत

कोरोना वायरस संक्रमण ने उद्योगों की भी कमर तोड़ दी है। उद्योगों से होने वाले उत्पादन में महज 45 दिनों में ही 45 फीसदी तक की कमी आ गई है। आने वाले दिनों में इसका अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। हालांकि काफी हद तक प्रदेश सरकार ने उद्योगों के संचालन को छूट दे रखी है। कोरोना कर्फ्यू में अन्य क्षेत्रों में बंदिशों का असर उद्योगों पर दिखाई दे रहा है। इंदौर, पीथमपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में कच्चे माल की कमी और उद्योग चलाने के दौरान मेंटेनेंस से जुड़े उपकरणों के नहीं मिलने के साथ ही संक्रमण के चलते भी दिक्कत आ रही है। मजदूरों की कमी भी उत्पादन कम होने की मुख्य वजह बताई जा रही है। ये भी वजह बताई जा रही है कि अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की भारी कमी के चलते पिछले कई दिनों से उद्योगों में ऑक्सीजन सप्लाय रोक दिया गया था। लोगों की जिंदगी बचाने के लिए यह बेहद जरूरी फैसला था। इसकी वजह से भी कुछ सेक्टर प्रभावित हुए थे।

उद्योगपतियों का कहना है यही हालात रहे तो जून के पहले सप्ताह तक उत्पादन घटकर 50 फीसदी ही रह जाएगा। उनका कहना है कि अब कोरोना के इंदौर में तेजी से फैलने से मजदूरों और कर्मचारियों में भय जरूर है। मजदूरों का कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में आंशिक पलायन हो रहा है। इंदौर और पीथमपुर में दवाएं बनाने वाली कई बड़ी और छोटी कंपनियां हैं। 10 से अधिक कंपनियां इंजेक्शन का भी उत्पादन करती हैं। कच्चा माल और ऑक्सीजन सप्लाय नहीं होने से इनका उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। दवा बनाने का कई माल विदेशों से भी आता है, कोरोना के चलते आयात प्रभावित है।

उद्योगपतियों का कहना है इंदौर और पीथमपुर के कई उद्योगों में कच्चे माल की सप्लाय महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली सहित अन्य राज्यों से होती है। अधिकांश प्रदेशों में कोरोना संक्रमण के चलते यातायात बंद है। इसके कारण कच्चा माल नहीं आ रहा है। जिससे उत्पादन प्रभावित है। प्लास्टिक इंडस्ट्री काफी हद तक महाराष्ट्र और गुजरात के कच्चे माल पर निर्भर है। औद्योगिक क्षेत्रों की फैक्ट्रियों को चलाने की अनुमति जरूर दी गई है, लेकिन उद्योगों की मशीनों के मेंटेनेंस से जुड़े उपकरणों और पुर्जों की दुकानें बंद हैं। यह नहीं मिलने से कई बार मशीनें बंद हो जाती हैं और उद्योगपति को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधिकांश फैक्ट्रियों से नियमित रूप से इन कलपुर्जों की जरूरत होती है। बाजार बंद होने से परेशानी आ रही है और उत्पादन गिरा हुआ है। सवा सौ से ज्यादा उद्योग तो बिक्री नहीं होने से घटे उत्पादन से बंद होने की कगार पर पहुंच गए है।

महीनेभर में 450 करोड़ का व्यापार हुआ ठप

2020 में इंदौर और पीथमपुर से चीन का रोजाना औसतन 15 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार है। इस हिसाब से अंदाजा लगाया जाए तो महीनेभर में सिर्फ इन दो शहरों का ही 450 करोड़ से अधिक व्यापार ठप हुआ था। दवाइयां बनाने के लिए दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला पैरासिटामॉल जो 1 सप्ताह पहले तक 250 रुपए किलो में मिल रहा था, उसकी कीमत 450 रुपए किलो तक पहुंच गई थी। सिर्फ पैरासिटामॉल की कीमतों में एक सप्ताह में दोगुने से ज्यादा की वृद्धि हो गई थी। वहीं डायक्लोफीनिक का रेट 700-800 रुपए किलो से 1500 रुपए किलो तक पहुंच गया था। इसी तरह दूसरी दवाओं में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कीमतों में भी 20 से लेकर 40 फीसदी तक इजाफा हो गया था।

प्रदेश का लोहा उद्योग वेंटिलेटर पर आ गया है। कच्चे माल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि, कोरोना में गिरी मांग और उद्योगों को ऑक्सीजन नहीं मिलने से ये हालात बने हैं। मप्र के विभिन्न शहरों में लोहे के उत्पाद बनाने वाली 50 रोलिंग मिल में से 40 अगले 15 से 20 दिनों के लिए बंद हो जाएंगी। मेटल कारोबारी योगेश मेहता बताते हैं कि कच्चे माल की कीमतों में एक महीने में 20-25 फीसदी का इजाफा हुआ है। आपूर्ति नहीं होना भी मिल बंद होने की मुख्य वजह है। एक साल में लोहा उद्योग के कच्चे माल (शीट) की कीमतों की बात करें तो 60 फीसदी तक का इजाफा हुआ है। पिछले साल 30 रुपए किलो मिलने वाला कच्चा माल 50 रुपए किलो है। मप्र रोलिंग मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश मित्तल का कहना है बाजार बंद हैं। जिससे डिमांड खत्म है। माल बिक नहीं रहा है तो महंगा कच्चा माल खरीदकर कौन स्टॉक बढ़ाएगा। एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष दर्शन मेहता बताते हैं, रोलिंग मिल में क्षमता अनुसार 30 से 50 हजार रुपए प्रतिदिन की बिजली खर्च होती है। इंदौर की 30 में से 25 मिल 15 से 20 दिनों के लिए बंद रहेंगी। मिलें बंद रहने के दौरान भी बिजली का न्यूनतम बिल संचालकों को भरना होगा, जो लाखों में होगा। आर्थिक संकट में बिजली बिल और परेशानी बढाएंगे। चीन से फैले कोरोना वायरस की दहशत जहां दुनियाभर में देखी जा रही है। देश के फॉर्मा उद्योग में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल का 70 फीसदी हिस्सा चीन से आता था। वायरस के असर के चलते कच्चे माल की पूर्ति नहीं हो रही थी। जिससे प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर और पीथमपुर का फॉर्मा उद्योग प्रभावित होने लगा था। मांग की तुलना में सप्लाय बेहद कम होने के कारण कच्चे माल की कीमतों में 30 से 40 फीसदी तक का इजाफा हो गया था। जिससे अब दवा की कीमतें बढ़ने के आसार बन गए थे। एक साल में चीन से कई दवाओं पर आयात निर्यात पर प्रतिबंध लग गया है।

● **राकेश ग्रोवर**

मुनाफाखोरी ने बढ़ाई समस्या

ऑक्सीजन संकट के दौर में वैश्विक सहयोग

वैक्सीन मैत्री का प्रतिफल ऑक्सीजन संकट के दौर में वैश्विक सहयोग के रूप में भी देखने को मिल रहा है। अब तक दर्जन भर से अधिक देशों से ऑक्सीजन की आपातकालीन आपूर्ति की जा चुकी है। चूंकि देश में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति में एक बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र से आता है, इसलिए यदि सरकार निजी क्षेत्र की गैस कंपनियों की क्षमता का पूरा लाभ लेना चाहती है तो उन्हें आर्थिक पैकेज या सहयोग प्रदान कर प्रोत्साहित किया जा सकता है। स्पष्ट है कि ऑक्सीजन के तात्कालिक संकट की अहम वजह देश में संसाधनों की कमी से कहीं अधिक विपत्ति के समय भी मुनाफे की तिकड़म और कुछ राज्यों की प्रशासनिक अकर्मण्यता है। ये कभी तीन-चार सौ रुपए के पीपीई किट के नाम पर मरीजों से हजारों रुपए वसूलते हैं तो कभी चंद दूरी के लिए एंबुलेंस सेवा के नाम पर लाखों का बिल थमा देते हैं। कोरोना की जंग के साथ मानवता के मूल्यों को कमजोर करने वाले ऐसे विघटनकारी तत्वों से समाज की जागरूकता और सार्वजनिक नियामकों की सख्ती से ही बचा जा सकता है।

ऑक्सीजन मनुष्य के लिए प्राणवायु है। वातावरण में मौजूद जिस ऑक्सीजन के जरिए हमारी सांसों की डोर चलती है, उसके लिए हमें न तो पैसे खर्च करने पड़ते हैं और न ही कतार लगानी पड़ती है। शायद इसीलिए ऑक्सीजन के प्रति हमने संवेदनशील होना तो दूर, अपनी गतिविधियों से उसकी गुणवत्ता को नष्ट किया। ऑक्सीजन के चिकित्सकीय रूप ने तो कोरोना की दूसरी लहर की वजह से ही लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। आज यह एक ऐसा उत्पाद बन गया है जिसे हासिल करने के लिए मरीज और अस्पताल जद्दोजहद कर रहे हैं। कई मामलों में तो न्यायालयों को भी दखल देना पड़ रहा है। हालांकि ऑक्सीजन से जुड़ी यह विपदा संसाधनों के अभाव से कहीं अधिक उसके अनुचित संग्रहण और उसके उपयोग के प्रति जागरूकता के अभाव से उत्पन्न हुई है। औद्योगिक गतिविधियों और चिकित्सकीय उपचार में प्रयुक्त होने वाली ऑक्सीजन सामान्यत: एक ही संयंत्र में तैयार की जाती है। एक ही प्रकार के टैंक और सिलेंडर के जरिए इसे संग्रहित किया जाता है।

देश में तकरीबन एक लाख टन ऑक्सीजन का प्रतिदिन उत्पादन होता है। इसमें औद्योगिक और चिकित्सा ऑक्सीजन, दोनों शामिल हैं। देश में इस्पात उद्योग औद्योगिक उपयोग के लिए ऑक्सीजन तैयार करता है। इस क्षेत्र के उपक्रम जरूरत पड़ने पर मेडिकल ऑक्सीजन का भी उत्पादन करते हैं। वहीं निजी क्षेत्र की कुछ कंपनियां मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन में सक्रिय हैं। औद्योगिक गतिविधियों में प्रयुक्त होने वाली ऑक्सीजन की खपत चिकित्सा ऑक्सीजन के मुकाबले काफी अधिक होती है, इसलिए इसका परिवहन मुख्य रूप से पाइपलाइन के जरिए ही होता है। अपने देश में ऑक्सीजन उत्पादन कुछ निश्चित भौगोलिक क्षेत्रों में केंद्रित है। इनमें कुछ बड़े केंद्र पूर्वी भारत के ओडिशा, झारखंड के अलावा मध्य भारत के छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। दक्षिण के कुछ राज्यों के साथ ही महाराष्ट्र की भी ऑक्सीजन उत्पादन में अच्छी हिस्सेदारी है। इन राज्यों में स्थित संयंत्र औद्योगिक ऑक्सीजन का 5 से 10 प्रतिशत ही लिक्विड रूप में तैयार करते हैं।

अगस्त 2020 में जहां लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमओ) का उत्पादन 5,700 मीट्रिक टन होता था, वहीं आज यह 8,922 मीट्रिक टन उत्पादित की जा रही है। इनमें लगभग 4,500 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन स्टील और पेट्रोलियम क्षेत्र की कंपनियों द्वारा तैयार की जा रही है। वहीं गंभीर स्थिति में मरीजों को दी जाने वाली मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति विशेष प्रकार के क्रायोजेनिक टैंकर्स और सिलेंडरों के जरिए ही होती है। ऐसे में देखा जाए तो हमारे यहां मेडिकल ऑक्सीजन की किल्लत उत्पादन के मोर्चे से कहीं अधिक उसके वितरण तंत्र से जुड़ी है।

मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए उपयोग में लाए जाने वाले क्रायोजेनिक स्टोरेज टैंक और सिलेंडर की कमी ने समस्या को और बढ़ाया है। क्रायोजेनिक टैंक में उन्हीं गैसों को संग्रहित किया जाता है जिन्हें बहुत ठंडा रखने की आवश्यकता होती है। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को माइनस-185 से लेकर माइनस-93 के तापमान में रखा जाता है। इस टैंक के जरिए 20 टन तक ऑक्सीजन का परिवहन संभव है। क्रायोजेनिक टैंक में दो मजबूत परत होती हैं। दोनों परतों के बीच निर्वात होता है, जिससे बाहर की गरमी का असर भीतर संग्रहित गैस पर बिल्कुल नहीं होता। भारत में सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों के पास इस समय लगभग 1500 क्रायोजेनिक टैंक हैं। विभिन्न वजहों से 200 टैंक संचालन की स्थिति में नहीं हैं।

हालांकि केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन संकट के सामने आते ही कुछ प्रभावी कदम उठाए हैं। इनका असर दिखने भी लगा है। रेल मंत्रालय, केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय तथा राज्यों के परिवहन विभागों का एक उप समूह लगातार ऑक्सीजन के सुगम परिवहन की निगरानी कर रहा है। वहीं पीएम केयर्स फंड के सहयोग से 162 पीएसए संयंत्र लगाने की योजना संचालन स्तर पर आ चुकी है। ये सभी संयंत्र देश के विभिन्न अस्पतालों में लग रहे हैं। पीएसए संयंत्र सीधे हवा से मेडिकल ऑक्सीजन तैयार करने की तकनीक पर काम करते हैं। सरकार ने ऑक्सीजन संकट के शुरुआती दिनों में ही इस्पात संयंत्रों के पास उपलब्ध सरप्लस स्टॉक के उपयोग की अनुमति दे दी थी। सरकार ऑक्सीजन स्रोतों के लिए राज्यों की मैपिंग भी कर रही है। इस प्रक्रिया से ऑक्सीजन की उपलब्धता वाले स्रोत से निकटवर्ती मांग वाले राज्यों को सुगम आपूर्ति का तंत्र विकसित किया जा रहा है। इसी क्रम में औद्योगिक सिलेंडरों को भी मेडिकल ऑक्सीजन के परिवहन के लिए उपयोग में लाए जाने की अनुमति दी गई है।

● **विकास दुबे**

पीले सोने में रिकार्ड उछाल

मप्र में तीन दशक पहले सोयाबीन यानी पीला सोना के उत्पादन से लगातार किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन इस बार सोयाबीन के रिकॉर्ड भाव के चलते किसानों को बीज की चिंता सता रही है। दरअसल 6 महीने से मंडियों में सोयाबीन के भाव ढाई गुना चल रहे हैं और बीज का भाव 9000 रुपए प्रति क्विंटल बताया जा रहा है। सवा महीने में मानसून की दस्तक मालवा-निमाड़ में आने की संभावना से पहले किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं। दरअसल किसानों को मानसून के पहले खेत जुताई कर बारिश की फसल बोने की तैयारी करना होती है और वह कर भी रहे हैं, लेकिन इस बार बड़े ही अनमने मन से किसान अपने खेत जोत रहे हैं। इसके पीछे कारण यह है कि मालवा-निमाड़ में सबसे ज्यादा रकबा सोयाबीन की बुवाई का होता है और इस बार बीज की सोयाबीन के दाम सर्वाधिक 9000 के करीब बताए जा रहे हैं।

दरअसल गत वर्ष आखिरी समय में बारिश के कारण सोयाबीन की फसल दागी हो गई थी, इसलिए अच्छे बीज किसानों के पास बेहद कम या नहीं के बराबर हैं। जिन 5 से 10 फीसदी किसानों के पास सोयाबीन के बीज हैं वह अभी सोयाबीन बेचना ही नहीं चाहते। अक्टूबर-नवंबर 2020 में जब सोयाबीन की फसल मार्केट में आई थी, तब सोयाबीन 2900 से 3200 रुपए प्रति क्विंटल में किसानों ने बेची थी। पिछले 6 महीने में सोयाबीन में रिकॉर्ड तेजी आई है, जो अब तक के सबसे ज्यादा दाम हैं। वर्तमान में मंडी में सोयाबीन 7200 रुपए प्रति क्विंटल के करीब बोली जा रही है।

प्रदेश में दो साल से सोयाबीन की फसल खराब होने से इस साल बीज के लिए भारी किल्लत रहने के आसार हैं। प्रदेश में करीब 56 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की फसल होती है और इसके लिए करीब 45 लाख क्विंटल बीज की जरूरत होगी। कृषि विभाग की निगरानी में मप्र बीज निगम, राष्ट्रीय बीज निगम, कृभको, नाफेड, बीज प्रमाणीकरण संस्था और बीज उत्पादक सहकारी संस्था के जरिए बीज उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन प्रतिकूल मौसम और बीमारियों के कारण इनका बीज उत्पादन कार्यक्रम भी खराब हुआ है। दूसरी तरफ निजी बीज उत्पादकों के बीज के सैंपल भी फेल हो रहे हैं। इस कारण पर्याप्त बीज मिलना मुश्किल है।

अधिकांश किसानों को खुले बाजार के बीज पर निर्भर रहना पड़ेगा, लेकिन वहां न केवल महंगा बल्कि अमानक बीज भी मिल सकता है। निजी बीज कारोबारी मुनाफाखोरी कर किसानों से मनमाने दाम वसूलने की तैयारी में हैं। दरअसल, इस समय सोयाबीन तेल में काफी तेजी है। इस तेजी का असर सोयाबीन के भाव पर भी है। पिछले साल खरीफ सीजन के बाद जो सोयाबीन 5300 से 5400 रुपए प्रति क्विंटल बिकी थी, वही अब लगभग 8 हजार रुपए क्विंटल बिक रही है। ऐसे में बीज की सोयाबीन तो इससे भी अधिक में मिलने का अनुमान है। दो साल से बेमौसम बारिश और सोयाबीन में फंगस के कारण सीड की क्वालिटी अच्छी नहीं रह पाई। ऐसे हालात में सरकार को चाहिए कि वह किसानों ने लिए रियायती दर पर बीज का इंतजाम करे। अब तक कृषि विभाग भी बीज का आंकलन नहीं कर पाया है। इंदौर जिले में बीज की उपलब्धता को लेकर उप संचालक कृषि एसएस राजपूत का कहना है कि इंदौर में विभिन्न शासकीय, सहकारी संस्थाओं और निजी संस्थाओं के माध्यम से 1.60 लाख क्विंटल सोयाबीन बीज उपलब्ध है। बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा इसकी टेस्टिंग की जा रही है। अब तक करीब 60 हजार क्विंटल की जांच रिपोर्ट आ चुकी है, बाकी के परिणाम आना बाकी हैं। इसके बाद ही स्पष्ट होगा कि कितना मानक बीज उपलब्ध हो पाएगा। यह सही है कि इस बार सोयाबीन बीज की कमी रहेगी, लेकिन इंदौर की जरूरत पूरी हो जाएगी। आसपास के जिलों में परेशानी आ सकती है। इंदौर जिले के जामली गांव के किसान संतोष पाटीदार का कहना है कि सोयाबीन खराब होने से हमने तो बड़नगर से परिचित किसानों से अच्छा बीज पहले ही ले लिया था, लेकिन कई किसानों को बीज का संकट आएगा।

प्रदेश में भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर व राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधान केंद्रों पर सोयाबीन का ब्रीडर सीड तैयार किया जाता है। बताया जाता है कि प्रतिकूल मौसम का असर इन अनुसंधान केंद्रों के ब्रीडर सीड उत्पादन पर भी पड़ा है। बताया जाता है कि यह अनुसंधान केंद्र मिलकर हर साल करीब 6 हजार क्विंटल ब्रीडर सीड उपलब्ध कराते थे, लेकिन इस साल 4 हजार क्विंटल ही हो पाएगा। ब्रीडर सीड से ही फाउंडेशन और फिर फाउंडेशन सीड से सर्टिफाइड सीड तैयार होता है जो किसानों को खेतों में उगाने के लिए उपलब्ध हो पाता है।

● **बृजेश साहू**

अपना बीज खुद तैयार करें किसान

सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर के वरिष्ठ वैज्ञानिक और बीज अनुसंधान के प्रभारी डॉ. मृणाल कुचलान का कहना है कि किसानों को अपनी जरूरत के हिसाब से अपना बीज कार्यक्रम और योजना खुद भी तैयार करना चाहिए। अपने खेत में 10 प्रतिशत रकबे में बीज उत्पादन के लिए उत्तम गुणवत्ता का बीज बोना चाहिए। साथ ही गाइडलाइन के हिसाब से उसकी विशेष देखरेख, कटाई, सफाई, भंडारण करना चाहिए। भंडारण करने से पहले इनकी अंकुरण क्षमता जांचने के लिए कुछ बीज बोकर देखना चाहिए। जिन बीजों का बेहतर अंकुरण हो, उन्हें ही बीज के लिए रखें। अगले साल खेत में बोने से पहले एक बार फिर इसकी अंकुरण क्षमता को जांचना चाहिए। वहीं सोया प्रदेश मप्र में कृषि वैज्ञानिकों ने सोयाबीन की नई प्रजाति विकसित की है। इस प्रजाति के बीज के इस्तेमाल से किसान मालामाल हो जाएंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार इस बीज से 1 हैक्टेयर में 7 क्विंटल से अधिक की पैदावार होगी।

भाजपा अपनों की भितरघात के कारण भले ही दमोह विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव को हार गई है, लेकिन वह निराश होने की बजाय अब दोगुने जोश के साथ खंडवा लोकसभा सीट के साथ ही जोबट, पृथ्वीपुर और रैगांव विधानसभा उपचुनाव की तैयारी में जुट गई है। दमोह विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मिली हार के बाद आलाकमान ने मप्र भाजपा संगठन को टारगेट दिया है कि एक सीट की हार के बदले में आगामी 4 उपचुनावों को जीतो।

हार को भुलाकर नई तैयारी में...

दमोह में भाजपा को जिसका डर था वही हुआ। यानी भितरघात के कारण भाजपा उपचुनाव हार गई। लेकिन इस हार से भाजपा हतोत्साहित नहीं है। बल्कि आगामी उपुचनावों के लिए अभी से रणनीति बनाने लगी है। पार्टी आलाकमान ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को दमोह की हार को भुलाकर खंडवा लोकसभा सीट के साथ ही जोबट, पृथ्वीपुर और रैगांव विधानसभा उपचुनाव की तैयारी में जुटने का निर्देश दिया है। अब दमोह की हार से सबक लेते हुए भाजपा आगामी चारों उपचुनाव में उतरेगी।

गौरतलब है कि दमोह उपचुनाव को जीतने के लिए भाजपा ने अपना पूरा दमखम लगा दिया था। लेकिन भाजपा की रणनीति और दमखम पर अपनों का भितरघात भारी पड़ा। हालांकि दमोह उपचुनाव में हार के बाद अब भाजपा ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पार्टी ने दमोह से 7 बार के विधायक व पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया को नोटिस जारी किया है, जबकि उनके पुत्र सिद्धार्थ मलैया समेत 5 मंडल अध्यक्षों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। उपचुनाव हारने के बाद भाजपा उम्मीदवार राहुल लोधी ने आरोप लगाया था कि जयंत मलैया ने भितरघात किया है। जिन 5 मंडल अध्यक्षों को पार्टी से निष्कासित किया गया है, उनमें अभाना मंडल अजय सिंह, दीनदयाल नगर मंडल संतोष रोहित, दमयंती मंडल मनीष तिवारी, बांदकपुर मंडल अभिलाष हजारी व बॉसा मंडल देवेंद्र सिंह राजपूत हैं। बता दें कि कांग्रेस के अजय टंडन ने भाजपा के राहुल लोधी को 17 हजार से ज्यादा वोटों से हराया है, जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित कई मंत्रियों ने इस उपचुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी।

प्रदेश में खंडवा लोकसभा, जोबट, पृथ्वीपुर और रैगांव विधानसभा सीटें खाली हैं। 2 मार्च को खंडवा सांसद नंदकुमार सिंह चौहान के निधन के बाद से संसदीय क्षेत्र की सीट खाली है। वहीं पृथ्वीपुर विधायक बृजेंद्र सिंह राठौर और जोबट विधायक कलावती भूरिया के निधन के बाद विधानसभा सचिवालय ने यह दोनों विधानसभा क्षेत्र रिक्त घोषित कर दिए हैं। सचिवालय ने चुनाव आयोग को जानकारी भेज दी है। खंडवा संसदीय क्षेत्र में रिक्त स्थान पर चुनाव कराने से चुनाव आयोग फिलहाल इंकार कर चुका है, ऐसे में विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव भी फिलहाल कोरोना संक्रमण कम होने तक टल सकते हैं। गौरतलब है कि अलीराजपुर जिले के जोबट विधानसभा क्षेत्र से विधायक रही कलावती भूरिया का 24 अप्रैल को निधन हो चुका है। वहीं निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित विधायक बृजेंद्र सिंह राठौर का 2 मई को निधन हो चुका है। जबकि हाल ही में रैगांव से भाजपा विधायक जुगलकिशोर बागरी का निधन हुआ। तीनों ही विधायकों को पहले कोरोना संक्रमण हो चुका था। इसके चलते उन्हें गंभीर स्थिति में अस्पतालों में भर्ती करना पड़ा था। विधानसभा सचिवालय ने जोबट, पृथ्वीपुर और रैगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायकों के निधन हो जाने के कारण इन विधानसभा क्षेत्रों को रिक्त घोषित कर दिया है। सचिवालय ने भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को इसकी जानकारी भेज दी है। अब भारत निर्वाचन आयोग

हार पर आत्मचिंतन और मंथन

भाजपा के बारे में ख्यात है कि वह कोई भी चुनाव युद्ध की तरह लड़ती है। यही नहीं पार्टी छोटी हार भी बर्दाश्त नहीं करती है। इसलिए दमोह उपचुनाव की हार पर पार्टी में आत्मचिंतन और मंथन का दौर जारी है। हालांकि इस जीत-हार से सरकार पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन भाजपा किसी भी हार को सामान्य नहीं मानती है। इसलिए दमोह उपचुनाव के नतीजे की समीक्षा कर रही भाजपा चिंतन की मुद्रा में है। सत्ता में मौजूदगी और मजबूत संगठन रहते हुए उसके तीन दशक पुराने किले में ढाई साल के दौरान दूसरी हार को शीर्ष नेतृत्व गंभीर संकेत मान रहा है। पार्टी ने कांग्रेस से आए राहुल लोधी को मौका दिया था, जो 2018 के विधानसभा चुनाव में बतौर कांग्रेस प्रत्याशी यहां भाजपा को मात दे चुके थे। लोधी की हार को दलबदल के खिलाफ जनमत माना जा रहा है तो खुद भाजपा में भितरघात का परिणाम, वहीं संगठन के लिहाज से कांग्रेस से मिलती नई चुनौती भी। चूंकि अब झाबुआ लोकसभा सीट सहित विधानसभा की कुछ सीटों पर उपचुनाव और स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं, तो भाजपा अब नए सिरे से जनता की नब्ज टटोलने और संगठन में असंतोष को भांपकर समय रहते विकल्प पर विचार की तरफ फोकस करेगी।

को निर्णय लेना है कि वर्तमान परिस्थितियों में इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव फिलहाल कराएं या नहीं कराएं।

उधर दमोह उपचुनाव में मिली हार के बाद से ही भाजपा ने इन चारों सीटों पर उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पदाधिकारियों को सक्रिय कर दिया है। वहीं संघ ने भी अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। भाजपा सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा के दिशा-निर्देश पर भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अभी से उपचुनाव वाले क्षेत्रों में सक्रिय होने लगे हैं। पार्टी का फोकस इस बात पर है कि इन सीटों पर उम्मीदवार कोई भी हो लेकिन जीत भाजपा की ही होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में ख्यात है कि वे उपचुनाव जीतने में माहिर हैं। ऐसा उन्होंने करके भी दिखाया है। जीत के जज्बे के साथ भाजपा संगठन के साथ ही सरकार भी खंडवा, जोबट, पृथ्वीपुर और रैगांव में रणनीति बनाकर काम करेगी। हालांकि अभी कोरोना संक्रमण के कारण गतिविधियां सीमित रहेंगी, लेकिन जैसे ही संक्रमण कंट्रोल होगा भाजपा अगली परीक्षा में उतर जाएगी। वैसे देखा जाए तो 15वीं विधानसभा के गठन के बाद से प्रदेश में जितने उपचुनाव हुए हैं, भाजपा का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद अब तक मप्र में 31 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो चुके हैं। कोरोना संकट से निपटने के बाद एक बार फिर उपचुनाव का बिगुल बजेगा। इस बार खंडवा लोकसभा क्षेत्र के साथ जोबट और पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव होंगे। इसमें कांग्रेस और भाजपा की चुनावी परीक्षा होगी। 15वीं विधानसभा का रिकॉर्ड देखें तो भाजपा का पलड़ा भारी रहा है। उपचुनाव में 20 सीटें भाजपा ने और 11 कांग्रेस ने जीती हैं।

मप्र में पंद्रहवीं विधानसभा के गठन के बाद से उपचुनाव होने का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो अभी भी जारी है। पिछले दिनों दमोह विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव का परिणाम घोषित हुआ, जो कांग्रेस के पक्ष में रहा। यह सीट कांग्रेस

के विधायक राहुल लोधी के विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने की वजह से रिक्त हुई थी। प्रदेश में कुल 31 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो चुके हैं। इनमें 28 सीटें विधायकों के इस्तीफा देने की वजह से खाली हुई थी। वहीं, तीन सीटें जौरा, आगर और ब्यावरा विधायकों का निधन होने से रिक्त हुई थीं। अब तीन सीटें जोबट, पृथ्वीपुर और रैगांव सीट भी विधायकों के निधन की वजह से खाली हो गई हैं। उधर, खंडवा लोकसभा सीट भी सांसद नंदकुमार सिंह चौहान के निधन की वजह से रिक्त हो गई है। यहां भी उपचुनाव कराए जाएंगे।

भाजपा भले ही दमोह विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव को हार गई है, लेकिन 15वीं विधानसभा में अब तक हुए 31 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में से पार्टी 20 उपचुनाव जीत चुकी है। वहीं कांग्रेस 11 सीटें जीती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन 31 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, उनमें से दो सीटें आगर और झाबुआ भाजपा के कब्जे वाली रही है। जबकि 29 सीटें कांग्रेस ने 2018 में जीती थीं। अब जिन 3 विधानसभा सीटों में उपचुनाव होना है, उसमें से 2 कांग्रेस और एक भाजपा विधायक के निधन के बाद खाली हुई है। वहीं खंडवा लोकसभा सीट भाजपा सांसद के निधन के बाद खाली हुई है।

भाजपा के लिए दमोह की हार महज एक सीट गंवाना नहीं है, बल्कि अपने मजबूत गढ़ में लगातार दूसरी मात है, जो सियासी जमीन कमजोर होने के संकेत करता है। यहां पार्टी का चेहरा रहे पूर्व वित्तमंत्री जयंत मलैया 1984 के उपचुनाव में यहां पहली बार जीत दर्ज कर सातवीं विधानसभा में पहुंचे थे। इसके बाद 1990, 93 और 98 में क्रमशः 9वीं, 10वीं और 11वीं विधानसभा में पहुंचे। 2003 में पांचवीं बार दमोह से निर्वाचित हुए और 2004 में उमा भारती की सरकार, फिर बाबूलाल और शिवराज सिंह चौहान की सरकारों में भी मंत्री बने। 2008 और 13 में भी दमोह से जीतकर सरकार में मंत्री बने, लेकिन 2018 में कांटेदार मुकाबले में कांग्रेस से राहुल लोधी ने महज 798 वोटों से मलैया को मात दे दी।

मलैया और फिर लोधी की हार से दमोह में भाजपा की जमीन खिसकने के संकेत मिल रहे हैं, वहीं दोनों बार कांग्रेस की जीत ने संगठन की चिंता बढ़ा दी है। दमोह में भाजपा की हार पर प्रत्याशी राहुल लोधी द्वारा कार्यवाही की मांग पर पूर्व मंत्री जयंत मलैया चुप नहीं रहे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पार्टी ने गलत उम्मीदवार का चयन किया। बड़े अंतर की हार को मलैया सामान्य हार नहीं मानते। उन्होंने कहा कि बड़ी हार किसी नेता के कारण नहीं हो सकती। यह सिर्फ वोटर ही दे सकता है।

● **अरविंद नारद**

गुटबाजी-भितरघात या कोई और वजह

आखिरकार भाजपा और शिवराज सरकार का पूरा कुनबा अपनी पूरी ताकत झोंक देने के बावजूद उपचुनाव में दमोह विधानसभा सीट बचा पाने में नाकामयाब रहा। यहां कांग्रेस को बड़ी जीत के साथ सियासत में जिंदा रहने की अपनी उम्मीदों की सौगात मिली। वहीं भाजपा को बड़ा झटका लगा, जो आने वाले नगरीय निकाय, पंचायत, चुनाव से लेकर भविष्य में होने वाले उपचुनाव में उसके लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। इसलिए भाजपा दमोह की हार को गंभीरता से ले रही है। पार्टी पड़ताल में जुट गई है कि आखिर दमोह में गुटबाजी और भितरघात की वजह क्या है। भाजपा सूत्रों का मानना है कि गुटबाजी और भितरघात के साथ ही जनता में संभवतः इस बात को लेकर नाराजगी थी कि जब वो महामारी से कराह रही थी, तब उसे सरकार की मदद और साथ की जरूरत थी, जो नहीं मिली। उसी वक्त मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री समेत दर्जनभर से ज्यादा मंत्री दमोह में रैलियां करवाते हुए अपनी और अपनी पार्टी, अपने प्रत्याशी की ब्रांडिंग कर रहे थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पूरे समय दमोह में डेरा डाले नेताओं, कार्यकर्ताओं की बैठकें, सभाएं ले रहे थे। जनता समझ रही थी कि सरकार को जनता से ज्यादा सत्ता और चुनाव की पड़ी है। इसी का सबक सिखाते हुए उसने ये नतीजे दिए। भाजपा व सरकार का पूरा कुनबा भी मिलकर एक प्रत्याशी को नहीं जिता पाया।

भाजपा बंगाल, केरल, तमिलनाडु जैसे सांस्कृतिक भाषाई और क्षेत्रीय पहचान वाले राज्यों में उदारवादी हिंदुत्व के जरिए ही पैठ बना सकती है। प्रारंभिक दौर में इसकी बुनियाद संघ जैसा सामाजिक संगठन ही रख सकता है। लोगों के मुद्दे समय के साथ बदलते भी हैं।

हावी माफिया राज

ग्वालियर में माफिया राज हावी है। लाख कोशिशों के बाद भी माफिया बाज नहीं आ रहे हैं। गत दिनों जंगल में पत्थर के अवैध उत्खनन को रोकने पहुंची वन विभाग की टीम पर माफिया ने हमला कर दिया। वन विभाग के अफसरों को जंगल में दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया। एक वनकर्मी की वर्दी फाड़ दी। टीम को घेरकर पथराव किया गया। पत्थर लगने से दो लोग घायल भी हुए हैं। घटना तिघरा के जंगल में महेशपुरा के पास हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायल वनकर्मियों को उपचार के लिए भेजने के बाद पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। तिघरा में नीलपुरा वन चौकी प्रभारी सत्यप्रकाश पुत्र बीएस गौड़ को अवैध उत्खनन की सूचना मिली थी। इस पर वह तिघरा के जंगल में सांकरे बाबा मंदिर के पास महेशपुरा इलाके में पहुंचे। उनके साथ में वनकर्मी नीलेश पचौरी, नंदन दुबे, सोबरन सिंह पटेल और रिंकू यादव भी थे।

यहां पर काफी मात्रा में माफिया पत्थर का अवैध उत्खनन कर रहे थे। यहां से पत्थर निकाल रहे माफिया की पहचान बलराम बघेल, गोटा सिंह, शिवचरण, राधे यादव और अरविंद यादव के रूप में हुई। वन विभाग के अमले ने माफिया को चारों तरफ से घेर लिया। साथ ही माफिया को सरेंडर करने के लिए कहा, इस पर माफिया ने वन टीम पर अचानक हमला बोल दिया। जंगल में छुपे एक दर्जन से अधिक युवक पत्थरों से लैस होकर पहुंचे और वन अमले पर पथराव शुरू कर दिया। खुद को घिरा पाकर वन अमले में भगदड़ मच गई। इसके बाद तो वनकर्मियों को जंगल में दौड़ा-दौड़ा कर पीटा।

हमलावरों ने पथराव के बाद भाग रहे वनकर्मी नीलेश पचौरी को घेर लिया और वर्दी फाड़ दी। नीलेश को जमीन पर पटककर लाठियों से पीटा। पथराव में वन पाल हरिवल्लभ चतुर्वेदी तथा एक अन्य के सिर में पत्थर लगा, जिससे वह घायल हो गए। माफिया के हमले से बचने वनकर्मियों ने जंगल में छुपकर जान बचाई, साथ ही पुलिस को सूचना दी। मामले का पता चलते ही तिघरा थाना प्रभारी अवधेश सिंह कुशवाह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तो पत्थर माफिया स्पॉट से भाग चुके थे। पुलिस ने घायल वनकर्मियों को उपचार के लिए भेजकर पुलिस ने आरोपियों बलराम बघेल, गोटा सिंह, शिवचरण, राधे यादव और अरविंद यादव के खिलाफ बलवा, मारपीट व शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज कर लिया है। गत दिनों चंबल रेत से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली को पकड़ने पहुंचे रामपुर थाने के सिपाही के साथ माफिया ने मारपीट कर दी। हमले की सूचना पाकर पुलिस जसलावनी पहुंची तो रेत कारोबारी सड़क पर रेत फैलाकर भाग खड़े हुए। माफिया व रेत वाहन को पकड़ने के लिए फोर्स ने 4 राउंड फायर किए लेकिन कारोबारी पकड़े नहीं जा सके। जानकारी के मुताबिक, रामपुर थाने के सिपाही शिवरतन ने जसलावनी गांव में चंबल रेत से भरे एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोका। रेत कारोबारियों ने सिपाही से रास्ते से हटने के लिए कहा, लेकिन सिपाही बजाय हटने के लिए मोबाइल फोन से थाना प्रभारी को मौके पर बुलाने लगा। रेत कारोबारियों को लगा कि सिपाही को रास्ते से नहीं हटाया तो वह उनके ट्रैक्टर-ट्रॉली को जरूर पकड़वा देगा। चूंकि वाहन में चंबल का रेत भरा है इसलिए ट्रैक्टर-ट्रॉली राजसात हो जाएंगे।

8 से 10 की चपत लगती देख ट्रैक्टर पर सवार लोगों ने सिपाही की मारपीट कर दी और मौके से रेत वाहन लेकर भाग गए। इधर सिपाही ने थाने को सूचना दे दी कि उसके साथ नगवानी के रेत कारोबारियों ने मारपीट की है इसलिए थाना प्रभारी फोर्स लेकर जसलावनी मोड़ पर पहुंच गए। पुलिस ने रेत वाहन को रोकने के लिए 2 फायर किए लेकिन वाहन को पकड़ा नहीं जा सका। उस हाल में फोर्स ने रेत वाहन का पीछा किया और दो फायर पासवान मोड़ पर किए। रात होने का लाभ उठाकर रेत माफिया अपने ट्रैक्टर-ट्रॉली को भगा ले जाने में सफल हो गया। पुलिस दोनों घटनास्थल से चलाए गए कारतूसों के खाली खोके भी बीन लाई ताकि फायरिंग का कोई सबूत सार्वजनिक नहीं हो। लेकिन जसलावनी के लोगों ने पुलिस द्वारा रेत वाहन पर गोली चलाने व सिपाही की मारपीट किए जाने की पुष्टि की है। यहां बता दें कि रामपुर क्षेत्र में चंबल के बटेश्वरा घाट से रेत लाया जा रहा है।

● **सुनील सिंह**

लगातार हो रहे हैं हमले

वन अमला या पुलिस पर यह माफिया का पहला हमला नहीं है। शिवराज में माफियाराज हावी है। माफिया लगातार पुलिस, जिला प्रशासन व वन अमले पर हमले करता रहा है। जिसमें से कुछ ताजा मामले सामने आए हैं। गौरतलब है कि 6 फरवरी को पुरानी छावनी जलालपुर अंडर रेलवेब्रिज पर रेत माफिया ने कार्रवाई के बौखलाकर गोलियां चलाईं। पुरानी छावनी टीआई सुधीर सिंह कुशवाह पर ट्रैक्टर चढ़ाकर कुचलने का प्रयास किया। इसमें वह घायल हुए थे। बीते 2 महीने में तिघरा के महेशपुरा के पास वन टीम पर यह तीसरा हमला है। हर बार माफिया हमला कर बच निकलते हैं। पनिहार के छोड़ा गांव के बीच पत्थर का अवैध उत्खनन कर रहे माफिया ने पिछले ही महीने वन विभाग पर हमला किया था। बाद में पुलिस ने पहुंचकर एक ट्रॉली पत्थर जब्त किया था।

खाद बिगाड़ेगी खेती का गणित

कोरोना महामारी के बीच किसानों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। कभी मंडी में बारदानों के कमी के कारण गेहूं की खरीदी में रुकावट, कभी भुगतान में देरी, तो कभी हम्मालों की कमी...। किसान आए दिन ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। अब सरकार के एक निर्णय ने उन्हें आर्थिक मार दी है। संकट में फंसे अन्नदाताओं को अब 1200 रुपए में मिलने वाली डीएपी खाद के 1900 रुपए चुकाने होंगे। जानकारों का कहना है कि महंगे होते रासायनिक खाद के दाम से अब किसानों की लागत में भारी बढ़ोतरी होना तय है। पेट्रोल-डीजल के बाद महंगी हुई खाद के सवाल पर किसानों का कहना है कि खेती अब घाटे का सौदा बन रही है।

किसान नेता बबलू जाधव ने खाद में की गई बढ़ोतरी पर सरकार व फर्टीलाइजर कंपनियों पर निशाना साधते हुए कहा कि लगातार रासायनिक उर्वरक खाद के भाव में बढ़ोतरी हो रही है। बात तो किसानों की आय दोगुनी करने की थी, इसके उलट आय दोगुनी तो नहीं हुई बल्कि किसानों की लागत में भारी बढ़ोतरी की जा रही है। दूसरी ओर किसानों की फसलों के उचित दाम तक नहीं मिल रहे हैं। वहीं, अब बढ़े हुए रासायनिक खाद की कीमतों से किसान काफी आक्रोशित हैं। बढ़े हुए दाम तत्काल वापस लेना चाहिए और किसानों को राहत देनी चाहिए।

किसानों का कहना है कि साल 2014 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करते थे। सत्ता में आने के बाद उनकी पार्टी कई बार किसानों की आय दोगुनी होने की बात करती रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ 5 महीने से ज्यादा समय से आंदोलनरत है। ऐसे में अब उर्वरकों की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया है। डीएपी 50 किलो वाले बैग की कीमत में 58 फीसदी की वृद्धि की गई है। 1200 रुपए में मिलने वाले डीएपी के लिए किसानों को अब 1900 रुपए चुकाने होंगे। देश में यूरिया के बाद किसान सबसे अधिक डीएपी और एनपीके 12, 32, 16 खाद का इस्तेमाल करते हैं, एनपीके खाद के भाव बढ़कर 1800 रुपए प्रति बैग हो गए हैं।

प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष व पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने खाद की बढ़ी कीमतों को वापस नहीं लिया, तो सीएम हाउस के सामने धरना दिया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर कहा कि कोरोना और पेट्रोल-डीजल के दामों से जूझ रहे किसान महंगाई की मार झेलने को मजबूर हैं। आपने खाद की कीमतों में आश्चर्यजनक रूप से बढ़ोतरी कर किसानों पर एक बोझ और डाल दिया है। डीएपी व एनपीके की कीमत 1200 से 1900 रुपए करने को न्यायोचित नहीं माना जा सकता। अगर सरकार इस निर्णय को वापस नहीं लेती, तो सीएम हाउस के सामने धरना दिया जाएगा और कांग्रेस चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी।

कांग्रेस का आरोप है कि एक तरफ किसान कोरोनाकाल में अपनी फसलों की लागत तक नहीं निकाल पा रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार उसे राहत देने की बजाय खेती किसानी संबंधित रासायनिक खाद की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि कर रही है। जिससे खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात सिर्फ कागज तक सिमटकर रह गई है। कोरोना संकट के बीच सरकार ने आगामी खरीफ और रबी सीजन के लिए खाद का इंतजाम करना शुरू कर दिया है। खरीफ और रबी सीजन के लिए सवा आठ लाख टन यूरिया की व्यवस्था की जाएगी। सोयाबीन, धान सहित अन्य फसलों के लिए चार लाख टन यूरिया की व्यवस्था बनाई जाएगी। इसके लिए सरकार ने राज्य सहकारी विपणन संघ मार्कफेड को नोडल एजेंसी बनाने का निर्णय लिया है। वर्ष 2023-24 तक प्रतिवर्ष खाद के इंतजाम के लिए मार्कफेड को 600 करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी भी मिलेगी। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि खाद के अग्रिम भंडारण की योजना पहले की तरह चलती रहेगी। इसके लिए सहकारी समितियों में जरूरत के हिसाब से खाद का भंडारण किया जाएगा। किसान अपनी सुविधा से इस खाद को पात्रता अनुसार ले जा सकेंगे ताकि सीजन पर खाद को लेकर मारामारी की स्थिति न बने। वर्ष 2021-22 की खरीफ फसलों के लिए बोवनी में लगने वाला डीएपी चार लाख टन लिया जाएगा।

● **लोकेंद्र शर्मा**

डीजल ने पहले ही तोड़ दी किसानों की कमर

उर्वरक की कीमतों में वृद्धि से किसानों की जेब पर भारी असर पड़ने की संभावना है, जो पहले से ही डीजल की बढ़ी कीमतों के चलते भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। नई कीमतों से आगामी खरीफ सीजन में इनपुट लागत दोगुनी हो सकती है। डीजल की कीमत फिलहाल 90 रुपए से ज्यादा है। ऐसे में किसानों पर आर्थिक भार पड़ा है। उसे खेत में बोवनी करने, खेत को तैयार करने और अपना माल ढुलाई करने के लिए ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है। ऐसे में डीजल के दामों में वृद्धि से कृषि की लागत पहले ही बढ़ चुकी है। अब डीएपी के दामों में वृद्धि से किसान पर आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। डीएपी के दाम बढ़ने पर कुछ किसान संगठनों ने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है। कोरोना के चलते पिछले वर्ष से खेती-किसानी की कमर टूटी हुई है। अब उस पर सरकार की ओर से बोझ बढ़ाया गया है। इससे खरीफ सीजन में बोवनी की तैयारी कर रहे किसानों को भारी झटका लगा है। दरअसल डीएपी व एनपीके खाद की कीमतों में एकाएक 58 फीसदी तक बढ़ोतरी की गई है। इससे खेती की लागत भी बढ़ गई है। दरअसल पिछले 1 सप्ताह में सरकार के द्वारा खेतों में उपज बढ़ाने के लिए डाली जाने वाली रासायनिक खाद डीएपी के दाम 700 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं। ऐसे में किसानों को अब 1200 रुपए में मिलने वाली डीएपी 1900 में खरीदनी पड़ेगी।

अर्थव्यवस्था को टीके की आस

महामारी की पहली लहर से बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था अभी पटरी पर लौटना शुरू भी नहीं हुई थी कि दूसरी लहर कहर बरपाने लगी। इस बार की लहर कहीं ज्यादा व्यापक और तीव्र है। दैनिक संक्रमण के मामले साढ़े तीन लाख के पार निकल गए हैं और मरने वालों का रोजाना का आंकड़ा भी तीन हजार के करीब पहुंच चुका है। ऐसे में संक्रमण से निपटने के लिए सरकारों को फिलहाल पूर्णबंदी जैसे ही कड़े प्रतिबंधों के अलावा कोई चारा नजर आ भी नहीं रहा। इसलिए ज्यादातर राज्यों ने फिर से कड़े प्रतिबंध और आंशिक पूर्णबंदी जैसे उपायों का सहारा लेना शुरू कर दिया है।

कहने को फिलहाल कारोबार और औद्योगिक गतिविधियों को इस सख्ती से अलग रखा गया है। लेकिन जब व्यापकस्तर पर लोगों की आवाजाही पर ही रोक लग जाएगी तो आर्थिकी इससे कैसे अछूती रह सकती है। भले इस बार आर्थिक गतिविधियां बनाए रखने की भरसक कोशिशों के दावे हो रहे हों, पर सख्त पाबंदियों के कारण अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्र खासतौर से अनौपचारिक क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। अर्थव्यवस्था पर क्या और कितना असर होना है, इसका अंदाजा लगाने के लिए हमारे पास अनुभव और आंकड़े उपलब्ध हैं। दो महीने से ज्यादा की पूर्णबंदी के कारण वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई थी। तब पहली तिमाही में विकास दर शून्य से 24.4 फीसदी और दूसरी तिमाही में शून्य से 7.50 फीसदी नीचे दर्ज की गई थी। धीरे-धीरे आर्थिक गतिविधियां बहाल होने के बाद तीसरी तिमाही में विकास दर शून्य से ऊपर (0.5 फीसदी) आई और चौथी तिमाही में इसके और ऊपर उठने का अनुमान है। इसके आंकड़े अभी आने हैं। महामारी की दूसरी लहर को काबू करने के लिए राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी तो लागू नहीं है, लेकिन अलग-अलग राज्यों में लागू सख्त पाबंदियों और संक्रमण के भय के कारण जो माहौल बन गया है, उससे आर्थिक गतिविधियों के दरवाजे फिर बंद होने लगे हैं।

उड्डयन, ऑटोमोबाइल, पर्यटन, मॉल, स्पा, होटल, रेहड़ी-पटरी जैसे छोटे-बड़े क्षेत्रों के कारोबार एक बार फिर से ठप होने के कगार पर हैं। घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में लगातार गिरावट हो रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 20 अप्रैल को 155,207 यात्रियों ने घरेलू उड़ानों में यात्रा की। इसके पहले 19 अप्रैल को यह आंकड़ा 169,971 यात्रियों का था और 17 अप्रैल को घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 182,189 थी। जबकि फरवरी के अंत में घरेलू हवाई यात्रियों की एक दिन की संख्या 313,000 थी, जो पिछले मई में उड़ानों की बहाली के बाद यात्रियों की सर्वाधिक संख्या थी।

बेरोजगारी चरम पर

अर्थव्यवस्था की सेहत मापने का सटीक पैमाना बेरोजगारी दर होता है। सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के आंकड़े के अनुसार 23 अप्रैल को देश की बेरोजगारी दर 7.74 फीसदी हो गई, जो मार्च में 6.52 फीसदी थी। अप्रैल में बेरोजगारी दर में लगातार वृद्धि का रुझान बना हुआ है और महीने के अंत तक यह आठ फीसदी से ऊपर जा सकती है। यानी तब हम अगस्त 2020 की स्थिति में पहुंच जाएंगे, जब बेरोजगारी दर 8.35 फीसदी थी। उसके बाद के महीनों में दिसंबर (9.06 फीसदी) को छोड़कर यह छह से सात फीसदी के बीच बनी रही। यानी हमने अगस्त से मार्च तक आठ महीनों में जो हासिल किया था, वह एक महीने के दौरान हाथ से निकल चुका है। रेटिंग एजेंसियों और ब्रोकरेज कंपनियों ने विकास दर के अपने अनुमान घटा दिए हैं। मूडीज ने भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने ऋणात्मक साख की जोखिम की आशंका जताई है, यानी आर्थिक गतिविधियां सुस्त होने से लेनदार न कर्ज लेने की स्थिति में रहेंगे और न चुकाने की स्थिति में। लक्षण स्पष्ट हैं, क्योंकि बैंकिंग प्रणाली में अतिरिक्त धनराशि बढ़ती जा रही है। बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में जमा जो राशि 31 मार्च को अड़तीस खरब रुपए थी, वह 18 अप्रैल तक बढ़कर 55.5 खरब रुपए हो गई। यानी बैंकों द्वारा कर्ज देने या लेनदारों द्वारा कर्ज लेने की रफ्तार में अप्रत्याशित गिरावट आई है। मूडीज ने कहा है कि यदि संक्रमण की स्थिति नियंत्रित नहीं हो पाई तो वित्त वर्ष 2021-22 में 13.7 प्रतिशत विकास दर के उसके अनुमान को हासिल कर पाना भारत के लिए कठिन हो सकता है।

महामारी की दूसरी लहर का वाहन उद्योग पर बुरा असर पड़ा है। कई कारखानों में उत्पादन एक बार फिर ठहर-सा गया है। देश में बनने वाले कुल वाहनों का एक-चौथाई हिस्सा अकेले महाराष्ट्र में बनता है, लेकिन वहां इन दिनों सख्त पाबंदियां लगी हैं और कारखाने सामान्य दिनों की तुलना में 50-60 फीसदी क्षमता के साथ ही संचालित हो रहे हैं। इससे 100 से 125 करोड़ रुपए प्रतिदिन का नुकसान हो रहा है। मरीजों के लिए ऑक्सीजन की भारी मांग के कारण इस्पात संयंत्रों को होने वाली आपूर्ति अस्पतालों की ओर मोड़ दी गई है। इस कारण इस्पात कारखानों में भी उत्पादन बंद हो गया है।

पाबंदियों के कारण असंगठित क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत की 90.7 फीसदी श्रमशक्ति असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, लिहाजा इस क्षेत्र के प्रभावित होने से बड़ी संख्या में लोगों के बेरोजगार होने का खतरा पैदा हो गया है। इसी तरह शहरों और महानगरों में खरीदारी के बड़े ठिकानों के भी बुरे दिन लौट आए हैं। देशभर में मॉल कारोबार नब्बे प्रतिशत तक लौट आया था, लेकिन महामारी की दूसरी लहर के कारण अप्रैल में इस क्षेत्र के कारोबार पर फिर से ग्रहण लग गया। हर महीने पंद्रह हजार करोड़ रुपए की कमाई करने वाले इस क्षेत्र की कमाई स्थानीय पाबंदियों के कारण घटकर आधी भी नहीं रह गई है। आर्थिक अनिश्चितता के कारण उपभोक्ताओं का भरोसा भी डगमगाया है। रिफिनिटिव-इप्सास के मासिक प्राइमरी कंज्यूमर सेंटीमेंट इंडेक्स (पीसीएसआई) के अनुसार, उपभोक्ताओं के भरोसे में पिछले एक महीने के दौरान 1.1 फीसदी की गिरावट आई है।

● **नवीन रघुवंशी**

पीडीएस के विस्तार का समय

अप्रैल 2021 में पूरे उत्तर और पश्चिम भारत में कोरोनावायरस के प्रकोप की तीव्रता ने किसानों के आंदोलन को सुर्खियों से बाहर कर दिया है। अपने चारों तरफ अस्पतालों में ऑक्सीजन और आईसीयू के लिए चीख-पुकार करते लोगों की तस्वीरों के बीच किसान नरेंद्र मोदी सरकार के तीन कृषि कानूनों का दृढ़ता से विरोध जारी रखे हुए हैं। उन्होंने अपनी फसल कटाई का काम बंद नहीं किया और बहादुरी के साथ बीमारी तथा मौत का सामना करते हुए बड़ी संख्या में दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं।

अच्छा होता अगर केंद्र सरकार पहल करते हुए ऐलान कर देती कि तीन कृषि कानूनों को मार्च 2023 तक ठंडे बस्ते में रखा जाएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल चुनावों में अपनी जीत का बोध करते हुए, जिसके नतीजे घोषित हो चुके हैं, केंद्र सरकार को शायद ये लगा कि वो इन नतीजों को, कृषि कानूनों पर लोगों के जनमत संग्रह के तौर पर पेश कर सकती हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब, भाजपा के चुनाव हारने के बाद हम केंद्र को जल्द ही किसानों के साथ संपर्क स्थापित करते हुए देख सकते हैं। हमें अभी भी लगता है कि किसानों को अपना आंदोलन वापस ले लेना चाहिए था, कम से कम अप्रैल 2021 में, जब कोविड महामारी की लहर ऊपर उठ रही थी और मीडिया ऐसे रसूखदार लोगों की तस्वीरें दिखा रहा था, जो बेबसी के साथ अपने कोविड पॉजीटिव परिजनों के लिए चिकित्सा सहायता की गुहार लगा रहे थे। संक्रमण के डर के बावजूद किसानों ने न सिर्फ अपनी फसल की कटाई की, बल्कि उसे बहुत बदनाम की हुई मंडियों में भी लेकर आए, जिन्होंने अपना काम जारी रखा हुआ था। 2021-22 के रबी मार्केटिंग सीजन में 30 अप्रैल 2021 तक, 280.39 लाख टन गेहूं खरीदा जा चुका था। ये 30 अप्रैल 2020 की खरीद से 137.35 लाख टन अधिक था, जब वो 143.04 लाख टन था।

संभावना है कि पंजाब, हरियाणा, मप्र और राजस्थान, गेंहू खरीद के अनुमानित लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन उप्र में 55 लाख टन के अनुमान के मुकाबले, सिर्फ 11.50 लाख टन की खरीद हुई है। 2006-08 के वैश्विक खाद्य संकट के बाद, मप्र ने खरीद की एक विश्वसनीय प्रणाली खड़ी की और राज्य में भंडारण क्षमता स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र को आकर्षित करने में सफल रहा। उसने पहले ही 70.66 लाख टन की खरीद कर ली है। लेकिन, बिहार केवल 3,179 टन की खरीद कर पाया है, जिससे पता चलता है कि राज्य अपने गेहूं किसानों के लिए 1,975 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य का बंदोबस्त नहीं कर पा रहा है। केंद्र सरकार के आधीन उपभोक्ता मामलों के विभाग की, मूल्य निगरानी डिवीजन की वेबसाइट (28 अप्रैल 2021 को) दिखाती है कि बिहार में बहुत सी जगहों पर थोक मूल्य 1,600 रुपए से 1,900 रुपए प्रति क्विंटल के बीच था। राज्य के मोतिहारी जिले में, ये सिर्फ 1,500 रुपए प्रति क्विंटल था, जो एमएसपी से 24 प्रतिशत कम था। साफ जाहिर है कि 2006 के बाद से कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) की गैर-मौजूदगी, बिहार के गेहूं किसानों के लिए अच्छी साबित नहीं हुई है।

ऐसा लगता है कि गेहूं की खरीद का पिछले साल का रिकॉर्ड, इस बार टूट जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत, आमतौर पर लगभग 250-270 लाख टन गेहूं उठाया जाता है। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के अंतर्गत, 107.5 लाख टन अतिरिक्त गेहूं उठाया गया था। तब भी, गेहूं खरीद की मात्रा पीडीएस की जरूरत से ज्यादा थी। चूंकि गेहूं की उपज रबी की दूसरी फसलों से अधिक होती है और किसान अपने गेहूं को एमएसपी पर बेच पाते हैं (सिवाय बिहार और उप्र जैसे राज्यों के), इसलिए वो सरसों और चने जैसी दूसरी फसलों के बदले गेहूं बोना पसंद करते हैं। चावल के मामले में, खरीफ के मौजूदा मार्केटिंग सीजन 2020-21 (अक्टूबर 2020 से मार्च 2021) की खरीद ने, सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। 31 मार्च 2021 तक चावल की खरीद 465.47 लाख टन थी, जो 2016-17 के 304.35 लाख टन से 53 प्रतिशत अधिक थी। पिछले साल, रबी सीजन (अप्रैल से सितंबर) में चावल की अब तक की रिकॉर्ड, 126.29 लाख टन खरीद हुई थी, जबकि रबी में चावल का कुल उत्पादन केवल 165.9 लाख टन था। इसका मतलब है कि करीब 76 प्रतिशत चावल, एमएसपी पर खरीदा गया। पंजाब और हरियाणा रबी में चावल पैदा नहीं करते, इसलिए रबी मार्केटिंग सीजन 2019-20 में, चावल की अतिरिक्त खरीद के लिए, उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसकी बजाय पिछले साल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, रबी चावल के प्रमुख ख़रीदार थे। अगर इस साल रबी सीजन में चावल की खरीद, पिछले साल जितनी ही रही (126.29 लाख टन), तो भारत में सितंबर में खरीफ मार्केटिंग सीजन का अंत होते-होते, कुल 592 लाख टन चावल की खरीद की जा चुकी होगी। ये मात्रा 2020-21 में देश के कुल अनुमानित, 1,203.2 लाख टन चावल उत्पादन का करीब 50 प्रतिशत होगी।

● धर्मेन्द्र सिंह कथूरिया

पीडीएस के अंतर्गत कवरेज बढ़ाना

पीडीएस के तहत करीब 350 लाख टन चावल उठाया जाता है। पिछले साल, पीएमजीकेएवाई के तहत 112 लाख टन अतिरिक्त चावल उठाया गया। इस तरह, चावल की खरीद भी जरूरत से कहीं ज्यादा है। फिलहाल, 79.32 करोड़ लोग पीडीएस के अंतर्गत आते हैं। अगर 2020 की अनुमानित आबादी को पीडीएस के दायरे में ले आया जाए, तो 8.17 करोड़ अतिरिक्त लोग बेहद रिआयती अनाज के पात्र हो जाएंगे। इसका मतलब होगा कि पीडीएस कवरेज, 79.32 करोड़ से बढ़कर 87.49 करोड़ हो जाएगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इशारा किया गया है कि नीति आयोग ने एक चर्चा पत्र जारी किया है, जिनमें सिफारिश की गई है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इस कवरेज को घटाकर क्रमशः 60 प्रतिशत और 40 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए। अनुमान के मुताबिक, इससे 47,229 करोड़ रुपए सालाना की बचत हो सकती है।

नई वन नीति की जरूरत

हम मनुष्यों ने आज तक प्रकृति को समझने की कोशिश नहीं की और न ही प्रकृति के प्रबंधन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम सब यह जान जाते तो ऐसा कुछ नहीं होता। याद रखिए जीवन में प्राकृतिक संसाधनों का जो प्रबंधन होता है वह प्रकृति को समझकर ही तय किया जा सकता है और जो पारस्परिक संबंध होते हैं गांव, जंगल, नदी, खेत, धारें, कुएं इनकी महत्ता को भी समझना चाहिए। क्योंकि आज से 30-40 साल पहले जब वन नीति नहीं आई थी, सारे के सारे गांव आग बुझाने के लिए जाते थे बारी-बारी से। वहां पर भोजन ले जाते थे उनके लिए पानी ले जाते थे अब वह संबंध टूट गया है। वन नीति ने इस रिश्ते पर चोट कर दी है। वन अब गांव वालों के लिए गैर संपदा बनकर रह गई है। जब आग लगती स्थिति तस्वीर बिल्कुल बदली हुई है। पुरानी परंपरा को जीवित करना होगा।

सरकार की नीति को दोष दिया जा सकता है क्योंकि इस वन नीति ने ही जंगल को इंसानों से अलग कर दिया है। जन और वन को अलग नहीं किया जा सकता। 1988 की वन नीति, वनों के पर्याप्त विस्तार प्रबंधन करने में सक्षम नहीं है तो इसके कारणों पर ध्यान देना जरूरी है। इस नीति के अनुसार राज्य में 30 फीसदी और पहाड़ में 65 फीसदी वन होने चाहिए। लेकिन इस नीति के चलते इन लक्ष्यों पर पहुंच पाए हैं हम? गत 33 सालों में यह नीति वनों को बेहतर कर पाई है या आग लगने की घटनाओं को रोक लग पाई है? इसके अलावा सामूहिक दोष भी समझना होगा। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन यह सामूहिक दोष है। हमारी क्या, पूरी दुनिया की लाइफ टाइम देखिए। जिस तरह से ऐनर्जी इस्तेमाल करके दुनियाभर में इंडस्ट्रीलाइजेशन, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वह खतरनाक है। हाल ही की एक रिपोर्ट चेतावनी देती है कि विश्व का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया तो दुनिया तबाह हो जाएगी। अब और 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। डेढ़ डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने का मतलब है कि 14 से 20 फीसदी ग्लेशियर बर्फ पिघल जाएगी जिससे आप समझ गए कि तबाही आ जाएगी।

सरकार चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की चिंता किसे है? और इस सरकार को चुनता कौन है? आप और हम। आप ही बताइए चुनाव के दौरान क्या जंगल की आग, आपदा, जलवायु परिवर्तन, नदियों का सूखना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को इंपॉर्टेंस दी जाती है? कोई भी पार्टी इस मुद्दे पर ध्यान दे रही है? ना पार्टी सोचती है ना हम सोचते हैं। यह भी सामूहिक दोष है हम सबका। जंगल की आग से नुकसान का आंकलन तो हो ही नहीं सकता। सरकारी आंकलन का अपना तरीका होता है। सबसे पहले तो अपनी लाज बचाने का काम करती है वह। उसके बाद जो पेड़ जलने से बच गए उनके तनों की गिनती करते हैं। ठूंठ बचा होगा उससे अंदाजा लगाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आग से माइक्रो इकोसिस्टम खत्म होता है। आग की वजह से जमीन के नीचे तकरीबन 10 सेंटीमीटर तक गरमी फैल जाती है। गुड बैक्टीरिया के अलावा कई प्रकार के माइक्रोब्स खत्म हो जाते हैं उनका आंकलन कहां होगा? पत्तियां जल गईं पेड़ बचा हुआ है लेकिन उस पेड़ में जो चिड़ियाएं रह रही थीं उनका क्या? हर पेड़ का अपना एक इकोसिस्टम होता है, वह राख हो गया है उसका आंकलन कैसे करेंगे? नुकसान को इकोनॉमिकली कैलकुलेट किया जा सकता है लेकिन इकोसिस्टम खत्म हुआ उसका आंकलन कैसे करेंगे? इस पर चर्चा करने का कोई मतलब ही नहीं है।

इकोसिस्टम की सर्विस अथाह होती है। पेड़ के पत्ते जो जल गए उनसे जो प्राणवायु ऑक्सीजन मिल रही थी वह तो खत्म हो गई, उसका आंकलन किस तरह करेंगे? पत्ते, डंठल, फल जो भी हैं वह जमीन पर गिरता है, वह जमीन को उपजाऊ और नम बनाए रखता है। हरा भरा ऊपरी हिस्सा आग लगने से बचाता है। जंगल जलने से मिट्टी पर भी असर पड़ता है। उसकी नमी खत्म हो जाती है, वह टूटने लगती है और पहली बारिश में ही सतही मिट्टी बह जाती है। उसका नुकसान जो होता है उसका आंकलन कौन करेगा? सूखी मिट्टी, जली हुई भूमि जल को अवशोषित नहीं कर पाती। जंगल से निकलने वाली नदियों के सूखने की भी यही वजह है।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

दूरगामी योजना क्या हो सकती है?

स्थानीय लोगों की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। जिस तरह से वन नीति ने लोगों को जंगल से दूर कर दिया है उस गैप को भरने के लिए इस पर पुनर्विचार करना बहुत ही जरूरी है। उन्हें भागीदार बनाना होगा उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकेंगे। ना तो उनके पास कोई अधिकार है और ना ही उन्हें वनों से मिलने वाले नफा नुकसान पर कोई भागीदारी। दरअसल देखा जाए तो वन पंचायत काफी हद तक की आग पर काबू पाने में सफल हो सकते हैं। वन पंचायतों का गठन आज मात्र एक औपचारिकता ही प्रतीत होती है क्योंकि, उनके वर्तमान दायित्व और अधिकार उन्हें वनों के संरक्षण के प्रति प्रेरित भी नहीं करते हैं। इन वन पंचायतों को नए तर्ज व शैली में पर्याप्त प्रोत्साहन, इंटेंसिव देकर गांवों के हर दर्जे के वनों के रखरखाव के लिए भी जोड़ा जा सकता है। अकेले मप्र में हजारों वन पंचायतें हैं, जो जंगल की आग को समय पर रोकने के लिए काफी हैं। दूसरी बात यह कि अंधाधुंध कटाई से कनार (शाक) व बांज (ओक) के वनों का खोज लगभग खत्म कर दिया गया, उसकी जगह ले ली है ज्वलनशील चीड़ ने। उसे कम करके कनार और बांस के पेड़ लगाए जाएं। जहां तक संभव हो वॉटरहोल्स (जलछिद्र), चैकडैम बनाएं, आप मान कर चलिए जमीन पर नमी बनी रहेगी। हरे भरे पौधे बढ़ेंगे। जिसकी वजह से आग से जंगल बचे रहेंगे और नदियां बहती रहेंगी, जलस्रोत नहीं सूखेंगे।

माफिया ने फिट किए मोहरे

पंजाब के रूपनगर से बांदा जेल में शिफ्टिंग से पहले और बाद में माफिया मुख्तार अंसारी आसपास के जिलों की जेलों में अपने मोहरे फिट करने में जुटा था। ये बात चित्रकूट जेल में हुए गैंगवार से सामने आई है। चित्रकूट जेल में गैंगवार में गैंगस्टर अंशु दीक्षित ने मुख्तार अंसारी के खास गुर्गे मेराज और बदमाश मुकीम काला की गोली मारकर हत्या कर दी। मेराज बनारस जेल से भेजा गया था, जबकि मुकीम काला सहारनपुर जेल से लाया गया था। मेराज को फर्जी तरीके से शस्त्र लाइसेंस बनवाने और उसके नवीनीकरण के आरोप में 3 अक्टूबर 2020 को वाराणसी की जैतपुरा थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 20 मार्च 2021 को प्रशासनिक आधार पर मेराज को चित्रकूट जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। अब चर्चा है कि आसपास जिलों की जेलों में उसके गुर्गे हो सकते हैं।

चित्रकूट जेल में गैंगवार के दौरान तीन बंदियों की मौत अचानक हुई वारदात नहीं है। इसकी पटकथा काफी पहले लिखी जा चुकी थी। इसकी पुष्टि खुद मामले की जांच करने वाले अफसरों की रिपोर्ट बता रही है। जिस हाई सिक्योरिटी सेल में अंशु दीक्षित और मेराज को रखा गया था, वहां के सीसीटीवी करीब दो महीने पहले ही बंद किए जा चुके थे। जांच में सामने आया कि जिस हाई सिक्योरिटी सेल में अंशु को रखा गया था वहां और उसके आसपास के सभी कैमरे बंद थे। पूछताछ में जिम्मेदारों ने बताया कि करीब दो महीने पहले सभी कैमरे एक साथ खराब हो गए। इनके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी इसे लगाने वाली एजेंसी की है। एजेंसी को दर्जनों शिकायती पत्र भेजे गए लेकिन अभी तक कैमरों की मरम्मत नहीं की गई। जांच रिपोर्ट से साफ है कि चप्पे-चप्पे पर कैमरों की नजर रखने का दावा करने वाला शासन जेल जैसी संवेदनशील जगह पर इतने समय तक कैमरे बंद नहीं रहने देगा। अगर ऐसा था भी तो सवाल उठता है कि इसे ठीक करने में लापरवाही बरतने वाली एजेंसी को ब्लैक लिस्ट या उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने जैसी कोई ठोस कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की गई?

जांच में सामने आया कि अंशु असलहा लेकर उस दायरे से बाहर नहीं गया, जिसे वारदात के लिए चुना गया था। सेल के भीतर ही उसके पास घातक 9 एमएम की पिस्टल पहुंचाई गई। इससे उसने पहले अपने सेल के इनक्लोजर में मौजूद मेराज को गोली मारी। इसके बाद सेल के खुले दरवाजे को पार कर करीब 50 मीटर दूर किशोर जेल पहुंचा, जहां मुकीम उर्फ काला था। मुकीम की हत्या करके वापस अपनी सेल में पहुंचा और कुछ बंदियों को गन पॉइंट पर लेकर जेल के सुरक्षाकर्मियों को ललकारने लगा। इस पर पुलिस ने घेराबंदी करके अंशु को गोली मारी। लेकिन पूरे घटनाक्रम की एक भी तस्वीर जेल के उन कैमरों में भी कैद नहीं हुई जो ठीक-ठाक काम कर रहे थे। दरअसल कैमरों को इस हिसाब से खराब किया गया था कि वारदात के लिए पर्याप्त दायरा तैयार हो सके। उधर, कहा जा रहा है कि मुख्तार पहले से ही यह जमावट कर रहा था कि वह जिस जेल में रहे उसमें या उसके आसपास की जेलों में करीबी कैदी रहें। बांदा मंडल कारागार में माफिया मुख्तार पहले भी बंद रह चुका है। जेल में निरुद्ध रहने के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ी तो जिला अस्पताल लाए जाने पर कुछ ही क्षण में उसके दर्जनों करीबी जेल पहुंच गए थे। तब पता चला था कि मुख्तार के स्वजन यहां एक खास के घर में शरण लिए थे। वहीं, घनी बस्तियों व पॉश इलाके के मकानों को किराए पर लेकर उसके खास शूटर शरण पाए थे। यही वजह रही कि माफिया के फिर बांदा जेल शिफ्ट होने पर पुलिस व खुफिया ने ऐसे सभी मोहल्लों पर अपनी नजरें गड़ा दी थीं, जहां पूर्व में उसके खास लोग शरण लिए थे। सूत्रों के मुताबिक, इस बार उसके खास लोगों ने अपनी चाल बदल दी है। पहले की तरह बाहर के नंबर की गाड़ियां इस बार शहर में नजर नहीं आ रही हैं। वजह, पुलिस की रणनीति जाहिर हो गई थी कि बाहर के नंबर वाली गाड़ियों पर उसकी पैनी नजर रहेगी। कयास है कि माफिया के कुछ खास लोग शहर व आसपास के ग्रामीण इलाकों में छिपे हैं।

रमजान की शुरुआत में ही प्रयागराज से आए खुद को वकील बताने वाले शख्स ने मुख्तार से मुलाकात की कोशिश की थी, लेकिन कोरोना का हवाला देकर इजाजत नहीं मिली थी। यह जरूर है कि उनका लाया ब्रांडेड कंपनियों का सामान सुरक्षा जांच के बाद जेल में भिजवा दिया गया था। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी मंडल कारागार की करीब 50 सीसीटीवी कैमरों से चप्पे-चप्पे की निगरानी के साथ लखनऊ मुख्यालय से मॉनीटरिंग हो रही है। माफिया की बैरक के आसपास किसी को फटकने की इजाजत नहीं है। पांच बॉडी वार्न कैमरों के साथ ही ड्रोन कैमरा भी जेल प्रशासन को मुहैया कराया गया है।

● **सिद्धार्थ पांडे**

मुख्तार पर पल-पल नजर, फिर अंशु पर मेहरबानी क्यों

बस्ती जिला जेल में बंदियों के विद्रोह में हुई गोलीबारी में एक बंदी की मौत के बाद जेल प्रशासन सुरक्षा को लेकर चौकन्ना हुआ। इसके बाद सभी जेलों को कैमरों के इंट्रीग्रेटेड कमांड सिस्टम से जोड़ा गया। इससे जेल मुख्यालय प्रदेश की सभी 72 जेलों में हो रही हल पल की गतिविधियों पर नजर रखता है। 7 अप्रैल को माफिया मुख्तार अंसारी को बांदा जेल लाया गया तो उनके हाई सिक्योरिटी सेल में अतिरिक्त कैमरे लगाए गए। इन कैमरों से मुख्तार की हर हरकत पर जेल मुख्यालय नजर रख रहा है। सवाल उठता है कि चित्रकूट जेल की जिस सेल में प्रदेश के हार्डकोर क्रिमिनल बंद थे उनके कैमरे में नजर न आने पर भी जेल मुख्यालय खामोश क्यों बैठा था? अभी तक कि जांच में यह सामने नहीं आया कि अंशु का मेराज और मुकीम से कोई व्यक्तिगत विवाद था जिसके लिए वह इतना बड़ा रिस्क लेकर जेल में उनकी हत्या करता। जांच अफसरों का कहना है कि अंशु के ऐसा कदम उठाने के पीछे मोटिव क्या था। इसका पता नहीं चल पा रहा है। अफसरों का यह भी कहना है कि तीनों के बीच कोई खासी जान पहचान भी नहीं थी। जेल में भी उनके बीच किसी तरह का विवाद नहीं हुआ था।

सांसों की सौदेबाजी

देश में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने के बाद जब पहली बार लॉकडाउन किया गया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की थी कि यह समय आपदा को अवसर बनाने का है। सरकार भले ही आपदा को अवसर नहीं बना पाई, लेकिन कालाबाजारियों ने इसे जमकर भुनाया। दूसरी लहर में जिस तरह ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और अन्य दवाओं की कालाबाजारी हुई, उससे मानवता तार-तार हो गई। लालची कालाबाजारियों ने सांसों की जमकर सौदेबाजी की।

● राजेंद्र आगाल

कोरोना की दूसरी लहर से बेफिक्र भारत सरकार ने विश्वगुरू बनने के लिए पड़ोसी देशों सहित विश्व के कई देशों को वैक्सीन भेजी। लेकिन दूसरी लहर भारत में इस कदर जानलेवा हो गई कि सरकार के सारे दावों की पोल खुल गई। न अस्पतालों में जगह बची, न दवा मिली। ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन सहित कई दवाओं के अभाव में लोग असमय कालकवलित हो गए। सरकारी व्यवस्था चरमराने के बाद कालाबाजारियों ने मोर्चा संभाला और अपनों का जीवन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे लोगों को मुंहमांगी कीमत पर ऑक्सीजन और नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचकर जमकर कमाई की। उधर, मप्र सहित देश के जितने बड़े राज्य अपने आप को विकसित होने का दावा कर रहे थे, उन्हें छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा जैसे गरीब राज्यों के आगे ऑक्सीजन के लिए मिन्नत करनी पड़ी। इन राज्यों ने पूरे देश को ऑक्सीजन सप्लाई कर लाखों लोगों की जान बचाई।

कोविड-19 की तुलना अक्सर स्पेनिश फ्लू से की गई है, जिसमें 1918 से 1920 के बीच करीब 5 करोड़ लोग मारे गए थे। उस फ्लू की एक मनहूस खासियत संक्रमण की एकाधिक विनाशकारी लहरें थीं, कुछ उसी तरह जैसे कोरोनावायरस के मामले में देखा जा रहा है। इस साल फरवरी में जब यूरोप कोविड-19 के मामलों की दूसरी जबरदस्त लहर की चपेट में था, भारत अपनी पीठ थपथपा रहा था। यह सोचकर कि उसने वायरस पर काबू पा लिया है और 2020-21 की पहली छमाही में मंदी झेलने के बाद देश आर्थिक बहाली की राह पर है। मध्य मार्च आते-आते वह उजला आशावाद झूठा साबित हुआ, जब भारत में भी कोविड के मामले एक बार फिर उछाल भरने लगे। संक्रमण और मौत के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया। इससे सरकार की स्वास्थ्य सहित अन्य व्यवस्था की पोल खुल गई, वहीं यह अवसर कालाबाजारियों के लिए स्वर्णकाल साबित हुआ।

आपदा को अवसर बनाया

साल 2020, एक बेहद मनहूस और दिल को दहलाकर रख देने वाला साल। ऐसा साल जब चीन के वुहान से एक वायरस जिसका नाम कोरोना वायरस था, चला और उसने ऐसी तबाही मचाई की देखने वाले बस देखते रह गए। दुनियाभर में लोगों ने अपनों को खोया और इसका असर भारत में भी हुआ। अब इसे विडंबना कहें या दुर्भाग्य करीब एक साल बाद भारत में स्थिति जस की तस बनी हुई है और मौत का ग्राफ दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। साल 2020 में जब दुनिया इस वायरस के कोप से थर-थर कांप रही थी, यहां भारत में हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमाम तरह की बातें करते सुना। साल 2020 में मार्च के बाद हमने कई मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी से राष्ट्र को संबोधित होते देखा और एक दिन वो भी आया जब हमने प्रधानमंत्री को ये कहते सुना कि अब हमें कोरोना के साथ ही जीवन गुजारना है और इस आपदा को अवसर में बदलना है। साल 2020 में प्रधानमंत्री मोदी की ये बातें हमें जुमला लगीं मगर अब जबकि 2021 में हम भारत में कोविड-19 की दूसरी वेव में अपने करीबियों को इलाज और मूलभूत चिकित्सीय सुविधा के आभाव में दुनिया से रुक्सत होते देख रहे हैं महसूस होता है कि प्रधानमंत्री मोदी की आपदा में अवसर की बात केवल जुमला नहीं थी उसके पीछे गहरे अर्थ छिपे हुए थे।

संक्रमण के इस दौर में धंधेबाज न केवल शासन-प्रशासन की नजरों में धूल झोंक रहे हैं बल्कि कालाबाजारी को अंजाम देते हुए जमकर आपदा को अवसर में बदल रहे हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ गए। आपदा के इस दौर में प्राइवेट अस्पताल, एम्बुलेंस सेवाओं, दवा कंपनियों और विक्रेताओं आदि ने जमकर चांदी काटी है।

इतिहास में जब भी कोविड की इस दूसरी लहर के चलते मौत की दास्तां लिखी जाएगी उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल के मालिकानों का जिक्र अवश्य होगा। आज जैसे हालात हैं वो तमाम लोग जो किसी अपने के इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल का रुख कर रहे हैं उनका भरपूर शोषण प्राइवेट अस्पताल का मैनेजमेंट कर रहा है। क्या देश की राजधानी दिल्ली, क्या लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, आगरा और वाराणसी हर जगह स्थिति कमोबेश एक जैसी ही है। चूंकि प्राइवेट अस्पताल फौरन ही मरीज को अपने आईसीयू में डाल दे रहे हैं। इस आपदा में हम कई ऐसे अस्पतालों के बारे में सुन चुके हैं जो मरीजों से आईसीयू के नाम पर हर दिन के हजारों रुपए ऐंठ रहे हैं। इन अस्पतालों में कालाबाजारी का लेवल क्या है इसका अंदाजा इसी को देखकर लगाया जा सकता है कि आईसीयू चार्ज के अलावा मरीज से दवाइयों और हॉस्पिटल में मुहैया हो रही ऑक्सीजन की मोटी कीमत वसूली जा रही है।

आज इस मुश्किल हालात में जब हर दूसरा व्यक्ति आपदा में अवसर तलाश रहा हो हम एम्बुलेंस सर्विस देने वालों को कैसे खारिज कर सकते हैं। चाहे कुछ मीटर हों या कई किलोमीटर हर यात्रा के लिए इनकी अपनी रेट लिस्ट है, जिसमें छूट की शायद ही कोई गुंजाइश हो। तमाम ऐसे मामले आए हैं जिसमे अपने मरीज को चंद किलोमीटर ले जाने के लिए इन निष्ठुरों ने मोटी रकम वसूली है। ऐसा नहीं है कि ये अस्पताल से अस्पताल भटकते मरीज को ही झेलना पड़ रहा है यदि किसी की मौत हो जाए और उसे एम्बुलेंस से श्मशान या कब्रिस्तान ले जाना हो तो इनकी जिस तरह की कालाबाजारी देखने को मिलती है कठोर से कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी पसीज कर मोम बन जाए। आपदा के

चिकित्सा व्यवस्था बदहाल

यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना महामारी के इस संकटकालीन दौर में यही दर्शाती है कि महामारी से निपटने के लिए देश में स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा ही नहीं है। हमारे पास मरीजों के लिए बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और जीवनरक्षक दवाइयों का भारी अभाव है। लेकिन जैसा कि जाने-माने हृदयरोग विशेषज्ञ डॉ. देवी प्रसाद शेट्टी का कहना है कि मरीजों का इलाज बेड नहीं, बल्कि डॉक्टर करते हैं। देश में स्वास्थ्यकर्मियों की भारी कमी ने कोविड के खिलाफ लड़ाई को अत्यंत कठिन बना दिया है। इन स्वास्थ्यकर्मियों में डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और टेक्नीशियन शामिल हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक, देश में हर 10,000 लोगों पर मात्र 37.6 स्वास्थ्यकर्मी हैं जबकि डब्ल्यूएचओ (विश्व स्वास्थ्य संगठन) के मानदंडों के अनुसार यह संख्या न्यूनतम 44.5 होनी चाहिए। मेडिकल कॉलेजों की संख्या के हिसाब से भारत में 562 मेडिकल कॉलेज हैं, और यह विश्व में पहले स्थान पर है। इसलिए आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारा देश डॉक्टरों की संख्या के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है। लेकिन 130 करोड़ की आबादी को देखते हुए डॉक्टर-मरीज का अनुपात बहुत दयनीय है। प्रत्येक 10,000 लोगों पर केवल 9 डॉक्टर हैं, जबकि जर्मनी में 42, ब्रिटेन में 28, और अमेरिका में 26 डॉक्टर हैं। चीन से तुलना करें तो बहुत बड़ा अंतर है। 140 करोड़ की आबादी वाले चीन में भारत की तुलना में करीब तीन गुना 36.1 लाख डॉक्टर हैं। भारत में 32 लाख नर्सें हैं और 5,085 संस्थानों से हर साल करीब 3,35,000 नर्सिंग प्रोफेशनल तैयार होते हैं, फिर भी 10,000 लोगों पर हमारे यहां केवल 15 नर्सें हैं जबकि ब्रिटेन में 150, जर्मनी में 132, अमेरिका में 85 और चीन में 23 है।

सरकार की यह कैसी तैयारी... न ऑक्सीजन, न कंटेनर

दूसरी लहर में जब लोगों का जीवन बचाने के लिए ऑक्सीजन की मांग बढ़ी तो यह तथ्य सामने आया कि देश में न ऑक्सीजन है और न ही उसे लाने वाले कंटेनर। जबकि पहली लहर में ही केंद्र और मप्र सहित देश की अन्य सरकारों ने भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने के दावे किए थे। चिकित्सीय ऑक्सीजन प्रत्येक दिन देश में तैयार होने वाले 7,500 टन औद्योगिक ऑक्सीजन का एक छोटा-सा हिस्सा होता है। विशिष्ट वायु पृथक्करण इकाइयां वायुमंडलीय हवा को सोखती हैं और इसे अपने मूल तत्वों-नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित कर देती हैं। ऑक्सीजन को तरलीकृत करके क्रायोजेनिक कंटेनरों में विशेष टैंकरों में भेज दिया जाता है, और उसे शून्य से 183 डिग्री नीचे के तापमान पर रखा जाता है। हर टैंकर में 17,000 लीटर तरलीकृत ऑक्सीजन होती है। भारतीय इस्पात उद्योग उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है, जो बुनियादी ऑक्सीजन प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, या ब्लास्ट फर्नेस लोहे को स्टील में बदलने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन को तरल ऑक्सीजन में तब्दील किया जाता है। अधिकांश बड़े ऑक्सीजन संयंत्र देश के इस्पात क्षेत्र के पास स्थित हैं- पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में।

इस अवसर पर एम्बुलेंस वाले उतने पैसे मांग ले रहे हैं जितने का प्रबंध करना एक आम आदमी के लिए टेढ़ी खीर है। मुद्दा आपदा में अवसर का है और बात लूट घसोट और कालाबाजारी की चली है तो हम मेडिकल स्टोर वालों के साथ-साथ उन लोगों को क्यों नजरअंदाज करें जो मरीजों को सर्जिकल का सामान मुहैया करा रहे हैं। चाहे आप ऑक्सीमीटर के लिए इनके पास जाएं या फिर ऑक्सीजन किट, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए इनसे पूछें कीमत 5 गुनी हैं।

ये अपने आप में विचलित करने वाला है कि जो सामान आज से 15-20 माह पहले साधारण कीमतों पर थे वो आज कैसे आसमान पर पहुंच गए। हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि ये सब उस वक्त में हुआ है जब कोविड की दूसरी लहर का पीक आना अभी बाकी है। बात मेडिकल स्टोर वालों की हुई है और उनके द्वारा की जा रही कालाबाजारी पर चर्चा हो रही है तो ये बताना भी बहुत जरूरी है कि ये वही लोग हैं जो एक जमाने में दवाइयों की खरीद पर 10 प्रतिशत या 15 प्रतिशत की छूट देते थे लेकिन आज इनका रवैया पूरी तरह बदल चुका है। जरूरी दवाइयां और मेडिकल से जुड़े सामान या तो इन्होंने स्टॉक कर लिए हैं या फिर ये मुंह मांगी कीमतों पर सामान देकर कालाबाजारी की आग को हवा दे रहे हैं।

ऑक्सीजन के लिए संघर्ष

आपदा को अवसर में बदलने वाली इन बातों के सबसे अंत में हम उन लोगों का जिक्र करना चाहेंगे जो हैं तो मानव योनि में लेकिन जो किसी गिद्ध से कम नहीं हैं। जिस तरह किसी मरते हुए पशु को देखकर गिद्ध उसके ऊपर मंडराने लगते हैं वैसा ही हाल ऐसे लोगों का है। जब देश में ऑक्सीजन की किल्लत शुरू हुई इन लोगों ने तमाम जरूरी चीजों को स्टॉक कर लिया। आज जब लोग मदद की डिमांड कर रहे हैं तो ऐसे ही लोगों की बड़ी संख्या सामने आ रही है और मदद के नाम पर मोटे पैसे अपनी जेब में डाल रही है। ऑक्सीजन का वो छोटा सिलेंडर जो कभी 6 हजार रुपए में मिल जाता था आज उसे ये लोग 25 से 30 हजार के बीच बेच रहे हैं इसी तरह ऑक्सीजन का वो जंबो सिलेंडर जिसकी

वैक्सीन कंपनियों ने कर डाली 5 हजार करोड़ की कमाई

पूरे देश में टीके के टोटे से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन वैक्सीन कंपनियां आपदा की इस घड़ी में भी कमाई करने में जुटी हैं। देश की वैक्सीन कंपनियों ने जहां 5 हजार करोड़ कमा लिए, वहीं कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम अकेले अब तक 2200 करोड़ का मुनाफा कमा चुकी है। फिर भी देश में वैक्सीन का टोटा है। इस कारण देशभर में वैक्सीनेशन अभियान ठप हो गया है। वैक्सीनेशन ने भारत को कोविड-19 की अफरा-तफरी से उबरने के लिए रास्ता दिया है, लेकिन वैक्सीन की आपूर्ति ही पर्याप्त नहीं है और इसके लिए बजट के बारे में भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। वैक्सीन की कमी के चलते देशभर में वैक्सीनेशन अभियान पूरी तरह सुस्त पड़ा है। 130 करोड़ की आबादी में अब तक जहां 17.72 करोड़ लोगों को वैक्सीन का टीका लगा है, वहीं सिर्फ 4 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जिनको वैक्सीन के दोनों डोज लग पाए। वैक्सीन कंपनियों ने 5 हजार करोड़ उस समय कमाए, जब देश को वैक्सीन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हुई, लेकिन अब भारत सहित दुनियाभर में वैक्सीन की मांग के चलते यह कंपनियां 16 हजार करोड़ का मुनाफा कमाएंगी। यह आरोप दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार दोनों कंपनियों को मुनाफा कमाने का बहुत ज्यादा अवसर दे रही है। केंद्र को सीरम जो वैक्सीन 150 रुपए में दे रही है, वही राज्यों को दोगुने दाम पर दी जा रही है। सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वित्तीय आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष 2019-20 में ही 5,920 करोड़ का टर्नओवर किया, जिसमें उसने 41.3 प्रतिशत शुद्ध मुनाफे के तौर पर 2,251 करोड़ कमाए। इसी तरह देश में वैक्सीन पर काम कर रही अन्य 418 कंपनियों ने 5 हजार करोड़ रुपए से अधिक आय की घोषणा की। सीरम राज्य सरकारों को 300 रुपए तो निजी अस्पतालों को 600 रुपए प्रति खुराक के हिसाब से कोविशील्ड की आपूर्ति कर रही है, जबकि केंद्र सरकार को 150 रुपए में भी वैक्सीन देने पर लाभ कमा रही है। इतने मुनाफे के बावजूद सीरम वैक्सीन के दाम बढ़ाने की मांग कर रही है। भारत सरकार द्वारा जहां कोरोना से लड़ाई में ढिलाई बरती गई वहीं जीवन बचाने वाली वैक्सीन के उत्पादन पर भी ध्यान नहीं दिया गया और नतीजा यह रहा कि वैक्सीन उत्पादन करने वाली सीरम ने अधिकांश डोज जहां विदेशों में निर्यात कर डाले वहीं देश की अन्य दवा उत्पादक कंपनियों को भारत सरकार ने मंजूरी ही नहीं दी और न ही भारत की बायोटेक कंपनी की वैक्सीन को तवज्जो दी।

कीमत 15 हजार हुआ करती थी आज इन लोगों की बदौलत 80 हजार से 1 लाख के बीच मिल रहा है। मामले में दिलचस्प ये भी है अब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन इनकी नजर में आ गई है और इन्होंने उसकी कालाबाजारी शुरू कर दी है। जो मशीन अभी कुछ दिनों पहले तक 50 हजार में आसानी से मिल जाती थी आज ये लोग उस मशीन को सवा लाख से डेढ़ लाख के बीच बेचकर आपदा को अवसर में बदल रहे हैं।

पहली लहर में सांस की तकलीफ वाले अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या 41.7 फीसदी थी। दूसरी लहर में ऐसे 47.5 फीसदी रोगी हैं। दूसरी लहर में वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से हो रहा है, इसलिए ऑक्सीजन की जरूरत वाले रोगियों की संख्या भी बढ़ी है। गंभीर रूप से बीमार कोविड रोगियों को प्रति मिनट 2 से 8 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसलिए 7,800 लीटर की क्षमता वाला पांच फुट लंबा ऑक्सीजन सिलेंडर मात्र 6 घंटे चलता है। वेंटिलेटर से अधिक चिकित्सीय ऑक्सीजन वायरस के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण होने जा रहा है, जो मानव शरीर के श्वास तंत्र को पंगु बना देता है। इसे सरकार पिछले साल से ही अच्छी तरह से जानती थी। इसलिए मार्च 2020 में केंद्र सरकार के 11 अंतर-मंत्रालयीय अधिकार प्राप्त समूहों के सामने यह प्रमुख एजेंडे में से एक था।

अपनों के लिए वैक्सीन नहीं

कुछ माह पहले तक विदेशों में वैक्सीन भिजवाकर वाहवाही लूटने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि देश में हर एक व्यक्ति को वैक्सीन लगाई जा सके। लेकिन सरकार के पास वैक्सीन नहीं है। सीरम और बायोटेक द्वारा मांग की आपूर्ति से हाथ खड़े कर दिए जाने के बाद दिल्ली, राजस्थान सहित 13 राज्यों ने ग्लोबल टेंडर निकालकर विदेशी वैक्सीन निर्माताओं से वैक्सीन खरीदने का निर्णय लिया है। इन दोनों राज्यों के अलावा कर्नाटक, उत्तराखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उप्र, ओडिशा, हरियाणा के साथ ही मप्र भी शामिल है। इन राज्यों के जरिए टीके की कितनी खुराक मंगाई जाएगी, यह अब तक स्पष्ट नहीं हैं। कर्नाटक की योजना 2 करोड़ (20 मिलियन) खुराक खरीदने की है, जबकि राजस्थान एक से चार करोड़ (10-40 मिलियन) खुराक के बीच कहीं भी ऑर्डर करेगा। टीकों के आयात को भारत सरकार के मानदंडों को पूरा करना होगा। भारतीय दवा नियंत्रक ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड और गामालेया इंस्टीट्यूट द्वारा टीकों को मंजूरी दी है। भारत इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अनुमोदित टीकों का भी आयात कर सकता है। ये फाइजर इंक, मॉडरना, जॉनसन एंड जॉनसन, एस्ट्राजेनका पीएलसी और चाइना नेशनल फार्मास्यूटिकल्स ग्रुप कॉर्प (सिनोफॉर्म) द्वारा निर्मित टीके हैं। भारत की अनुमानित जनसंख्या 139 करोड़ है। अगर हम यह मान लें कि इनमें से 70 प्रतिशत आबादी वैक्सीन के लिए पात्र है तो यह संख्या लगभग 97.4 करोड़ आती है। अगर हम यह मान लें कि हर्ड इम्युनिटी पाने के लिए इनमें से 60 प्रतिशत आबादी को वैक्सीन लगाना जरूरी होगा, तब हमें 58.4 करोड़ लोगों का टीकाकरण करना ही पड़ेगा। अगर इसे सुलझाकर कहें तो 60 करोड़ से लेकर एक अरब आबादी टीकाकरण के लिए पात्र है। इसका मतलब है कि भारत में उपलब्ध दोहरे डोज वाली वैक्सीन के साथ सभी का टीकाकरण करने के लिए हमें 1.2 अरब से 2 अरब डोज की जरूरत है।

वैक्सीन आपूर्ति की मौजूदा स्थिति

इतने ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए उत्पादन क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है। 9 मई को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे के अनुसार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (जो कोविशील्ड का उत्पादन करता है) ने अपनी उत्पादन क्षमता को प्रतिमाह 5 करोड़ से 6.5 करोड़ तक बढ़ाया है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड (जो कोवैक्सीन उत्पादित करता है) ने अपने उत्पादन को 9 लाख डोज से 2 करोड़ डोज तक बढ़ाया। यह उम्मीद है कि यह जुलाई के अंत तक प्रतिमाह 5.5 करोड़ डोज बढ़ जाएगी। स्पूतनिक-वी (डॉ. रेड्डीज लैब की ओर से वितरित) की आपूर्ति जुलाई के अंत तक 3 लाख डोज से बढ़कर 1.2 करोड़ डोज तक पहुंचने की उम्मीद है। इस प्रकार हमारे पास जुलाई के अंत तक प्रतिमाह 13.2 करोड़ डोज उपलब्ध होगी। अगर हम यह मान लें कि सभी लोगों का टीकाकरण करने में चार महीने लग जाएंगे, तब भारत को हर महीने 30-60 करोड़ डोज की जरूरत है। कोविड-19 की दूसरी लहर में अधूरे इंतजाम और ध्यान देने के आरोपों को खारिज करते हुए नीति आयोग ने कहा है कि वायरस फिर से उभर सकता है और इसलिए राज्यों के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर पर तैयारी की जानी चाहिए, बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की जरूरत है। नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वीके पॉल ने इन आरोपों को खारिज किया

चिकित्सा की प्राणवायु

जैसे ही देश के 12 राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपाना शुरू किया, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने संक्रमण के पहले दिन से ही फेफड़े को नुकसान पहुंचाने वाले वायरस के नए आक्रामक स्ट्रेन का पता लगाना शुरू कर दिया। सांस लेने में तकलीफ दूसरी लहर का सबसे बड़ा लक्षण है। पश्चिमी दिल्ली के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सचिव और पल्मोनोलॉजिस्ट (श्वास रोग विशेषज्ञ) डॉ. संदीप दत्ता कहते हैं, नए म्यूटेंट स्ट्रेन इतने आक्रामक हैं कि आप पहले या दूसरे दिन दवा नहीं देते हैं, तो रोगी की पहले ही गंभीर स्थिति हो जाती है। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली साइटोकिन को बढ़ावा देती है, जो शरीर की अपनी कोशिकाओं और ऊतकों पर हमला करती है, न कि वायरस पर। यह 'साइटोकिन तूफान' फेफड़ों को सूजन और गंभीर क्षति की ओर ले जाता है, जिससे हवा से ऑक्सीजन ग्रहण करने करने की फेफड़ों की क्षमता खत्म हो जाती है, जिससे हाइपोक्सिया हो जाता है। गंभीर रूप से बीमार रोगियों को सांस लेने में सहायता प्रदान के लिए चिकित्सा ऑक्सीजन की जरूरत इस प्रकार महत्वपूर्ण हो जाती है।

कि सरकार दूसरी लहर की तीव्रता से अनजान थी। उन्होंने कहा कि हम इस मंच से बार-बार चेतावनी देते रहे हैं कि कोविड-19 की दूसरी लहर आएगी। पॉल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 17 मार्च को दूसरी लहर के उभरने के बारे में देश में दहशत उत्पन्न किए बिना बता दिया था और कहा था कि हमें इससे लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि हमने दहशत उत्पन्न नहीं की थी, अन्य देशों ने कई उच्चतम स्तर तक सामना किया है, आखिरकार यह एक महामारी है।

2,000 करोड़ के वेंटिलेटर बीमार

देश में जारी कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने गत दिनों एक हाईलेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कुछ राज्यों में वेंटिलेटर का उपयोग सही से नहीं होने की कुछ रिपोर्टों को गंभीरता से लिया। उन्होंने निर्देश दिया कि केंद्र सरकार की ओर से मुहैया कराए गए वेंटिलेटर्स की इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन का तत्काल ऑडिट किया जाना चाहिए। कोरोना के साथ-साथ वैक्सीनेशन की स्थिति पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को कोरोना संक्रमण के मौजूदा हालातों के बारे में बताया। ये भी बताया कि देश में टेस्टिंग की रफ्तार भी बढ़ रही है। मार्च में हर हफ्ते 50 लाख के आसपास टेस्ट होते थे, पर अब हर हफ्ते 1.3 करोड़ टेस्ट हो रहे हैं। प्रधानमंत्री को ये भी बताया कि देश में लगातार पॉजीटिविटी रेट घट रहा है और रिकवरी रेट बढ़ रहा है।

जानकारी के अनुसार, पीएम केयर्स फंड से 58 हजार 850 वेंटिलेटर्स खरीदने के ऑर्डर दिए गए थे। जिसमें से 2,000 करोड़ रुपए के 50,000 वेंटिलेटर्स की सप्लाई सरकार के पास पहुंची। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर शुरू होते ही केंद्र ने राज्यों को वेंटिलेटर्स की सप्लाई दी। लेकिन बिहार, उप्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्यों के कई अस्पतालों में पीएम केयर्स के वेंटिलेटर धूल खा रहे हैं। वहीं जिन राज्यों में इनका उपयोग शुरू किया गया है वहां अधिकांश काम नहीं कर रहे हैं। दिल्ली, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पहुंचे वेंटिलेटर्स जब खराब निकले तो तीनों राज्यों ने इसको लेकर आवाज उठानी शुरू कर दी। ये

आवाजें उस समय उठी जब देश में कोरोना संक्रमित मरीज वेंटिलेटर के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। मामले के तूल पकड़ने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सक्रिय हुए हैं। उन्होंने अफसरों से पूरे मामले की ऑडिट रिपोर्ट मांगी है।

केंद्र सरकार ने दावा किया है कि पीएम केयर्स से 50,000 वेंटिलेटर खरीदे गए हैं। जबकि सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी में बताया गया है कि 58,850 में से 30,000 वेंटिलेटर्स ही खरीदे गए हैं। 18 मई 2020 को प्रधानमंत्री के सलाहकार भास्कर कुल्बे ने स्वास्थ्य मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी जिसमें पीएम केयर्स फंड से 2,000 करोड़ की रकम से 50 हजार मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स का ऑर्डर दिए जाने की जानकारी दी थी। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मार्च महीने के अंत में ही वेंटिलेटर खरीदने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी थी। 5 मार्च 2020 को स्वास्थ्य मंत्रालय के उद्यम एचएलएल ने वेंटिलेटर्स की सप्लाई के लिए एक टेंडर निकाला। इसमें एचएलएल ने टेक्निकल फीचर्स की लिस्ट जारी की जो इन वेंटिलेटर में होनी चाहिए। इस लिस्ट को समय-समय पर बदला गया और कुल 9 बार संशोधन किए गए। 18 अप्रैल 2020 को नौवीं बार कुछ नए फीचर जोड़े गए यानी कंपनियों को दिए गए फीचर्स में बदलाव होता रहा। बिहार, राजस्थान, उप्र, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पीएम केयर्स फंड के तहत मिले वेंटिलेटर्स का हाल जानने के लिए कुछ अस्पतालों से संपर्क किया गया तो ज्यादातर अस्पतालों से पता चला कि या तो ये वेंटिलेटर अब तक इंस्टॉल ही नहीं हुए हैं, या स्टाफ की जरूरी ट्रेनिंग तक नहीं हुई है। जहां ये इंस्टॉल हो गए हैं और स्टाफ भी है, वहां डॉक्टरों को इसमें ऑक्सीजन को लेकर समस्याएं आ रही हैं। उप्र में पीएम केयर्स फंड से 500 से भी ज्यादा वेंटिलेटर्स दिए गए थे लेकिन ज्यादातर वेंटिलेटर आज भी अस्पतालों में पड़े हैं और मरीज वेंटिलेटर्स के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। पटना के एम्स को छोड़कर राज्य के लगभग सभी सरकारी अस्पतालों में पीएम केयर्स फंड के तहत मिले ये वेंटिलेटर्स अभी तक चालू भी नहीं हो पाए हैं। कहीं स्टाफ की कमी का हवाला दिया जा रहा है तो कहीं वेंटिलेटर चलाने के लिए संसाधन की कमी का। राजस्थान को पीएम केयर्स फंड से करीब डेढ़ हजार वेंटिलेटर बीते साल मिले। लेकिन अभी तक कई जगह यह वेंटिलेटर इंस्टॉल तक नहीं हुए हैं जबकि अधिकतर जगह से इनमें सॉफ्टवेयर, प्रेशर ड्राप, कुछ समय बाद खुद-ब-खुद बंद होने समेत कई शिकायतें सामने आ रही हैं।

दूसरी लहर से सीखने होंगे सबक

देश में ऑक्सीजन संकट में कई महत्वपूर्ण सबक छिपे हैं। सबसे पहला तो यही है कि समस्या की पहचान हो गई। किसी जीवनरक्षक उत्पाद की मांग और आपूर्ति का बड़ा अंतर निश्चित तौर पर हर राज्य में राष्ट्रीय आपदा की तरह है। फिर भी, इसे चिकित्सकीय संकट की तरह देखा गया, जिससे निपटने का जिम्मा केंद्र और राज्य सरकारों के स्वास्थ्य मंत्रालयों पर छोड़ दिया गया और अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाना वेंडरों के जिम्मे रह गया। बदतर यह रहा कि कोई रीयल टाइम केंद्रीकृत व्यवस्था या ऑक्सीजन के देशभर में ढुलाई की बेरोकटोक सुविधा की निगरानी का कोई रीयल टाइम डैशबोर्ड उपलब्ध नहीं है। जरूरत थी कि देशभर में आपूर्ति के लिए एक व्यक्ति समन्वय का काम करता और इस काम में नौकरशाही को पीछे रखा जाता। 26 अप्रैल को पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश ने एक गंभीर राष्ट्रीय आपातकाल की चेतावनी दी और कहा कि सेना को बुला लेना चाहिए। वे दिसंबर, 2004 में हिंद महासागर में आई सूनामी आपदा के राहत कार्य की निगरानी कर चुके हैं। एक ट्वीट में उन्होंने सुझाव दिया कि किसी तीन सितारा अधिकारी के तहत ऑपरेशन सेंटर बनाया जाए, जिसमें सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा को समूचे देश की स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी सौंपी जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री को संसाधन प्रबंधन, आवंटन और सैन्यकर्मियों के इस्तेमाल का सुझाव दिया। विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर ऑक्सीजन की आपूर्ति को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया जाता तो इसे लेकर प्रोटोकॉल के अलग कायदे तय हो जाते।

कृषि उत्पादों के निर्यात की जरूरत

पिछले एक वर्ष से अधिक समय के दौरान देश में कोरोना महामारी के चलते आर्थिक क्षेत्र के लगभग समस्त खंड विपरीत रूप से प्रभावित हुए हैं। सेवा (पर्यटन, होटल, यातायात, आदि) एवं उद्योग क्षेत्र तो विशेष रूप से अधिक प्रभावित हुए हैं। परंतु, केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को विकसित करने के उद्देश्य से मिशन मोड में लगातार किए जा रहे प्रयासों के कारण कृषि क्षेत्र कोरोनाकाल के बीच भी विपरीत रूप से प्रभावित नहीं हुआ है। कृषि क्षेत्र में न केवल उत्पादन में लगातार वृद्धि दृष्टिगोचर है बल्कि कृषि उत्पादों का निर्यात भी लगातार प्रभावशाली तरीके से बढ़ता जा रहा है। हाल ही में जारी किए गए, कृषि क्षेत्र से हो रहे निर्यात से संबंधित आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के दौरान कृषि उत्पादों का निर्यात 2.74 लाख करोड़ रुपए का रहा है, जो अप्रैल 2019 से फरवरी 2020 के दौरान 2.31 लाख करोड़ रुपए का रहा था। इस प्रकार कृषि उत्पादों के निर्यात में वर्ष 2020-21 (अप्रैल-फरवरी) के बीच 18.49 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। विशेष रूप से गेहूं, चावल, अन्य अनाज, सोयामील, मसाले, चीनी, कपास, ताजी सब्जियां, संसाधित सब्जियां एवं एल्कोहोलिक पेय पदार्थ के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

कृषि के क्षेत्र में भारतीय किसानों ने अपनी मेहनत के बल पर एवं सरकारी नीतियों को लागू करते हुए, कृषि उत्पादों की पैदावार को मांग की तुलना में आपूर्ति अधिक की श्रेणी में ला खड़ा किया है। अब भारतीय कृषि क्षेत्र में उत्पादों की पैदावार में आधिक्य रहने लगा है और देश के किसान लगातार साल दर साल बहुत अच्छा उत्पादन करते दिख रहे हैं। विशेष रूप से सरकारी नीतियां एवं उत्पादकता में हो रही वृद्धि भी इस बढ़ती पैदावार में अहम भूमिका अदा कर रही है। भारत में कोरोना महामारी का कृषि क्षेत्र पर लगभग नगण्य प्रभाव पड़ा है। हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों ने बागवानी की पैदावार में गुणवत्ता की दृष्टि से बहुत विकास किया है। इन राज्यों से बागवानी से हुई पैदावार का बहुत निर्यात हो रहा है, विशेष रूप से दुबई आदि देशों को। विशेष रूप से फल एवं सब्जियां बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, अतः इनके भंडारण के लिए बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है ताकि इन पदार्थों का उचित भंडारण किया जा सके। आगे आने वाले 5 से 10 वर्षों में भारत कृषि उत्पादों के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर एक मुख्य निर्यातक देश बन सकता है। अब तो देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी होने लगी है। इससे भी कृषि उत्पादन में बहुत फर्क पड़ने वाला है।

भौगोलिक संकेत (जीओग्राफी इंडिकेशन-जीआई टैग) योजना का भी कृषि उत्पादन बढ़ाने में बहुत योगदान रहा है। इस योजना के अंतर्गत एक विशेष क्षेत्र में, उसके मौसम को देखते हुए, एक विशेष उत्पाद की पैदावार को बढ़ावा दिया जाता है। जिसके कारण उस उत्पाद की उत्पादकता बहुत बढ़ जाती है। बासमती चावल इसी प्रकार का उत्पाद है। विदेशों से आने वाले सैलानी भी भारत के विशेष उत्पादों को खरीदना चाहते हैं। जीआई टैग इसमें मुख्य भूमिका निभाता है। इससे भारतीय उत्पादों में अन्य देशों का विश्वास बढ़ता है और देश के लिए निर्यात बढ़ाने में भी इसकी भूमिका बढ़ जाती है।

केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं कृषि संस्थानों ने कृषि के क्षेत्र को कई तरह के प्रोत्साहन उपलब्ध कराए हैं। इसके लिए विशेष रूप से कई नई योजनाएं भी लागू की गई हैं। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में बहुत सुधार किया गया है, जिसके चलते भी विदेशों में भारतीय कृषि उत्पादों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना महामारी के दौरान कृषि मजदूरों का भी विशेष ध्यान रखा गया, जिसके चलते कृषि पैदावार में वृद्धि हो पाई है। यह पता करने के लिए कि किन-किन देशों में किस-किस कृषि उत्पाद की कमी है, विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों की भी मदद ली गई है, ताकि इन देशों को कृषि उत्पाद भारत से उपलब्ध कराए जा सकें। कृषि उत्पादों की मार्केटिंग एवं निर्यात के लिए संपर्क तंत्र को मजबूती प्रदान की गई। कृषि उत्पाद के विदेशी खरीदारों एवं भारत के किसानों की आपस में मीटिंग कराई गई। इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है ताकि क्रेता एवं विक्रेता सीधे ही एक-दूसरे से माल खरीद एवं बेच सकें। इस संदर्भ में किसानों ने भी कम मेहनत नहीं की है। आत्मनिर्भर भारत, वोकल फोर लोकल एंड लोकल से ग्लोबल, जैसे नारों ने भी देश से कृषि उत्पादों के निर्यात में लगातार हो रही वृद्धि में अपनी अहम भूमिका अदा की है। अब तो दक्षिणी अमेरिकी देशों एवं अमेरिका को भी कृषि उत्पादों का निर्यात किया जाने लगा है। अफ्रीकी देशों को भी कृषि उत्पादों के निर्यात में लगातार वृद्धि हो रही है। उच्च मूल्य वाले कृषि उत्पादों का भी निर्यात अब तेजी से बढ़ रहा है जैसे आम, अंगूर आदि पदार्थ यूरोपीयन देशों एवं अमेरिका को निर्यात किए जा रहे हैं। अंगूर का निर्यात हाल ही में शुरू किया गया है। जापान, दक्षिणी कोरिया जैसे देशों में भी अब भारतीय कृषि उत्पादों के प्रति रुझान बढ़ रहा है।

● **प्रवीण कुमार**

भारत के अनाज की मांग तेजी से बढ़ी

भारत, भौगोलिक दृष्टि से एक बड़ा देश है एवं भारत में अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग मौसमी परिस्थितियां हैं जिसके कारण बहुत अलग-अलग किस्म के कृषि उत्पाद भरपूर मात्रा में पैदा किए जा सकते हैं। अपने देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए शेष आधिक्य का देश से निर्यात आसानी से किया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार ही अब देश में कृषि उत्पादों की पैदावार ली जा रही है। बासमती चावल की मांग इसी कारण से विदेशों में लगातार बढ़ती जा रही है और इसका निर्यात भी बढ़ता जा रहा है। भारत में उत्पादित अनाज की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। समुद्रीय उत्पादों की मांग भी बढ़ती जा रही है। देश में उत्पादकता बढ़ रही है, जिसके कारण उत्पादन बढ़ रहा है। 16 राज्यों ने कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं बनाई हैं। आंध्र प्रदेश ने केला का निर्यात बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं बनाई हैं। उप्र सरकार ने भी आम, अन्य फलों एवं सब्जियों के निर्यात को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। कृषि निर्यात नीतियों को राज्य स्तर पर बनाने का भी फायदा हुआ है।

ममता पर दांव लगाने का वक्त

नरेंद्र मोदी और भाजपा की विजयी अभियान को रोकने के लिए विपक्ष को ममता बनर्जी के रूप में एक ऐसा चेहरा मिल गया है, जिस पर 2024 के लोकसभा चुनाव में दांव लगाया जा सकता है।

5 राज्यों में संपन्न विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जिस तामझाम और दल-बल के साथ बंगाल चुनाव लड़ा था उसके अनुसार परिणाम नहीं मिले। यानी भाजपा की रणनीति और नीति पर ममता बनर्जी हावी रहीं। ऐसे में बंगाल चुनाव परिणाम ने विपक्ष को इसका संकेत दिया है कि अगर नरेंद्र मोदी और भाजपा के विजयी अभियान पर विराम लगाना है तो ममता बनर्जी को महागठबंधन का नेता बनाकर उन पर दांव लगाया जाए। सोनिया गांधी जितनी जल्दी सच का सामना कर लें, कांग्रेस का भी कल्याण होगा और राहुल गांधी का भी, क्योंकि ममता बनर्जी देश की राजनीति में आज हैं तो राहुल गांधी कल। कल से आशय यहां भविष्य से ही है क्योंकि राहुल गांधी के आज से बेहतर बीता हुआ कल ही था। राहुल गांधी का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2009 के आमचुनाव में ही देखने को मिला है - जब उप्र में वो कांग्रेस की सीटें बढ़ाकर समाजवादी पार्टी और बसपा के करीब ला खड़ा किए थे। बाद में तो हार का ही ठप्पा लगता गया और ये सिलसिला हाल के विधानसभा चुनावों में भी थम नहीं सका।

सोनिया गांधी ने एक समझदारी जरूर दिखाई कि जी-23 की तरफ से कोई कड़ी टिप्पणी आने से पहले ही विधानसभा चुनावों में हार पर अपनी बात कह दी। सोनिया गांधी ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बहुत ही बुरी हार को अप्रत्याशित बताया है। समझा जाए तो सोनिया गांधी को ऐसी उम्मीद नहीं थी। तमिलनाडु में तो कांग्रेस का प्रदर्शन कोई बुरा नहीं लगता, लेकिन केरल में अपनी सरकार बनाने की उम्मीद जरूर रही होगी। केरल में सत्ता परिवर्तन की उम्मीद थी और कांग्रेस को लग रहा होगा कि भाजपा को तो वो पछाड़ ही देगी। असम में राहुल गांधी से भी ज्यादा तो प्रियंका गांधी ने मेहनत की, लेकिन सारा एक्सपेरिमेंट फेल रहा। मुश्किल ये है कि राहुल गांधी की तरह प्रियंका गांधी पर भी अब नाकामी का ठप्पा बढ़ता जा रहा है। प्रियंका गांधी के लिए इससे भी बड़ी नाकामी क्या होगी कि पूर्वी उप्र की प्रभारी होते हुए भी वो अमेठी में राहुल गांधी की हार नहीं टाल सकीं। अगर राहुल गांधी भी ममता बनर्जी की तरह एक ही सीट से चुनाव लड़ने की जिद किए होते तो क्या हाल होता। ममता बनर्जी ने तो पार्टी को जिताने के लिए ही खुद की हार का सबसे बड़ा जोखिम उठाया था। वरना, पहली बार में ही सोमनाथ मुखर्जी जैसे दिग्गज को शिकस्त देने वाली ममता बनर्जी भला नंदीग्राम में अपनी हार का सबसे बड़ा रिस्क क्यों लेतीं?

ममता बनर्जी ने नंदीग्राम हारकर एक पैर से बंगाल ही नहीं जीता है, दोनों पैरों से दिल्ली जीतने की तरफ भी जल्दी ही रफ्तार भरने की तैयारी कर रही होंगी। देखा जाए तो ममता बनर्जी भी उसी मोड़ पर आ खड़ी हुई हैं, जिस पर 2015 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खड़े थे और राष्ट्रीय स्तर पर वो भी तब नए सिरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन ममता बनर्जी और नीतीश कुमार की राजनीति में बड़ा ही बुनियादी फर्क है। नीतीश कुमार वो मुकाम आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाने के बाद ही हासिल कर पाए थे, लेकिन ममता बनर्जी ने उन्हीं मोदी और अमित शाह को अकेले शिकस्त दी है। ममता बनर्जी का साथ जिसे छोड़ना था, पहले ही छोड़ चुका है। फिलहाल तो ममता बनर्जी को नीतीश कुमार जैसा टेंशन कतई नहीं है, जैसा वो लालू प्रसाद और महागठबंधन छोड़ने से 10-20 बार पहले जरूर सोचे होंगे। अब ममता बनर्जी को वही छोड़ सकता है जिसे खुद कोई बड़ा लालच न हो या फिर कोई उसे दिला पाए।

देश के मौजूदा राजनीतिक हालात और उसमें कांग्रेस की हैसियत को देखें तो सोनिया गांधी के सामने गिने चुने विकल्प ही बचे हैं। पहले तो कांग्रेस को बनाए रखने या अस्तित्व बचाए रखने के लिए जरूरी हो गया है कि एक फुलटाइम अध्यक्ष का इंतजाम किया जाए। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी तक राहुल गांधी ने अपनी तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया है कि वो फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हैं। हालांकि, विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस की तरफ से यही समझाने की कोशिश हो रही थी कि राहुल गांधी ही फिर से कमान संभालेंगे, भले ही ऐसी खबरें कांग्रेस के सूत्रों की तरफ से लीक की जा रही हों।

मान भी लेते हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया चल रही है तो उसके नतीजे भी देर सवेर आ ही जाएंगे। ये भी मान लेते हैं कि कांग्रेस फिर से राहुल गांधी को ही चुन भी लेती है तो वो फुलटाइम अध्यक्ष भी बन जाएंगे और ये भी मान लेते हैं कि कांग्रेस में सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वाले नेताओं की अपेक्षा के अनुरूप राहुल गांधी बतौर अध्यक्ष काम करते

ममता या अब भी शरद पवार

कुछ दिन पहले शिवसेना की तरफ से शरद पवार को लेकर एक अभियान चलाया जा रहा था, शरद पवार को यूपीए का चेयरमैन बनाए जाने को लेकर। भले ही ये पूरे शिवसेना के मन की बात न हो, लेकिन संजय राउत के प्रवक्ता होने के नाते ऐसे बयान को महत्वपूर्ण तो माना ही जा सकता है। बातों-बातों में ही संजय राउत ने ये भी बता डाला था कि यूपीए तो अब किसी एनजीओ जैसा हो गया है और एक सवाल ये भी कि मौजूदा दौर के सारे क्षेत्रीय और मजबूत नेता तो यूपीए से बाहर ही हैं। शुरू से ही यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ही हैं। हालांकि, माना जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसी और को सौंप देने के बाद वो यूपीए के नेतृत्व से भी खुद को अलग कर लेना चाहेंगी और शिवसेना की तरफ यही सोचकर शरद पवार के नाम पर जनमत जुटाने का काम होने लगा था।

माकपा के नेता अपनी गलत नीतियों से पार्टी को मटियामेट कर देंगे?

यदि कोई पार्टी अपनी गलतियों को जान-समझ ले, उन्हें सार्वजनिक तौर पर स्वीकार भी कर ले, फिर भी उन्हें सुधारने की कोई गंभीर कोशिश न करे तो उसका क्या हश्र होगा? वही होगा जो सीपीएम यानी माकपा का बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार हुआ। उसे एक भी सीट नहीं मिली। कांग्रेस भी खाली हाथ रही। कांग्रेस को माकपा के हश्र से सबक लेना चाहिए। माकपा और कांग्रेस के कुछ नेतागण अपनी गलत नीतियों के कारण एक दिन पार्टी को मटियामेट कर देंगे, क्या यह कभी किसी ने सोचा भी था? अब बंगाल में राजनीति और चुनाव के मुद्दे बदल चुके हैं। देशहित और प्रदेशहित के उन मुद्दों पर मौजूदा पक्ष और विपक्ष में मजबूती से अड़े रहने वाले दो मजबूत राजनीतिक दल अब आमने-सामने हैं। बंगाल में तीसरे दल के लिए फिलहाल कोई जगह नहीं नजर आती।

हुए दिखेंगे भी, लेकिन इससे क्या और कितना कुछ हो पाएगा। क्या राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस चुनाव जीतकर बना हुआ अध्यक्ष घोषित कर दे तो आने वालें चुनावों के नतीजों में फर्क आ जाएगा? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों का इम्तिहान अगले ही साल होने वाला है, जब 2022 में ही उप्र और पंजाब से लेकर गुजरात और हिमाचल प्रदेश तक की विधानसभाओं के लिए चुनाव होने हैं।

गुजरात और हिमाचल भूल भी जाएं तो पंजाब की भी कोई टेंशन नहीं है। पंजाब में जीत हो या हार, जो भी होना होगा मौजूदा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर ही निर्भर करेगा। सुरक्षा पेटी के तौर पर अमरिंदर सिंह ने पहले से ही प्रशांत किशोर को बांध ही लिया है, एक रुपए की तनख्वाह पर। वैसे प्रशांत किशोर का कहना है कि पश्चिम बंगाल के बाद वो इलेक्शन कैंपेन का काम नहीं करेंगे। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान उप्र चुनाव होगा। हालांकि, उसे पहले से ही प्रियंका गांधी के सिर पर डालकर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ताकि किसी भी नुकसान के लिए ठीकरा उनके सिर फोड़कर राहुल गांधी को एक और हार से बचा लिया जाए। क्या सोनिया गांधी ने कभी सोचा होगा, अगर कांग्रेस ही नहीं रहेगी तो राहुल गांधी को कौन पूछेगा? अगर राहुल गांधी के नाम में गांधी नहीं जुड़ा होता तो क्या वो ममता बनर्जी और शरद पवार की तरह कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाकर मुख्यधारा की राजनीति में कहीं टिक पाते?

वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से ही ममता बनर्जी यह समझ चुकी थीं कि उनकी आगे की राह आसान नहीं है। नरेंद्र मोदी के जादू से ममता सदमे में थीं। बंगाल में भाजपा मजबूती से पैठ बना चुकी थी। भाजपा का वोट शेयर तृणमूल से महज तीन प्रतिशत ही कम रह गया था। भाजपा के सीटों की संख्या दो से बढ़कर 18 पहुंच गई थी तो वहीं ममता की सीटें 34 से घटकर 22 पर अटक गई थी। आइपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के बंगाल में प्रवेश के लिए यह समय सही था। आइपैक के मुखिया पीके यानी प्रशांत किशोर की मीटिंग ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ हुई। ममता बनर्जी ने पीके को चुनाव रणनीतिकार के तौर पर स्वीकार किया। इस बीच पीके की टीम ने बंगाल के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की जमीनी हालात का जायजा लिया और ममता बनर्जी को जमीनी सच से अवगत कराया। ममता ने कमजोर कड़ी को दुरुस्त करना शुरू किया।

बंगाल के लिए आइपैक के करीब 1,600 कर्मचारियों ने चुनाव मैदान में मोर्चा संभाल लिया। हर विधानसभा में प्रत्यक्ष तौर पर चार-चार आदमी पदस्थापित किए गए। इसके अलावा 400 लोग मॉनीटरिंग के लिए नियुक्त किए गए। हालांकि विधानसभा स्तर पर काम करने वाले वॉलेंटियर कहलाते हैं। दो वॉलेंटियर का काम केवल वाट्सएप ग्रुप बनाना था और विधानसभा क्षेत्र के नए लोगों को जोड़ना था। हर विधानसभा में दो आइपैक के कर्मचारी स्थायी तौर पर नियुक्त किए गए। सबसे ऊपर लीडरशीप टीम होती है, जिसे एलटी कहा जाता है। एलटी में चार लोग होते हैं, जिनकी ज्यादातर मीटिंग बेहद गोपनीय होती है। इसमें चार लोगों के अलावा आइपैक के निदेशक शामिल होते हैं। ऐसी ज्यादातर मीटिंग में पीके खुद भी मौजूद होते हैं। गोपनीय बैठकों में सरकारी योजनाओं के अमल, मतदान के रुझान, मतों के ध्रुवीकरण, जातीय समीकरण सहित तमाम मसलों पर चिंतन-मंथन होता है, रणनीति तय की जाती है। इसके नीचे आते हैं ईसी मेंबर। इलेक्शनरी काउंसिल में 18 से 20 लोग होते हैं। पीआईयू यानी पॉलिटिकल इंटेलिजेंस यूनिट, डीटी यानी डिजिटल टीम जैसी कई अलग-अलग टीमें भी होती हैं।

कोरोना के साये में पुडुचेरी और चार राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम कांग्रेस के लिए निराशाजनक हैं। असम (एनडीए), पश्चिम बंगाल (टीएमसी) और केरल (एलडीएफ) में सत्ताधारी सफल रहे, जबकि तमिलनाडु (डीएमके) और पुडुचेरी (एनडीए) में विपक्ष ने सत्ता परिवर्तन किया। इन परिणामों में कांग्रेस कहीं मुकाबले में नहीं दिखी। असम में एआईयूडीएफ और बीपीएफ के साथ मजबूत गठबंधन और सीएए विरोध के बावजूद भाजपा को सत्ता से बेदखल नहीं कर सकी। कांग्रेस का सबसे ज्यादा नुकसान पश्चिम बंगाल में हुआ, जहां वह अपनी 44 में से उन 32 सीटों को भी नहीं बचा सकी, जो 2006 से उसके कब्जे में थीं। कांग्रेस यहां शून्य तक गिरकर विधानसभा से बाहर हो चुकी है। कांग्रेस चाहे तो तमिलनाडु से सांत्वना ले सकती है, जहां वह द्रमुक के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शुमार है। हालांकि डीएमके की सियासी ताकत के आगे कांग्रेस की स्थिति बेहद कमजोर है। आखिर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के साथ ऐसा क्यों हुआ। पिछले कुछ चुनावों से देखने में आया है कि आमतौर पर कांग्रेस गठबंधन में कमजोर सहयोगी रही है। कांग्रेस की सफलता की दर असम और केरल में 27-27 प्रतिशत रही है, जो अपने सहयोगियों एआईयूडीएफ (80 प्रतिशत) और आईयूएमएल (64 प्रतिशत) की तुलना में बेहद कम है। राष्ट्रीय पार्टी होने के चलते कांग्रेस अधिक सीटों की मांग करती है, लेकिन प्रदर्शन कमजोर होने से वह गठबंधन में महत्वहीन हो जाती है। ऐसे में मतदाता का भरोसा भी कम होता जाता है।

● **रजनीकांत पारे**

भाजपा बंगाल, केरल, तमिलनाडु जैसे सांस्कृतिक भाषाई और क्षेत्रीय पहचान वाले राज्यों में उदारवादी हिंदुत्व के जरिए ही पैठ बना सकती है। प्रारंभिक दौर में इसकी बुनियाद संघ जैसा सामाजिक संगठन ही रख सकता है। लोगों के मुद्दे समय के साथ बदलते भी हैं।

बंगाल से सबक

पश्चिम बंगाल की हार के बाद भाजपा को यह समझना होगा कि मजबूत सांस्कृतिक, भाषाई और क्षेत्रीय पहचान रखने वाले समाजों में धार्मिक प्रतिबद्धता का स्वरूप बदलता जाता है। लिहाजा जय श्रीराम का जो चुनावी घोष उत्तर भारत के राज्यों खासकर उप्र, बिहार, राजस्थान और मप्र में असर रखता है, वह बंगाल और केरल, तमिलनाडु सहित कई राज्यों में प्रभावी नहीं। बंगाल जनादेश के विश्लेषण से स्पष्ट दिखेगा कि ऐसे राज्यों में राजनीतिक पैठ तब तक नहीं होगी, जब तक सामाजिक स्तर पर पार्टी उस समाज में दूध-पानी की तरह नहीं मिलेगी। बंगाल में तोलाबाजी (तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उगाही) एक हकीकत और भोगा हुआ यथार्थ है, लेकिन उससे भी एंटी-इनकंबेंसी नहीं पैदा हुई, क्योंकि तृणमूल से आयातित नेताओं को चुनाव में सिरमौर बनाने से बड़ी और स्पष्ट विचारधारा वाली पार्टी के प्रति जनता की विश्वसनीयता घटी। समाज से घुलने-मिलने का काम प्रारंभिक दौर में भाजपा के बूते का नहीं। यह केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही कर सकता है। बंगाली मानुष के दुख-सुख में शामिल होना, सेवा कार्य करना, अलग-अलग सामाजिक पहचान वाले समूहों के लिए प्रकल्प बनाकर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं धार्मिक जीवन में पैठ बनाने के लिए वर्षों तक काम करना होता है। यह काम मोदी और शाह के एक दिन में कई रैलियों से नहीं होगा। यह काम स्थानीय कार्यकर्ताओं को ठुकरा कर आयातित लोगों को टिकट देने से भी नहीं होगा। इसके उलट असम एक उदाहरण है, जहां संघ के दो दशक से ज्यादा के सेवा-कार्यों का प्रतिफल था भाजपा का सत्ता में आना।

तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पार्टी ने एम वेंकैया नायडू को लगाकर कई साल तक कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। केरल में संघ प्राणपण से लगा हुआ है, लेकिन राजनीतिक लाभ मिलने में अभी काफी समय लगेगा। जब-जब वहां कट्टर हिंदूवादी छवि वाले भाजपा के नेता प्रचार में जाएंगे, ईसाई समुदाय छिटक जाएगा। करीब 80 प्रतिशत हिंदू आबादी के बावजूद देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा को पिछले आम चुनाव में लगभग 36 प्रतिशत मत मिले। 2009 तक इस पार्टी को कांग्रेस से ज्यादा वोट नहीं मिले, बल्कि 1998 के 25 प्रतिशत के बाद से 2009 तक लगातार पार्टी का मत-प्रतिशत तक घटता ही रहा। मोदी की आंधी में भी 2019 में आधे से अधिक हिंदुओं ने भाजपा को वोट नहीं दिया।

अन्य धर्मों से अलग सनातन धर्म मूल स्वरूप में उदारवादी है। इसमें आराध्य-देव की निंदा करके भी आप अनुयायी रह सकते हैं। एक आंकलन के अनुसार देश में कट्टर हिंदुओं की संख्या करीब 15-20 प्रतिशत है, शेष उदारवादी हैं। कट्टर हिंदुत्व का रूप मजबूत सांस्कृतिक पहचान वाले राज्यों में नाराजगी का कारण बनता है। बंगाल में लोकसभा चुनाव के बाद से लेकर हाल के विधानसभा चुनाव तक भाजपा ऐसी बातें करती रही कि बंगाल में भाजपा शासन आया तो लोगों को सरस्वती पूजा करने और दुर्गा मूर्ति विसर्जन की खुली छूट होगी या एक भी घुसपैठिया बचेगा नहीं। भद्रलोक ने ही नहीं, आम जनता ने भी इस ब्रांड के हिंदुत्व को पसंद नहीं किया। बंगाल विधानसभा चुनाव में अपेक्षा से कमजोर प्रदर्शन भाजपा के लिए कुछ आमूल-चूल परिवर्तन का संदेश है।

आखिर क्या वजह है कि तीन साल पहले त्रिपुरा चुनाव में जीत के बाद से लगातार इस पार्टी का विधानसभा चुनावों में प्रदर्शन खराब होता जा रहा है? झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली इसके उदाहरण हैं, जबकि मप्र, छत्तीसगढ़ में जहां पार्टी शासन में थी, वहां भी स्थिति उत्साहवर्धक नहीं रही। बिहार में उसने जैसे-तैसे अपनी प्रतिष्ठा बचाई। अगर दो साल पहले बंगाल में लोकसभा चुनाव में पार्टी करीब

भाजपा की राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति बढ़ी

5 राज्यों के चुनाव परिणामों से कुछ प्रवृत्तियां रेखांकित की जा सकती हैं। एक, भाजपा की राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति बढ़ी है, खासतौर पर बंगाल, केरल और केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में, जहां कांग्रेस को विस्थापित कर राजग सत्ता में आता दिख रहा है। दूसरे, क्षेत्रीय पार्टियां अपने-अपने राज्यों में काफी मजबूत हैं और विधानसभा चुनावों में राज्य का मतदाता उन्हें राष्ट्रीय पार्टियों से ज्यादा पसंद करता है। तृणमूल बंगाल में, द्रमुक और अन्नाद्रमुक तमिलनाडु में सशक्त हैं और राष्ट्रीय पार्टियों को वहां प्रवेश करने में कड़ी स्पर्धा करनी पड़ती है। शायद इसीलिए भाजपा छोटे-छोटे क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करने से परहेज नहीं करती। असम और पुडुचेरी में भाजपा ने यही किया है। तीसरी, महिलाओं का रुझान भाजपा की ओर बढ़ा है और वे जाति-धर्म से ऊपर उठ एक वर्ग के रूप में वोट देने लगीं हैं। संभवतः मोदी के विकास मॉडल में जातियों के प्रभाव को कम करने का बीज है। महिला राजनीतिक सशक्तिकरण में मोदी ने आर्थिक सशक्तिकरण का तड़का लगा दिया है।

120 विधानसभा सीटों पर अपनी बढ़त दर्ज कर 18 सीटें जीतती है तो ताजा चुनाव में क्यों वोट डालने गए हर दूसरे वोटर की पसंद ममता बनर्जी बन जाती हैं? हर चुनाव के पहले तथाकथित चुनाव सर्वे की संस्थाएं अपनी दुकान सजाकर बैठ जाती हैं। उन्हीं के आधार पर हम यह मान बैठते हैं कि कौन जीतेगा और कौन नहीं? बंगाल का उदाहरण लें। अनेक सर्वे में प्रतिशत देकर कहा गया कि तृणमूल कैडर के भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है और उद्योगों में निवेश न होने से जबरदस्त बेरोजगारी है। यह भी कहा गया कि मोदी की उज्ज्वला योजना की महिलाओं में पैठ है, बिगड़ती कानून-व्यवस्था से महिलाओं में डर है और ममता के मुस्लिम-मोह से हिंदुओं में नाराजगी है, लेकिन शायद भारत में चुनाव सर्वेक्षण के सही होने में अभी कई दशक लगेंगे। सर्वेक्षक हकीकत से कोसों दूर रहते हैं। बंगाल में कोई नहीं बता पाया कि दस साल के शासन के बाद सत्ताधारी दल लगभग तीन चौथाई सीटें हासिल कर लेगा। तृणमूल के पक्ष में चुनाव परिणाम एक आंधी को बयान करने वाला रहा।

राजनीतिशास्त्र में जो लोकमत को प्रभावित करने वाले मुद्दे माने जाते हैं, वे भारत में सही नहीं उतरते। प्रजातंत्र में औसत नागरिकों के मुद्दे समय के साथ बदलते भी हैं। आक्रामक हिंदुत्व का रूप उप्र और बिहार में जोरशोर से चलता है, क्योंकि वहां क्रमशः 19 और 17 प्रतिशत अल्पसंख्यक हैं और सांप्रदायिक तनाव का इतिहास और वर्तमान भी रहा है। इसकी जरूरत गुजरात, राजस्थान, मप्र, उत्तराखंड या पंजाब, छत्तीसगढ़, आंध्र आदि में नहीं है। भाजपा बंगाल, केरल, तमिलनाडु जैसे सांस्कृतिक, भाषाई और क्षेत्रीय पहचान वाले राज्यों में उदारवादी हिंदुत्व के जरिए ही पैठ बना सकती है। प्रारंभिक दौर में इसकी बुनियाद संघ जैसा सामाजिक संगठन ही रख सकता है।

असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी विधानसभा के बहुप्रतीक्षित चुनाव परिणाम आ गए। असम में भाजपा, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और केरल में वाम मोर्चा की सत्ता में वापसी हुई, जबकि तमिलनाडु और पुडुचेरी में सत्ता परिवर्तन हुआ। केरल में 40 वर्षों से वामपंथी-एलडीएफ और कांग्रेसी-यूडीएफ के बारी-बारी से जीतने का क्रम मुख्यमंत्री पी विजयन ने तोड़ दिया। कोविड आपदा के कारण निर्वाचन आयोग के लिए चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण था, पर अपनी कर्मठता और अनुभव से उसने आपदा पर लोकतंत्र की विजय सुनिश्चित की। असम में भाजपा की वापसी काफी अहम है, क्योंकि नागरिकता कानून पर वह रक्षात्मक थी। भाजपा, असम गण परिषद और बोडो समर्थित यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी-लिबरल का गठबंधन बने रहने और कांग्रेस द्वारा सांप्रदायिक यूडीएफ से हाथ मिलाने और बदरुद्दीन अजमल को असम का चेहरा बनाने से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तय हो गया। बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिमों की संख्या बढ़ने से असम के मतदाता चिंतित हैं। करीब 82 प्रतिशत मतदान इस चिंता का संकेतक था। असम में हिमंता बिस्वा सरमा और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल का विकास मॉडल भी प्रभावी रहा। भाजपा को असमिया मुसलमानों का भी समर्थन मिला, जो वहां के बांग्लादेशी मुसलमानों से चिढ़ते हैं।

बंगाल में तृणमूल की तीसरी बार सरकार बनना अभूतपूर्व है। पार्टी ने वहां अपना जनाधार भी बढ़ाया। भाजपा भले ही वहां अपेक्षित विजय न हासिल कर सकी हो, पर 2016 में तीन सीटों और 10 फीसद वोट से लगभग 75 सीटें और करीब 40 प्रतिशत वोट प्राप्त करना भी सराहनीय है। इसकी शुरुआत 2019 के लोकसभा चुनावों से हो गई थी, जिसमें उसे 40 फीसदी से अधिक वोट और 18 सीटें मिली थीं। इसका कारण था बड़ी संख्या में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का तृणमूल से छिटककर भाजपा में आना। भाजपा ने बंगाल में अपने संगठन, कैडर और विचारधारा को विस्तार तो दिया, पर इतना नहीं कि सत्ता प्राप्त कर सके। फिर भी बंगाल को उसके रूप में एक सशक्त विपक्ष मिला है, जो लोकतंत्र के लिए जरूरी है। बंगाल में कांग्रेस और वामपंथ का पूर्ण सफाया हो गया। लगता है भाजपा ने उनसे उनका जनाधार छीन लिया।

केरल वामपंथ का गढ़ रहा है। स्वतंत्र भारत में प्रथम वामपंथी सरकार नंबूदरीपाद के नेतृत्व में वहीं बनी थी। पहली बार 2016 में भाजपा को एक सीट और करीब 10 प्रतिशत वोट मिले। बाद में पंचायत और नगरीय चुनावों में भी उसे सफलता मिली। भाजपा ने श्रीधरन को चेहरा बनाकर महिला सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर विधानसभा चुनाव लड़ा। केरल में एलडीएफ की वापसी वास्तव में मुख्यमंत्री विजयन की जीत है, जिन्होंने कोविड आपदा का अच्छा प्रबंधन किया। कांग्रेस ने राहुल और प्रियंका के अलावा शशि थरूर को एक बड़े नेता के रूप में प्रयोग किया, पर उसका दुर्भाग्य कि इस बार उसका टर्न होने के बावजूद उसे सत्ता न मिल सकी। भाजपा को दक्षिणी राज्यों और खासकर केरल में सफलता के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी।

● इंद्र कुमार

सभी मोदी सरकार से लड़ने में लगे

अमेरिका जैसे विकसित देश में अभी तक भारत से तीन गुना ज्यादा लोग कोविड महामारी से मर चुके हैं, लेकिन वहां विपक्षी दल, मीडिया या न्यायपालिका ने उसका ठीकरा सरकार पर नहीं फोड़ा। यहां आपदा से लड़ने के बजाय सभी मोदी सरकार से लड़ने में लगे हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि में में गृह और वित्तमंत्री रहे चिदंबरम ने कोविड आपदा प्रबंधन पर मोदी सरकार के विरुद्ध जनता से विद्रोह की अपील की? क्या यह लोकतंत्र में आस्था का प्रतीक है? इन चुनावों में कांग्रेस का जैसे और ह्रास हो गया है। पुडुचेरी और केरल में जहां इस बार उसकी सरकार बननी चाहिए थी, वहां भी उसे शिकस्त मिली। बंगाल से तो जैसे नामोनिशान ही मिट गया और असम में भी उसे घोर निराशा मिली। इसके बावजूद कांग्रेस नेतृत्व और संगठन को लेकर हठधर्मिता अपनाए हुए है। अंतिम प्रवृत्ति चुनाव आयोग पर आरोप लगाने को लेकर है। नेताओं और दलों द्वारा उस पर लांछन लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। एक हाईकोर्ट द्वारा भी आयोग पर कठोर टिप्पणियां की गईं। आयोग के पास नेताओं और पार्टी-कार्यकर्ताओं की अनुचित हरकतों पर दंडात्मक कारवाई का अधिकार नहीं है। आदर्श आचार संहिता दलों की आम सहमति पर आधारित है।

शराबियों की चिंता

लॉकडाउन के दौरान शराबियों को दिक्कत न हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने शराब की ऑनलाइन डिलीवरी शुरू कर दी है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच में शराब की दुकानों पर जुटने वाली भीड़ से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है। इसे देखते हुए भूपेश बघेल ने शराब प्रेमियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था कर दी। एक घंटे के अंदर ही 50 हजार से ज्यादा लोगों ने शराब की बुकिंग करा डाली। आलम ये रहा कि लाखों लोगों के एक साथ एप का यूज करने से सर्वर क्रैश हो गया। यहां गौर करने वाली बात ये है कि छत्तीसगढ़ में एक्टिव कोरोना संक्रमितों की संख्या करीब डेढ़ लाख है। राज्य में कोरोना संक्रमण की वजह से 10 हजार से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। लेकिन, छत्तीसगढ़ सरकार का ध्यान स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को छोड़कर शराब प्रेमियों का गला तर करने में लगा है।

आदिवासी बहुल राज्य छत्तीसगढ़ की अधिकांश आबादी गांवों और जंगलों में बसे गांवो-बस्तियों में रहती है। राज्य सरकार इन गांवों में कोरोना टेस्टिंग करने के मामले में काफी पीछे है। बीते महीने केंद्र सरकार की ओर से भेजी गई एक जांच टीम ने बताया था कि छत्तीसगढ़ में कोरोना टेस्टिंग की संख्या काफी कम है। मीडिया रिपोर्ट्स में ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण के बड़े स्तर पर फैलने की खबरें आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएम सिंहदेव खुद मानते हैं कि गांवों में संक्रमण के मामले बढ़ना चिंता का विषय है। प्रदेश में लगे लॉकडाउन से शहरी क्षेत्रों में कोरोना मामलों में कमी आई है, लेकिन गांवों में संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती दिख रही है। देश के कई ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं तब भी बेहतर हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमित की तबीयत बिगड़ने पर उसे दूसरे जिले में ले जाना पड़ता है। कई मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। लेकिन, छत्तीसगढ़ सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है।

राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का आलम ये है कि विशेषज्ञ डॉक्टरों से लेकर स्टाफ नर्स तक के पद बड़ी संख्या में खाली पड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार बने हुए करीब ढाई साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इन पदों पर भर्ती नहीं की जा सकी है। राज्य में वेंटिलेटर से लेकर कोरोना इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं तक की किल्लत हो रही है। लेकिन, जिम्मेदार इस पर पिछली भाजपा सरकार को दोष देते नजर आते हैं। राज्य सरकार ने बीते महीने ही हाईकोर्ट में दावा किया था कि छत्तीसगढ़ में सुविधाओं की कमी नहीं है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन, एचडीयू, आईसीयू और वेंटिलेटर बेड बड़ी संख्या में मौजूद हैं। लेकिन, छत्तीसगढ़ में लोग अस्पताल में बेड के लिए चक्कर लगा रहे हैं और सही समय पर इलाज न मिलने से दम तोड़ रहे हैं। जीवनरक्षक दवाईयों को लेकर भी कमोबेश यही हाल बना है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के लिए शराब की ऑनलाइन डिलीवरी कराने में व्यस्त नजर आती है। छत्तीसगढ़ में लोग अस्पताल में बेड के लिए चक्कर लगा रहे हैं और सही समय पर इलाज न मिलने से दम तोड़ रहे हैं।

राज्य में कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के चलते शराब की दुकानें बंद हैं। इस दौरान 11 लोगों की मौत सैनिटाइजर और शराब में कफ सिरप मिलाकर पीने से हो गई। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री कवासी लखमा ने जहरीली शराब से हुई इन मौतों को रोकने के लिए ऑनलाइन शराब डिलीवरी की व्यवस्था शुरू करने की बात कही। लेकिन, कोरोना से हो रही मौतों पर अफसोस जताने के अलावा कुछ खास प्रयास करते नहीं दिख रहे हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में शामिल रहे थे। उन्होंने दूसरी लहर के अंदेशे के बाद भी असम के चुनाव प्रचार में कोई कमी नहीं आने दी थी। असम में चुनाव की कमान संभाल रहे भूपेश बघेल ने बीते मार्च महीने में अपने ट्विटर हैंडल से 200 से ज्यादा ट्वीट किए, जिनमें से केवल 6 में कोरोना के बारे में बात की गई थी।

लॉकडाउन में आवश्यक सेवाओं को ही छूट दी गई है और शराब से ज्यादा कुछ जरूरी हो क्या सकता है। छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिले कोरोना की मार झेल रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार कोरोना संक्रमित मरीजों की 10 हजार से ज्यादा मौतें होने के बाद प्रदेश के डेढ़ लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमितों को लेकर कुछ खास चिंतित नहीं दिखती है। लेकिन, शराब के लती 11 लोगों की मौत के बाद सरकार की ओर से ऑनलाइन डिलीवरी की व्यवस्था कर दी जाती है। मौत किसी की भी हो, चिंता का विषय है। लेकिन, शराबियों पर छत्तीसगढ़ सरकार की 'कृपादृष्टि' कहीं से भी सही नहीं लगती है। लगता है सरकार जानती है कि लोगों को दवा, राशन, वेंटिलेटर की जरूरत ही कहां है? आराम से शराब से गला गीला कीजिए और सभी चिंताओं को किनारे रखते हुए चैन की नींद सो जाइए।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

प्रवासी मजदूरों की जांच और क्वारैंटीन की नहीं की गई व्यवस्था

इस साल लॉकडाउन लगने की आशंका से वापस लौटे प्रवासी मजदूरों की पिछले साल की तरह न जांच की गई और न ही उन्हें क्वारैंटीन करने की व्यवस्था सरकार की ओर से बनाई गई। इन मजदूरों में से जो भी कोरोना संक्रमित होगा, वह दूसरों के लिए भी घातक होगा। लेकिन, सरकार अपने दावों के सहारे खुद की पीठ थपथपाने में ही व्यस्त नजर आती है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो छत्तीसगढ़ के गांवों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार 200 फीसदी से भी ज्यादा है। गांवों में बसने वाली अधिकांश आबादी कम पढ़ी-लिखी या निरक्षर है और कोरोना को लेकर जागरुकता के अभाव में 'काल का निवाला' बनती जा रही है। ये लोग जांच और टीकाकरण का विरोध कर रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार के लिए एक नई समस्या खड़ी हो रही है। राज्य सरकार ने गांवों में बिना जांच के ही लक्षणों को आधार बनाते हुए दवाईयां पहुंचाने की बात कही है, लेकिन इससे फायदा होता नहीं दिख रहा है।

जाट राजनीति गरमाई

किसान नेता राकेश टिकैत की राजस्थान में बढ़ती सक्रियता से प्रदेश के जाट नेता बेचैन हो गए। प्रदेश के जाट नेताओं का मानना है कि कृषि कानून के बहाने टिकैत राजस्थान में राजनीति की जमीन तलाश रहे हैं। अब तक उन्होंने जाट बहुल 9 जिलों में किसान महापंचायत की। टिकैट के लिए प्रदेश में राजनीति की जमीन तलाशने का काम माकपा के नेता अमराराम, जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील और गुर्जर नेता हिम्मत सिंह कर रहे हैं। राकेश टिकैत की बढ़ती सक्रियता से चिंतित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और सांसद हनुमान बेनीवाल ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बेनीवाल ने टिकैट को बाहरी करार देते हुए कहा कि वे प्रदेश में सियासी जमीन तैयार नहीं कर पाएंगे। बाहरी नेता किसानों को नहीं जुटा सकता। बेनीवाल का मानना है कि जाट बहुल नागौर जिले में हुई टिकैत की सभा में मुट्ठीभर लोग आए। अगर टिकैत किसानों में लोकप्रिय होते तो किसानों की भारी भीड़ आती।

दरअसल, नागौर बेनीवाल का संसदीय क्षेत्र है। वहां टिकैत की किसान महापंचायत से बेनीवाल को अपने राजनीतिक नुकसान का अंदाजा है। कृषि बिलों के विरोध में खुद को एनडीए छोड़ने वाले बेनीवाल को नागौर की महापंचायत में दरकिनार किए जाने से उनके समर्थक नाराज हैं। बेनीवाल, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक भरतपुर पूर्व राजपरिवार के सदस्य विश्वेंद्र सिंह का मानना है कि टिकैट प्रदेश के जाट बहुल इलाकों में अपने लिए राजनीतिक जमीन तैयार करने में जुटे हैं। इसी आशंका के चलते इन नेताओं ने टिकैत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूनिया तो पहले से ही पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर टिकैत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। वे अपने समर्थकों को किसान आंदोलन के खिलाफ माहौल तैयार करने के लिए पहले से ही कह चुके हैं।

डोटासरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की हैसियत से पार्टी के निर्देश पर किसान आंदोलन का समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन टिकैत की बढ़ती सक्रियता को पसंद भी नहीं कर रहे। इन नेताओं का मानना है कि वामपंथी दलों और जाट महासभा के सहयोग से टिकैट उनकी सियासी जमीन हथियाने की कोशिश में जुटे हैं। ये सभी अलग-अलग दलों में होने के बावजूद प्रदेश में कोई नया जाट नेता पैदा नहीं होने देना चाहते। जाट नेता विनोद चौधरी का कहना है कि टिकैत बाहरी हैं, यहां के किसान जागरूक हैं।

देश-विदेश में विख्यात किसान आंदोलन के बहाने अब नेता अपनी राजनीति चमकाने का भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत उप्र और हरियाणा के बाद अब राजस्थान में भी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। टिकैत दूसरे प्रदेशों से ज्यादा राजस्थान के जिलों में किसान महापंचायत कर रहे हैं। ताकि केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में बने माहौल का वे भी फायदा उठा सकें। टिकैत के राजस्थान में सक्रिय होने से कांग्रेस, भाजपा और थर्ड फ्रंट की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उन्हें अपनी राजनीतिक जमीन के शेयर होने का डर है। हालांकि टिकैत की इन महापंचायत में कई जगह कांग्रेस और वाम दलों के नेता भी साथ दिखे। क्योंकि राजस्थान में वैसे भी कृषि कानूनों के खिलाफ माहौल है। अखिल भारतीय किसान सभा संयुक्त यूनियन सचिव संजय माधव का कहना है कि राकेश टिकैत की महापंचायत राजनीतिक के तौर पर नहीं, यह केवल किसान आंदोलन है।

किसान आंदोलन से राजनीतिक सरोकार अब सीधे तौर पर जुड़ने लगे हैं। अभी तक भाजपा यह आरोप लगाती रही है कि किसान आंदोलन के पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ है। खैर, जो भी हो मगर ये आंदोलन चार प्रदेशों की राजनीति को एक नई करवट दिला सकता है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उप्र की राजनीति में नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं। गणतंत्र दिवस पर लाल किले में हुए उपद्रव के बाद आंदोलन को दोबारा से जीवित करने में लगे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत को लेकर भी अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वे जाट राजनीति के केंद्र में बैठना चाहते हैं। वजह, मौजूदा परिस्थितियों में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उप्र और राजस्थान के जाटों में कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है, जो सर्वमान्य नेता के तौर पर स्वीकार्य हो।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

टिकैत की नजर जाट बहुल जिलों पर

टिकैत उप्र के निकट जाट बहुल भरतपुर में गए। इसके बाद उन्होंने जाटों के प्रभाव वाले झुंझुनू, सीकर, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ और जयपुर आदि जिलों में किसान महापंचायत की। राकेश टिकैत के लिए यह सुनहरा मौका है। वे जाट राजनीति के केंद्र में खुद को स्थापित कर सकते हैं। इसका उदाहरण देखें कि 28 जनवरी को जब टिकैत ने मीडिया के सामने रोते हुए अपनी बात कही, तो उसका असर उप्र के अलावा हरियाणा के किसानों में भी देखने को मिला। रात में सोशल मीडिया पर एक विशेष समुदाय के सदस्यों के बीच जमकर संदेशों का आदान-प्रदान हुआ। ऐसे मैसेज आगे बढ़ाए गए, जिनमें लोगों से टिकैत का साथ देने के लिए धरना स्थलों पर पहुंचने की अपील की गई। जो ट्रैक्टर लाल किले की घटना के बाद वापस जाने लगे थे, टिकैत का वीडियो वायरल होने के बाद वे वापस आने लगे। प्रदेश के जाटों में टिकैत के प्रति खास सहानुभूति देखी गई। किसान आंदोलन की दिशा चाहे जो भी हो, मगर टिकैत जाट नेता के तौर उभर सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। वजह, किसान आंदोलन ने टिकैत का कद काफी बढ़ा दिया है। पहले वे उप्र के किसानों का प्रतिनिधित्व करते थे। अब उन्हें देश के किसान नेता के तौर पर जाना जा रहा है। वे आगामी समय में हरियाणा, पंजाब, उप्र, राजस्थान और दिल्ली की जाट राजनीति के केंद्र में आ सकते हैं। पश्चिम उप्र की राजनीति में टिकैत का कद बढ़ चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। अजित सिंह के बेटे जयंत चौधरी, टिकैत को समर्थन देने पहुंचे, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी टिकैत से बातचीत की। जब राकेश टिकैत के आंसू निकले थे, उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी टिकैत के समर्थन में ट्वीट करने में देर नहीं लगाई।

मराठा आरक्षण की जरूरत किसको?

सुप्रीम कोर्ट ने मराठा समुदाय को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण देने वाले महाराष्ट्र के कानून को 'असंवैधानिक' करार दे दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र की 'सियासी चाय' में एक नया उबाल आने के संकेत मिलने लगे हैं। एंटीलिया केस और 100 करोड़ के कथित वसूली मामले की आग फिलहाल ठंडी पड़ती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से भाजपा को महाराष्ट्र में राजनीति करने के लिए एक और मुद्दा मिल गया है। वैसे, भाजपा के लिए मराठा आरक्षण केवल सियासी मुद्दा नहीं है, यह उसकी जरूरत है।

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना से मिले धोखे की टीस रह-रहकर भाजपा को सालती रहती है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले से लेकर सिंडिकेट राज तक महाविकास आघाड़ी सरकार को घेरने का कोई भी मौका भाजपा ने छोड़ा नहीं है। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार फिलहाल बिना किसी समस्या के चल रही है और सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी भाजपा इस सब पर नाराजगी जताने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती है। मराठा आंदोलन को लेकर भी राज्य में बड़ा आंदोलन हो चुका है और यह हिंसक तक हो गया था। वैसे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मराठा आरक्षण की डगर काफी कठिन है। गुजरात में पाटीदार आंदोलन के सहारे पटेल आरक्षण और हरियाणा व राजस्थान में जाट आरक्षण की मांग उठती रही है। मराठा आंदोलन को लेकर भी राज्य में बड़ा आंदोलन हो चुका है और यह हिंसक तक हो गया था। महाराष्ट्र की 32 फीसदी मराठा आबादी आरक्षण के सहारे ही सही जिसके पक्ष में रहेगी, राज्य में उस पार्टी का राजनीतिक वर्चस्व शायद ही कोई तोड़ सके।

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आरक्षण के मामले पर महाविकास आघाड़ी सरकार के मराठा समुदाय के साथ होने की बात कही है। उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बाबत पत्र लिखने की जानकारी देते हुए कहा कि धारा 370 हटाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जैसी हिम्मत दिखाई थी, वैसी ही मराठा आरक्षण के लिए भी दिखाएं। महाराष्ट्र की हर राजनीतिक पार्टी के लिए मराठा आरक्षण एक जरूरी मामला है। यही वजह है कि इस प्रस्ताव को पारित करने का समर्थन सभी सियासी दलों ने किया था। ये आरक्षण ठीक वैसा ही है, जैसा केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को दिया था। सवर्णों को मिलने वाले आरक्षण पर भी सभी राजनीतिक दलों ने सहमति जताई थी।

मराठी मानुष की राजनीति करने वाली शिवसेना के लिए भी मराठा आरक्षण परीक्षा के एक अनिवार्य विषय की तरह है। वह इससे अलग होती है, तो उसकी राजनीति ही खत्म हो जाएगी। शिवसेना की महाराष्ट्र से बाहर केंद्र की राजनीति करने में कभी दिलचस्पी नजर नहीं आई है। वह महाराष्ट्र और खासकर औद्योगिक नगरी मुंबई में ही खुद का प्रभाव स्थापित करने की पक्षधर रही है। शिवसेना के कब्जे वाली बीएमसी में भ्रष्टाचार के हाल जगजाहिर हैं। शिवसेना इस खेल से ही खुद को मजबूत करती रही है। मराठी कार्ड शिवसेना के लिए तुरुप का पत्ता है और वह इसे आसानी से अपने हाथ से जाने नहीं देगी।

मराठा आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धारा 370 हटाने जैसी ताकत का इस्तेमाल करेंगे या नहीं, ये बात वक्त की गर्त में छिपी है। लेकिन, यह मुद्दा भविष्य में भाजपा के लिए संजीवनी बूटी हो सकता है। यही वजह है कि भाजपा ने उद्धव ठाकरे नीत महाविकास आघाड़ी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट को अपनी बात नहीं समझा पाने का आरोप लगाया है। कोरोना महामारी के चरम पर होने के बावजूद महाराष्ट्र भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने उद्धव सरकार को घेरने के लिए मराठा आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक और विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर केंद्र सरकार मराठा आरक्षण पर कोई फैसला लेती है, तो महाराष्ट्र की 32 फीसदी मराठा आबादी एक झटके में भाजपा की झोली में आ सकते हैं। लेकिन, इतना तो कहा ही जा सकता है कि भाजपा ये फैसला अभी नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा समुदाय का आरक्षण असाधारण परिस्थिति न होते हुए कहकर खारिज किया है। भाजपा के लिए यह एक असाधारण मौका है, जो राज्य में उसकी राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय करने की क्षमता रखता है।

● **बिन्दु माथुर**

आरक्षण का श्रेय लेने की होड़

महाराष्ट्र भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने अप्रत्यक्ष रूप से मराठा समुदाय को एक बार फिर से आंदोलन करने की नसीहत दे डाली है। मराठा आरक्षण का श्रेय लेने की होड़ में चंद्रकांत पाटिल कहते नजर आते हैं कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाकर मराठा समुदाय को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मानने की सिफारिश की। फडणवीस सरकार ने ही मराठाओं के लिए कानून बनाया और जब इसे हाईकोर्ट में चुनौती मिली, तो फडणवीस सरकार ने ही कोर्ट को इसे जारी रखने के लिए समझाया था। अब महाविकास आघाड़ी सरकार ने मराठा समुदाय को विफल कर दिया है। पाटिल ने अप्रत्यक्ष रूप से मराठा समुदाय को एक बार फिर से आंदोलन करने की हिदायत दे डाली है। उन्होंने कहा कि मराठा समुदाय को इस मुद्दे पर खुलकर आवाज उठानी चाहिए और उद्धव ठाकरे सरकार पर दबाव बनाना चाहिए।

सत्ता विरोध का मौका

उप्र में कोरोना महामारी का तांडव मचा हुआ है। आम और खास सब इससे दुखी और पीड़ित हैं। प्रदेश की बड़ी आबादी इसकी चपेट में आ गई है। कई घर उजड़ गए हैं। लोगों का काम-धंधा चौपट हो गया है। रोजी-रोजगार चला गया है। विकास का पहिया थम-सा गया है। संकट की इस घड़ी ने योगी सरकार के लिए भी चुनौतियां खड़ी कर रखी हैं। सरकार का पूरा ध्यान इसी बात पर लगा है कि कैसे लोगों की जान बचाई जा सके या फिर जीवन का कम से कम नुकसान हो। वहीं ऐसे लोग भी कम नहीं हैं जिनके लिए महामारी 'फलने-फूलने' और अपनी सियासत चमकाने का मौका बन गया है। ऐसे लोगों में वह सभी दल और उनके नेता शामिल हैं जिन्हें लगता है कि अगले वर्ष उप्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में कोरोना महामारी से निपटने में योगी सरकार की सफलता अथवा असफलता बड़ा मुद्दा बन सकता है। इसीलिए गैर भाजपाई नेता लगातार इस प्रयास में लगे हुए हैं कि कोरोना महामारी की आड़ में योगी सरकार की जितनी फजीहत की जा सकती है, उतनी की जाए ताकि 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें इसका फायदा मिल सके।

यह हकीकत है कि यदि इस समय कोरोना महामारी का तांडव नहीं फैला होता तो सभी दलों के नेता चुनावी संग्राम में कूदकर शहर-शहर सभाएं कर रहे होते। प्रत्याशी टिकट के लिए हाथ-पैर मार रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है तो इसका यह मतलब नहीं है कि नेताओं ने हार मान ली है। सभी दलों के नेता सोशल मीडिया के सहारे मिशन 2022 को पूरा करने में लगे हैं। यह नेता घर में बैठकर ट्विटर आदि के माध्यम से अपनी बात जन-जन तक पहुंचा रहे हैं। सोशल साइट्स पर नेता और उनके समर्थक आपस में उलझे हुए हैं। सब अपने को पाक-साफ और विरोधियों पर दोषारोपण में लगे हुए हैं। एक तरफ नेता अपनी सियासत चमकाने में लगे हैं तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी मैदान में कूदे हुए हैं जो अपने आपको बताते तो गैर-राजनीतिक हैं, लेकिन सियासत करने में नेताओं से पीछे नहीं हैं। इसमें किसान आंदोलन चला रहे राकेश टिकैत जैसे किसान नेता भी हैं तो कुछ बुद्धिजीवी और समाजसेवी भी किसी न किसी दल के पाले में आंख मूंदकर खड़े नजर आ रहे हैं।

प्रियंका के निशाने पर भाजपा

प्रियंका गांधी लगातार भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही हैं। प्रियंका के तर्क और सुझाव कितने संजीदा हैं इसकी एक और बानगी उनके ताजा बयान में देखने को मिली, जब उन्होंने बेकाबू होते कोरोना संक्रमण पर योगी सरकार को पत्र लिखकर सुझाव दिया कि वह लोगों को जेल में डालने और संपत्ति जब्त करने की जगह कोरोना से लड़ने में ध्यान केंद्रित करें। वरना प्रदेश की जनता उन्हें माफ नहीं कर पाएगी। अब प्रियंका किसकी संपत्ति नहीं जब्त करने और किसको जेल में नहीं डालने की बात कह रही हैं, वह यह भी स्पष्ट कर देतीं तो ज्यादा अच्छा रहता। क्या उन्हें बाहुबली मुख्तार अंसारी के जेल जाने से परेशानी है जिसको उनकी पंजाब सरकार ने बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक में गुहार लगाई थी या फिर कोई और वजह है या प्रियंका को गांधी परिवार की ओर से कथित तौर पर अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति जब्त होने का डर तो सता रहा है।

कुल मिलाकर विपक्ष इस कोशिश में है कि योगी सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर बड़ी की जा सके। इसके लिए कोरोना महामारी के सहारे योगी सरकार को घेरने से बड़ा कोई मुद्दा विपक्ष के पास नजर नहीं आ रहा है। लगातार चार वर्षों से योगी सरकार के खिलाफ मुद्दे की तलाश कर रहे विपक्ष की कोरोना महामारी के चलते 'पौ-बारह' हो गई है। विपक्ष का ध्यान इस ओर बिल्कुल नहीं है कि योगी सरकार को कुछ सार्थक सुझाव दिए जाएं ताकि कोरोना से त्राहिमाम कर रही जनता को कुछ राहत मिल पाए, बल्कि कोशिश इस बात की है कि जनता को योगी सरकार के खिलाफ जितना हो सके उतना भड़काया जा सके। इसीलिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव सुबह उठते ही अनर्गल बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का भी पूरा ध्यान इस ओर है कि कैसे योगी सरकार को नाकारा साबित किया जा सके। इसलिए वह कभी ट्वीट करती हैं तो कभी चिट्ठी लिखती हैं। अच्छा होता प्रियंका उप्र सरकार पर कोरोना महामारी से निपटने में नाकामी का आरोप लगाते समय कांग्रेस शासित राज्यों के कुछ उदाहरण भी दे देतीं कि कैसे पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड की सरकारें कोरोना महामारी के खिलाफ निर्णायक जंग छेड़े हुए हैं, लेकिन उनके पास ऐसा कुछ कहने को है नहीं। कांग्रेस शासित राज्यों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। इन राज्यों की सरकारें कोरोना से निपटने के बजाय इस बात को लेकर ज्यादा चिंतित हैं कि कैसे मोदी सरकार को बदनाम किया जा सके।

महाराष्ट्र में मौत का तांडव होता रहा, न सोनिया के मुंह से बोल फूटे न राहुल-प्रियंका की जुबान खुली। महाराष्ट्र में किस तरह से लाशों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, वह शर्मनाक ही नहीं जघन्य अपराध की श्रेणी में भी आता है, लेकिन सत्ता की भूख के चलते सब मौन रहते हैं। यही स्थिति कमोबेश पंजाब की है। पंजाब के बारे में तो गांधी परिवार चाहकर भी मुंह नहीं खोल सकता है क्योंकि पंजाब में कांग्रेस का मतलब कैप्टन अमरिंदर सिंह है। बात प्रियंका गांधी द्वारा उप्र के मुख्यमंत्री योगी को लिखी गई चिट्ठी की कि जाए तो इस चिट्ठी में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है जिसे कोई सरकार गंभीरता से लेना चाहेगी। बिना किन्हीं तथ्यों के हवा में बातें करते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिख दिया गया है। वही ढिंढोरा, ऑक्सीजन की कमी है, दवाओं की कालाबाजारी हो रही है, अस्पताल में मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है। यह समस्या पूरे देश की है, दिल्ली में भी यही हाल है और कांग्रेस शासित राज्यों की भी यही स्थिति है, लेकिन गांधी परिवार को भाजपा शासित राज्यों के अलावा कहीं कुछ दिखाई-सुनाई ही नहीं देता है। इसीलिए तो यह बात दावे से कही जा रही है कि प्रियंका कोरोना महामारी की आड़ में मिशन-2022 पूरा करने की बिसात बिछाने में लगी हैं।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

पप्पू पास हो गए...

कोविड महामारी की चपेट में आई हर नजर पप्पू यादव की तरफ आखिरी उम्मीद से देख रही थी, बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने पूर्व सांसद और जन अधिकारी पार्टी के नेता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जाहिर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही निशाने पर रहेंगे। नीतीश कुमार निशाने पर विपक्षी पार्टी आरजेडी के भी हैं, लेकिन हैरानी की बात ये है कि लालू यादव की पार्टी के निशाने पर पप्पू यादव भी हैं और आरजेडी प्रवक्ता पप्पू यादव की गिरफ्तारी को नौटंकी बताते हुए दोनों की मिलीभगत की राजनीति बता रहे हैं। देखा जाए तो एक अरसे से पप्पू यादव बिहार के सोनू सूद बने हुए हैं, हर गाढ़े वक्त में अगर जरूरतमंद लोगों तक कोई पहुंच भी सका है तो वो पप्पू यादव के मदद के हाथ ही रहे हैं। पटना में बाढ़ के वक्त ये पप्पू यादव ही रहे जो नाव लेकर घर-घर दूध-ब्रेड और दवाएं पहुंचा रहे थे और जब कोविड महामारी के चलते सरकारी व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है तो पप्पू यादव कोविड मरीजों के लिए दवा और ऑक्सीजन से लेकर खाने तक के इंतजाम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर पप्पू यादव की रिहाई के ट्रेंड चल रहे हैं। पप्पू यादव को गिरफ्तार करके जब पुलिस ले जा रही थी तो सड़क के दोनों किनारे लोग खड़े थे और जगह-जगह पप्पू यादव के समर्थक पुलिस की गाड़ी के आगे ही सड़क पर लेट जा रहे थे। ये समझना जरूरी हो गया है कि आखिर नीतीश सरकार ने पप्पू यादव को गिरफ्तार कर रातों-रात हीरो बनाने का जोखिम क्यों लिया?

पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद बिहार में एक नैरेटिव चल रहा है कि नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के यादव वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए पप्पू यादव को हीरो बना दिया है। लेकिन कितनी अजीब बात है। अभी न तो कोई चुनाव है और न ही कोई राजनीतिक संकट, भला ऐसे में नीतीश कुमार लोगों की नाराजगी मोल लेने के जोखिम पर ऐसी राजनीति के चक्कर में क्यों पड़ेंगे? पप्पू यादव की गिरफ्तारी में तमाम राजनीतिक लोचे देखने को मिल रहे हैं, डबल इंजिन वाली सरकार में ये एक ही चाणक्य का फैसला है या इसमें भी डबल रोल है? और सबसे बड़ा ताज्जुब तो ये है कि बात-बात पर एक साथ पांच-पांच ट्वीट करने वाला लालू यादव के परिवार को लगता है जैसे सांप सूंघ गया हो, लेकिन ऐसे सवालों के जवाब में पप्पू यादव ने जो कुछ भी तेजस्वी यादव और लालू परिवार के लोगों के लिए कहा है, उसमें हर कोई कठघरे में खड़ा नजर आने लगा है। पप्पू यादव को सुपौल की ही वीरपुर जेल में रखा गया है। सुपौल की पूर्व सांसद रंजीत रंजन ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। रंजीत रंजन ने ट्विटर पर सीधे-सीधे लिख डाला है कि अगर पप्पू यादव को कुछ हुआ तो 'मुख्यमंत्री आवास से घसीट कर अगर चौराहे पर नहीं खड़ा किया तो मेरा नाम रंजीत रंजन नहीं।' जेल जाने से पहले पप्पू यादव भी लालू यादव की तरह बता गए हैं कि उनके लौटने तक उनकी टीम उनकी बातें लोगों से शेयर करती रहेगी। ट्विटर पर पप्पू यादव की टीम लगातार अपडेट दे रही है, लेकिन हर किसी को हैरानी लालू परिवार की चुप्पी पर हो रही है। अब तक तो यही देखने को मिला है कि किसी भी मुद्दे पर कम से कम पांच ट्विटर हैंडल से किसी भी मुद्दे पर मिलती जुलती बातें पोस्ट की जाती हैं। ये हैं - लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य के ट्विटर हैंडल। कभी-कभी किसी मुद्दे पर राबड़ी देवी के ट्विटर हैंडल से भी ऐसे ट्वीट किए जाते हैं और ऐसा दिन में कई बार होता है। राज्यसभा सांसद मीसा भारती और रोहिणी आचार्य लालू यादव की बेटियां हैं।

बाहर की बदइंतजामियों पर लगातार शोर मचाने वाले पप्पू यादव जेल पहुंचकर भी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और ये जानकारी भी उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दी गई है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद ऐसा बिलकुल नहीं है कि सिर्फ यादव समुदाय को तकलीफ हुई है, बल्कि समाज का हर तबका नीतीश कुमार सरकार के इस कदम से गुस्से में है। हर वो तबका गुस्से में है जिसे पप्पू यादव से कभी न कभी मदद मिली है, चाहे पटना में आई बाढ़ के वक्त, चाहे अभी कोरोना महामारी के वक्त। किसी को दवा की जरूरत पड़ी तो वो भी मिली। किसी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो वो भी मिली और कोई भूखा था तो उसे खाना भी मिला।

पप्पू की गिरफ्तारी से आम लोग ही नहीं राजनीति में भी पार्टीलाइन आड़े नहीं आ रही है। हर राजनीतिक दल में नेताओं की भी खासी तादाद है। पटना में सत्ता के गलियारों में घूमने वाले और उन पर नजर रखने वाले किसी भी शख्स से भी बात कीजिए, वो पप्पू यादव की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए सत्तापक्ष के लोगों का नाम लेकर ठेठ अंदाज में गाली देते हुए ही बात कर रहा है। पप्पू यादव के नाम पर हर पार्टी में बंटवारा हो गया है और चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू हो या फिर भाजपा। भाजपा नेता आधिकारिक तौर पर भले ही नाराजगी जाहिर करें, लेकिन भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी के खिलाफ पप्पू यादव के एक्शन को गलत नहीं मानने वाले नेताओं की संख्या भी काफी है। जेडीयू में तो पप्पू यादव के पक्ष और विपक्ष में साफ-साफ बंटवारा हो गया है। पप्पू यादव के खिलाफ नीतीश सरकार के एक्शन से हर कोई खफा है।

● **विनोद बक्सरी**

नीतीश की फजीहत और लालू परिवार की मुश्किल

जिस दिन लालू यादव जेल से रिहा हुए उसी दिन उनके बेहद करीबी और बाहुबली नेता शाहबुद्दीन की मौत की खबर मिली और अभी दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती के पास कुछ दिन खुली हवा में सांस लिए हैं कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी ने नई मुश्किल में डाल दिया है। अपनी पार्टी बनाने से पहले पप्पू यादव ने राजनीति की शुरुआत लालू यादव की आरजेडी के साथ ही की थी। जब पप्पू यादव आरजेडी सांसद थे तो बताते नहीं थकते थे कि कैसे लालू यादव उनको मानस-पुत्र मानते हैं। ये सब बताने के पीछे मकसद एक ही रहा, आरजेडी में लालू यादव का उत्तराधिकारी बनने की कोशिश। रास्ते में कोई रोड़ा न आए इसलिए वो तेजस्वी यादव को कमतर करके प्रोजेक्ट करते थे। तभी एक दिन लालू यादव ने साफ कर दिया कि वो अपनी पार्टी आरजेडी की विरासत तेजस्वी यादव को ही सौंपेंगे, किसी और को तो बिलकुल नहीं है। सच भी यही है कि बड़े बेटे को दरकिनार करते हुए लालू यादव ने तेजस्वी को ही अपनी विरासत सौंपी है।

सिद्धांतों से समझौता संभव नहीं

अमेरिका में यूएई के राजदूत यूसुफ अल ओतेबा ने बीते दिनों एक बड़ा दावा किया। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उनका देश भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कर रहा है। यह बात कुछ अजीब इसलिए थी, क्योंकि उनसे इस बारे में कोई सवाल ही नहीं किया गया था। उनसे पूछा गया था कि क्या उनका देश अफगान शांति प्रक्रिया में पाकिस्तान को और उपयोगी बनाने के लिए उसे समझाने का प्रयास करेगा? इसके जवाब में उन्होंने खुद ही भारत और पाकिस्तान को लेकर यह टिप्पणी की। स्पष्ट है कि ओतेबा कूटनीति की पिच का अपने मुताबिक इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि यह एकदम स्पष्ट है कि भारत, पाकिस्तान और यूएई के बीच कोई त्रिपक्षीय वार्ता नहीं हो रही है। इसका अर्थ यह नहीं कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के बिल्कुल संपर्क में ही नहीं हैं। विशेषकर तब जब दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव घटाने को लेकर, जो इन परमाणु शक्तियों के बीच नागरिक सीमा न रहकर सैन्य सीमा बन गई है। इसीलिए दोनों देशों के सैन्य अभियानों के महानिदेशक तनाव घटाने की संभावनाओं को तलाशने के लिए एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। यह सब उनकी जानकारी के बिना संभव नहीं है, जिन पर राष्ट्रीय सुरक्षा का दारोमदार है।

भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता की तार्किकता को लेकर कोई संदेह नहीं। संबंधों को शांतिपूर्ण एवं स्थायित्व रूप देने के लिए किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने कभी कोई हिचक नहीं दिखाई। सिर्फ एक उदाहरण से समझ लीजिए कि वर्ष 1965 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री काहिरा से लौटते समय तबके पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान से वार्ता के लिए कराची में रुक गए थे। इसके बावजूद पाकिस्तान ने उसी साल भारत के साथ सीमा पर विश्वासघात किया। पाकिस्तान से वार्ता किस परिवेश में संभव हो सकती है, उसे लेकर स्पष्टता बहुत आवश्यक है। भारतीय कूटनीति का यही तकाजा रहा है कि सभी प्रकार की वार्ताएं द्विपक्षीय स्तर पर होनी चाहिए। वार्ताओं को लेकर भारत का अनुभव खट्टा ही रहा है। इसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह पर कश्मीर मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने वाले कदम के साथ ही हो गई थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस पर अवश्य कड़ा रुख अपनाया था कि वार्ता और आतंक साथ-साथ नहीं चल सकते। दोनों देशों के बीच अंतिम शिखर वार्ता जो जुलाई 2001 में आगरा में हुई थी, उसमें पाकिस्तान ने मसलों को द्विपक्षीय स्तर पर सुलझाने की शर्त पर तो सहमति जताई, लेकिन आंतकवाद वाली दूसरी शर्त से वह मुकर गया। गत सात वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार-बार दोहराया है कि इन दोनों शर्तों पर कोई रियायत संभव नहीं।

भारत के उलट पाकिस्तान ने हमेशा से द्विपक्षीय विवाद के अंतरराष्ट्रीयकरण का प्रयास किया है। फिर इसमें चाहे उसे महाशक्तियों को या क्षेत्रीय ताकतों को जोड़ना हो या संयुक्त राष्ट्र के समक्ष ही गुहार क्यों न लगानी पड़ी हो। इस्लामाबाद में कुछ आशावादियों ने तो इसमें चीन तक को शामिल करने के भी प्रयास किए। असल में इस्लामाबाद किसी तीसरे पक्ष को इसलिए शामिल करना चाहता है ताकि वह भारत पर जम्मू-कश्मीर की स्थिति से समझौता करने के लिए दबाव बनाए और पाकिस्तान उसे अपनी 'जीत' के तौर पर पेश कर सके। भारत के साथ वार्ता को लेकर पाकिस्तानी नीति को एक वाक्य में इस प्रकार समेटा जा सकता है कि मानों कोई एक पैर ब्रेक पर मजबूती से टिकाकर ही आगे बढ़ रहा हो। यह खेल अभी भी जारी है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी दोनों यह कह चुके हैं कि भारत के साथ तब तक वार्ता संभव नहीं जब तक वह जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को बहाल नहीं करता।

जहां तक यूएई की बात है तो वह भारत का बहुत घनिष्ठ मित्र है। यह मित्रता एक निर्विवाद तथ्य है, लेकिन मित्रता का अर्थ यह नहीं कि उसमें सिद्धांतों की बलि दे दी जाए। एक बार द्विपक्षीयता के सिद्धांत से समझौता किया गया तो भारत के मित्र देशों की सूची से तीसरे देश का नाम कभी भी उछाला जा सकता है। क्या हम कल इस पर बहस करेंगे कि अमेरिका भारत का भरोसेमंद मित्र नहीं है? यदि यह स्वीकार करते हैं तो क्या हम उसके साथ जुड़ी अच्छी भावनाएं और उसके दर्जे को अनदेखा कर सकते हैं कि वाशिंगटन को तो वार्ता की मेज पर लाया ही जाएगा?

इतिहास इसका साक्षी रहा है कि मित्र देशों ने इस द्विपक्षीय विवाद को दिल्ली के नजरिए से देखने के बजाय अपने ही चश्मे से देखा है। अब हम उस कालखंड से आगे बढ़ चुके हैं, जब ब्रिटेन यह सोचता था कि इसमें हस्तक्षेप उसका स्वाभाविक अधिकार है। या फिर उस दौर से भी जब अमेरिका अपने दक्षिण एशियाई समीकरणों के अनुकूल किसी किस्म के समझौते पर दबाव बढ़ा रहा था। हमारी विदेश नीति उन गलियारों में वापस नहीं लौट सकती, जिन्हें वह काफी पीछे छोड़ चुकी है।

● **कुमार विनोद**

भारत ने भविष्य की वार्ताओं के लिए कुछ लचीलापन छोड़ दिया

भारत ने अपने रवैये में भविष्य की वार्ताओं के लिए कुछ लचीलापन छोड़ दिया। उस समझौते के अनुसार, 'दोनों देश इस पर सहमत हुए कि उनके बीच मतभेद द्विपक्षीय वार्ता के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से या परस्पर सहमति से स्वीकृत किसी अन्य शांतिपूर्ण तरीके से ही सुलझाए जाएंगे।' इसमें एक सन्निहित शर्त है कि किसी भी अन्य तरीके में दिल्ली की सहमति आवश्यक होगी। संभव है कि ओतेबा अपने मेजबान अमेरिकियों के बीच इस क्षेत्र में यूएई के रुतबे को दिखाने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हों। ऐसे प्रयासों को सुर्खियों में जगह नहीं मिलनी चाहिए। अगर पाकिस्तान भारत के साथ वार्ता के लिए तैयार है तो उसके नेताओं को एक महफूज टेलीफोन चुनकर दिल्ली में एक फोन लगाना होगा। भारत और पाकिस्तान ऐसे लोगों को चुन सकते हैं, जो दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच भविष्य के सम्मेलन की रूपरेखा तैयार कर सकें। इतिहास में गंवाए अवसरों पर ध्यान नहीं देना होगा, जैसा इंदिरा गांधी ने 2 जुलाई, 1972 को शिमला समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ गंवा दिया था। उस क्षण कश्मीर विवाद को हमेशा के लिए सुलझाया जा सकता था, लेकिन हम एक परास्त, पस्त और हताश पड़े पाकिस्तान से केवल 'जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा के सम्मान की प्रतिबद्धता' ही ले सके, जिसे 'स्थायी शांति की कुंजी' बताया गया।

ओली की फिर से होली

तमाम कोशिशों के बाद भी नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (माओवादी मध्य) का विपक्षी गठबंधन नई सरकार बनाने के लिए सदन में आवश्यक बहुमत जुटाने में नाकाम रहा और केपी शर्मा ओली ने एक बार फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री पद की कमान संभाल ली है। राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी ने विपक्षी दलों को 13 मई को रात 9 बजे तक नई सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत के साथ आने के लिए कहा था, लेकिन विपक्षी धड़ों के बीच गुटबाजी की वजह से आपसी सहमति नहीं बन सकी। इससे पहले केपी शर्मा ओली 10 मई को प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत नहीं हासिल कर सके थे। विपक्षी गठबंधन में एकमत नहीं होने की वजह से ओली फिर से प्रधानमंत्री बन गए। आपको बता दें, नेपाल की संसद प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत के लिए हुए मतदान में केपी शर्मा ओली के पक्ष में महज 93 वोट ही पड़े थे। जबकि विपक्ष में 124 सांसदों ने मतदान किया। ओली की अपनी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल के 28 सांसद व्हीप का उल्लंघन करते हुए सदन में उपस्थित ही नहीं हुए थे। विश्वास प्रस्ताव के दौरान कुल 232 सदस्यों ने मतदान किया था।

दरअसल पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' की अगुवाई वाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी मध्य) ने पार्टी के विभाजन के 3 महीने बाद ओली सरकार से समर्थन वापस ले लिया था जिसके बाद ओली सरकार को फ्लोर टेस्ट का सामना करना पड़ा। राजनीतिक उतार-चढ़ाव के बीच नेपाल में 10 मई को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था जिसमें ओली विश्वास मत हासिल नहीं कर सके थे। हालांकि राष्ट्रपति की ओर से नई सरकार के गठन को लेकर दी गई समयसीमा 13 मई रात 9 बजे हो रही थी, लेकिन इस बीच विपक्षी गठबंधन में कोई सहमति नहीं बन सकी। विपक्षी दल नई सरकार बनाने के लिए सदन में आवश्यक बहुमत जुटाने में असफल रहे, जिसके बाद ओली के प्रधानमंत्री पद पर दोबारा काबिज होने का रास्ता साफ हो गया। इससे पहले शेर बहादुर देउबा के नेतृत्व वाली नेपाली कांग्रेस ने 11 मई को प्रधानमंत्री पद के लिए दावा पेश करने का निर्णय लिया था, लेकिन गठबंधन सरकार बनाने की उसकी कोशिशों को तब झटका लगा जब महंत ठाकुर की अगुवाई वाली जनता समाजवादी पार्टी-नेपाल (जेएसपी-एन) के एक वर्ग ने साफ कर दिया कि वह सरकार गठन की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेगा।

आपको बता दें, ठाकुर के नेतृत्व वाले धड़े के प्रतिनिधि सभा में करीब 16 मत हैं। नेपाली कांग्रेस के पास 61 मत हैं। उसे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी मध्य) का समर्थन हासिल है, जिसके पास 49 मत हैं। कांग्रेस-माओवादी मध्य के गठबंधन को उपेंद्र यादव नीत जनता समाजवादी पार्टी के करीब 15 सांसदों का भी समर्थन हासिल है। लेकिन इन तीनों दलों के पास कुल 125 मत हैं जो 271 सदस्यीय सदन में बहुमत के आंकड़े 136 से 11 मत कम हैं।

सीपीएन-यूएमएल के माधव कुमार नेपाल-झालानाथ खनल धड़े से संबंध रखने वाले सांसद भीम बहादुर रावल ने गतिरोध खत्म करने के लिए दोनों नेताओं के करीबी सांसदों से नई सरकार का गठन करने के लिए संसद सदस्यता से इस्तीफा देने का आग्रह किया था। रावल ने गत दिनों ट्वीट किया कि ओली नीत सरकार को गिराने के लिए उन्हें संसद सदस्यता से इस्तीफा देना चाहिए। सांसद भीम बहादुर रावल ने लिखा, असाधारण समस्याओं के समाधान के लिए असाधारण कदम उठाए जाने की जरूरत होती है। प्रधानमंत्री ओली को राष्ट्रीय हितों के खिलाफ अतिरिक्त कदम उठाने से रोकने के लिए उनकी सरकार गिराना जरूरी है। इसके लिए हमें संसद की सदस्यता से इस्तीफा देना चाहिए। राजनीतिक नैतिकता और कानूनी सिद्धांतों के लिहाज से ऐसा करना उचित है।

बता दें, यदि नेपाल-खनल धड़े के यूएमएल के 28 सांसद एक साथ संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे देते तो नेपाली कांग्रेस और सीपीएन-माओवाद मध्य के लिए जनता समाजवादी पार्टी-नेपाल (जेएसपी-एन) के एक धड़े के सांसदों का समर्थन लिए बिना भी नई सरकार के गठन की राह आसान हो जाती, क्योंकि यूएमएल के 28 सांसद सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देते हैं तो 271 सदस्यों वाली प्रतिनिधि सभा में सांसदों की संख्या घटकर 243 हो जाती और बहुमत का आंकड़ा भी कम हो जाता। इसके बाद नेपाली कांग्रेस और सीपीएन-माओवाद मध्य गठबंधन आसानी से सरकार बना सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऐसे में केपी शर्मा ओली ने एक बार फिर अपनी राजनीतिक कुशलता का परिचय देते हुए न सिर्फ अपने आप को सिद्ध किया बल्कि अपना वजूद यानी कुर्सी बचाने में भी कामयाब रहे।

● **राजेश बोरकर**

ओली पर चीन के साथ होने का आरोप

ओली पर शुरू से ही आरोप लगते रहे हैं कि वो चीन के इशारों पर चलते हैं। भारत को लेकर उनका नजरिया भी कोई सकारात्मक नहीं रहा है। दरअसल 1966 से ही नेपाल की सियासत में सक्रिय रहे ओली के लिए तत्कालीन अधिनायकवादी पंचायत व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन में शामिल होना टर्निंग प्वाइंट था। कहा जाता है तब नौवीं कक्षा में पढ़ने वाले ओली के भीतर की आग का इस्तेमाल तत्कालीन राजशाही ने किया और अपने मोहरे के तौर पर पंचायत व्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाले एक चेहरे के तौर पर पेश किया। ओली ने पढ़ाई छोड़ दी, राजशाही उनकी पीठ थपथपा रही थी और सियासत में अपने मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी। इसके करीब चार साल बाद ओली को इस बात का एहसास हुआ और उन्होंने खुद को कम्युनिस्ट आंदोलन का हिस्सा बना लिया। चीन उनके लिए तब से ही आदर्श रहा है। 70 के दशक में भारत समेत कई एशियाई देशों में कम्युनिस्ट आंदोलन उफान पर था। नेपाल में भी कम्युनिस्ट पार्टी राजशाही के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत कर चुकी थी, पंचायती व्यवस्था के अधिनायकवादी चेहरे के भी खिलाफ आवाज उठ रही थी और लोकतंत्र की मांग तेज होने लगी थी।

लैंगिक विषमता के समांतर सवाल

महिलाओं को पुरुषों की तुलना में वरीयता नहीं दी जाती

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक अध्ययन बताता है कि अगर भारत में महिलाओं को श्रमबल में बराबरी हो जाए तो सकल घरेलू उत्पाद में 27 फीसदी तक का इजाफा हो सकता है। हालांकि इस तथ्य को जानने के बावजूद वस्तुस्थिति कुछ और ही तस्वीर बयां करती हैं। दरअसल लिंक्डइन अपार्च्युनिटी सर्वे-2021 में यह सामने आया है कि देश की 37 फीसदी महिलाएं मानती हैं कि उन्हें पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता है, जबकि 22 फीसदी महिलाओं का कहना है कि उन्हें पुरुषों की तुलना में वरीयता नहीं दी जाती है। जाहिर है, महिला सशक्तिकरण के लिए इस तरह के आर्थिक भेदभाव मिटाने होंगे। बहरहाल इस लैंगिक असमानता सूचकांक को देखने के बाद सवाल उठता है कि आखिर लैंगिक समानता के मामले में आइसलैंड, फिनलैंड और नार्वे जैसे राष्ट्र ही क्यों शीर्ष पर बने रहते हैं? गौरतलब है कि इन राष्ट्रों की गिनती दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में भले ही न होती हो, लेकिन बात जब खुशहाल और लैंगिक भेदभाव से मुक्त राष्ट्र की होती है तो ये चुनिंदा देश संपूर्ण विश्व का नेतृत्व करते दिखाई देते हैं। क्यों न दुनिया के अन्य देश इनके अथक प्रयासों और अभिनव प्रयोगों से कुछ सीखें? आइसलैंड को ही देखें तो यह एक छोटा-सा यूरोपीय देश है, जिसकी जनसंख्या केवल साढ़े तीन लाख के आसपास है। लेकिन लैंगिक समानता के मोर्चे पर आज वह विश्व का पथ-प्रदर्शक बन गया है।

विश्व आर्थिक मंच ने 15वीं वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट जारी की है। इसमें 156 देशों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आर्थिक सहभागिता, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों तक उनकी पहुंच और राजनीतिक सशक्तिकरण जैसे मुख्य संकेतकों व लैंगिक भेदभाव को कम करने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों का जिक्र किया गया था। रिपोर्ट बताती है कि इस सूचकांक में आइसलैंड, फिनलैंड, नार्वे, न्यूजीलैंड और स्वीडन शीर्ष पांच देशों में शामिल हैं, जबकि लैंगिक समानता के मामले में यमन, इराक और पाकिस्तान सबसे फिसड्डी देश साबित हुए। हालांकि यह रिपोर्ट भारत के संदर्भ में भी लैंगिक समानता की तस्वीर कोई अच्छी नहीं है।

इस सूचकांक में भारत पिछले साल के मुकाबले 28वें पायदान से फिसलकर 140वें स्थान पर पहुंच गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2020 में लैंगिक समानता के मामले में भारत 153 देशों की सूची में 112वें स्थान पर था। इससे पहले वर्ष 2006 में जब पहली बार यह रिपोर्ट जारी की गई थी, तब इस सूचकांक में भारत 98वें स्थान पर था। जाहिर है, लैंगिक समानता के मामले में पिछले डेढ़ दशक में भारत की स्थिति लगातार खराब होती गई है। राजनीतिक क्षेत्र में स्त्री-पुरुष समानता के मामले में भारत का स्थान 51वां है। इस संदर्भ में विश्व आर्थिक मंच का कहना है कि राजनीतिक क्षेत्र में लैंगिक समानता स्थापित करने में भारत को अभी एक सदी से ज्यादा वक्त लग जाएगा।

पुरुषों और महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करके ही राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लैंगिक असमानता अभी 63 फीसदी से ज्यादा है। लैंगिक असमानता न केवल महिलाओं के विकास में बाधा पहुंचाती है, बल्कि राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी प्रभावित करती है। स्त्रियों को समाज में उचित स्थान न मिले तो एक देश पिछड़ेपन का शिकार हो सकता है। लैंगिक समानता आज भी वैश्विक समाज के लिए एक चुनौती बनी हुई है। लैंगिक समानता सुनिश्चित करना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, महिलाओं के खिलाफ हिंसा व भेदभाव को रोकना और सामाजिक पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों से निपटना आधुनिक विश्व की बड़ी जरूरत के रूप में सामने आया है। आमतौर पर असंतुलित लिंगानुपात, पुरुषों के मुकाबले साक्षरता और स्वास्थ्य सुविधाओं का निम्न स्तर, पारिश्रमिक में लैंगिक विषमता जैसे कारक समाज में स्त्रियों की कमतर स्थिति को दर्शाते हैं। अगर समाज में लैंगिक भेदभाव खत्म नहीं किया गया तो संयुक्त राष्ट्र के 2030 के सतत् विकास लक्ष्यों के मूल में निहित महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लक्ष्य की प्राप्ति में हम पिछड़ जाएंगे।

किसी भी समाज में लैंगिक असमानता लोगों की मानसिकता में बदलाव लाकर ही दूर की जा सकती है। यह समझना होगा कि सामाजिक उत्थान में जितना योगदान पुरुषों का है, उतना ही महिलाओं का भी है। इस संबंध में हम मिजोरम और मेघालय से सीख सकते हैं, जहां बिना किसी भेदभाव के महिलाओं को समान रूप से काम दिया जाता है। महिलाओं को सम्मान और समुचित अवसर देकर ही लैंगिक भेदभाव से मुक्त प्रगतिशील समाज की स्थापना संभव है। लेकिन विडंबना है कि लैंगिक भदेभाव खत्म करने के मामले में हम अपने पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भूटान से भी पीछे हैं।

अलबत्ता देश में लैंगिक विषमता खत्म करने के सरकारी स्तर पर 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी तरह सैनिक स्कूलों में लड़कियों के प्रवेश का फैसला भी ऐतिहासिक और क्रांतिकारी है। वहीं केरल के कोझिकोड में हाल में बने 'जेंडर पार्क' ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। चौबीस एकड़ के परिसर में बने इस बहुउद्देशीय 'जेंडर पार्क' में महिला सशक्तिकरण से संबंधित नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम बनाए जाएंगे। दूसरी ओर, राजस्थान सरकार ने घूंघट की कुप्रथा को खत्म करने के आव्हान के बाद जयपुर के जिला प्रशासन ने 'घूंघट मुक्त जयपुर' नामक जागरूकता अभियान शुरू किया। इस तरह के प्रयासों का मकसद लैंगिक समानता स्थापित करने के मार्ग में आने वाले अवरोधकों को दूर करना और महिलाओं की उन्नति के लिए अवसर खोलना है।

● **ज्योत्सना अनूप यादव**

आखिर क्यों प्रिय हैं श्रीराम को हनुमान?

गोस्वामी तुलसीदासजी सुंदरकांड को लिपिबद्ध करते समय हनुमानजी के गुणों पर विचार कर रहे थे। वे जिस गुण का सोचते, वहीं हनुमानजी में भरपूर दिखाई देता। इसलिए उन्होंने हनुमानजी की स्तुति करते समय उन्हें 'सकल गुण निधानं' कहा है। यह सम्मान पूरे संस्कृत साहित्य में केवल बजरंगबली को मिला है। हालांकि ईश्वर के समस्त रूप अपने आप में पूर्ण हैं लेकिन हनुमानजी एकमात्र ऐसे स्वरूप हैं, जो किसी भी कार्य में कभी भी असफल नहीं हुए। एक स्वामी को अपने सेवक से काम में सफलता की गारंटी के अलावा और चाहिए भी क्या? पवनपुत्र अपने कई गुणों के कारण प्रभु श्रीराम को अत्यंत प्रिय रहे। ये गुण हमारे जीवन में भी बड़ा बदलाव लाने की शक्ति रखते हैं-

वीरता, साहस और प्रभावी सम्प्रेषण-तमाम बाधाओं को पार कर लंका पहुंचना, माता सीता को अपने राम दूत होने का विश्वास दिलाना, लंका को जलाकर भस्म कर देना- उनके इन गुणों का बखान करते हैं।

'सूक्ष्म रूप धरी सियंहि दिखावा,
विकट रूप धरी लंक जरावा'

'कपि के वचन सप्रेम सुनि, उपजा मन बिस्वास,
जाना मन क्रम बचन यह, कृपासिंधु कर दास।'

विनम्रता के साथ बुद्धि बल- उनका सामना सुरसा नामक राक्षसी से हुआ, जो समुद्र के ऊपर से निकलने वाले को खाने के लिए कुख्यात थी। हनुमानजी ने जब सुरसा से बचने के लिए अपने शरीर का विस्तार करना शुरू कर दिया, तो प्रत्युत्तर में सुरसा ने अपना मुंह और बड़ा कर दिया। इस पर हनुमानजी ने स्वयं को छोटा कर दिया और सुरसा के मुख से होकर बाहर आ गए।

हनुमानजी की इस बुद्धिमत्ता से सुरसा संतुष्ट हो गईं और उसने हनुमानजी को आगे बढ़ने दिया। अर्थात् केवल बल से ही जीता नहीं जा सकता बल्कि विनम्रता के साथ बुद्धिमत्ता से भी कई काम आसानी से किए जा सकते हैं।

'जस-जस सुरसा बदनु बढ़ावा,
तासु दून कपि रूप देखावा।'

समर्पण और आदर्श-रामजी के प्रति हनुमानजी की अपार श्रद्धा, विश्वास और सम्मान के प्रति समर्पण अतुल्य था। उनकी अनुपस्थिति में भी उनके मान की रक्षा का ध्यान रखा। रावण की सोने की लंका को जलाकर जब हनुमानजी दोबारा सीताजी से मिलने पहुंचे, तो सीताजी ने कहा- 'पुत्र, हमें यहां से ले चलो।' इस पर हनुमानजी ने कहा कि माता, मैं आपको यहां से ले चल सकता हूं, पर मैं नहीं चाहता कि मैं आपको रावण की तरह यहां से चोरी से ले जाऊं। रावण का वध करने के बाद ही प्रभु श्रीराम आदर सहित आपको ले जाएंगे। इन्हीं गुणों के बलबूते हनुमानजी ने अष्ट सिद्धियों और सभी 9 (नव) निधियों की प्राप्ति की।

लंका में रावण के उपवन में हनुमानजी और मेघनाथ के मध्य हुए युद्ध में मेघनाथ ने 'ब्रह्मास्त्र' का प्रयोग किया। हनुमानजी चाहते तो वे इसका तोड़ निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे उसका महत्व कम नहीं करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का तीव्र आघात सह लिया। हालांकि, यह प्राणघातक भी हो सकता था। तुलसीदासजी ने हनुमानजी की मानसिकता का सूक्ष्म चित्रण इस पर किया है-

'ब्रह्मा अस्त्र तेहि साधा, कपि मन कीन्ह विचार,
जो न ब्रहसर मानहु, महिमा मिटहीं अपार।'

सदैव सचेत रहना-किसी भी संकट के समय अपना मनोबल बनाए रखते व मस्तिष्क का संतुलन नियंत्रित भाव से रखते रहे। लक्ष्मण जब शक्ति लगने से अचेत हुए तब हनुमानजी का पहाड़ जाकर संजीवनी को पहाड़ सहित उठा लाना इसी का उदाहरण है। ऐसा वे इसलिए कर पाए, क्योंकि उनके अंदर निर्णय लेने की असीम क्षमता थी। उनका यह गुण अपने दिमाग को सक्रिय रखने के लिए प्रेरित करता है।

बौद्धिक कुशलता, वफादारी और नेतृत्व क्षमता- समुद्र में पुल बनाते समय अपेक्षित कमजोर और उद्दंड वानर सेना से भी कार्य निकलवाना उनकी विशिष्ट संगठनात्मक योग्यता का परिचायक है। राम-रावण युद्ध के समय उन्होंने पूरी वानर सेना का नेतृत्व संचालन प्रखरता से किया। सुग्रीव और बाली के परस्पर संघर्ष के वक्त प्रभु राम को बाली के वध के लिए राजी करना, क्योंकि एक सुग्रीव ही प्रभु राम की मदद कर सकते थे। इस तरह हनुमानजी ने सुग्रीव और प्रभु श्रीराम दोनों के कार्यों को अपने बुद्धि कौशल और चतुराई से सुगम बना दिया। यहां हनुमानजी की मित्र के प्रति 'वफादारी' और 'आदर्श स्वामीभक्ति' तारीफ के काबिल है। सीताजी का समाचार लेकर सकुशल वापस पहुंचे श्रीहनुमान की हर तरफ प्रशंसा हुई, लेकिन उन्होंने अपने पराक्रम का कोई किस्सा प्रभु श्रीराम को नहीं सुनाया। यह हनुमानजी का बड़प्पन था जिसमें वे अपने बल का सारा श्रेय प्रभु श्रीराम के आशीर्वाद को दे रहे थे। प्रभु श्रीराम के लंका यात्रा वृत्तांत पूछने पर हनुमानजी ने जो कहा, उससे भगवान राम भी हनुमानजी के आत्ममुग्धताविहीन व्यक्तित्व के कायल हो गए-

'ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम्ह अनुकूल,
तव प्रभाव बड़वानलहि, जारि सकइ खलु तूल।'

सबसे बड़ी बात यह है कि असंभव लगने वाले कार्यों में भी जब हनुमानजी ने विजय प्राप्त की तब भी उन्होंने प्रत्येक सफलता का श्रेय 'सो सब तव प्रताप रघुराई' कहकर अपने स्वामी को समर्पित कर दिया। पूरी मेहनत करना पर श्रेय प्राप्ति की इच्छा न रखना सेवक का देव दुर्लभ गुण होता है, जो उसे अन्य सभी सद्गुणों का उपहार दे देता है। यहीं हनुमानजी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता है।

भगवान श्रीराम और हनुमानजी के पावन व पवित्र रिश्ते को कौन नहीं जानता। रामजी की ओर अपनी भक्ति भावना के लिए हनुमानजी ने अपना सारा जीवन त्यागमय कर दिया था। हनुमानजी का चरित्र अतुलित पराक्रम, ज्ञान और शक्ति के बाद भी अहंकार से विहीन था। यही आदर्श आज हमारे प्रकाश स्तंभ हैं, जो विषमताओं से भरे हुए संसार सागर में हमारा मार्गदर्शन करते हैं।

● **ओम**

मां की भूमिका

दूं टर पास सुभद्रा ने पति की सहमति से शहर के नॉर्थ कॉलोनी में चार घरों में मौसी उर्फ कुक का काम करना शुरू कर दिया। पति की कमाई से एकमात्र बेटे की पढ़ाई और घर गृहस्थी चलाना संभव नहीं हो रहा था। अभी तीन महीने काम किया ही था कि पति बीमार पड़ गया और लॉकडाउन भी लग गया। अब क्या करे सुभद्रा? पति की देखभाल करना जरूरी, कैसे काम पर जाएगी? सास घर गृहस्थी के छोटे-मोटे काम के साथ पोते की भी देखरेख करती है।

मास्क लगाकर ही वह कॉलोनी के उस घर में जाती है जिसमें दो भाई रहते हैं, बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं दोनों और उसे मौसी से ज्यादा सम्मान भी देते हैं। कॉल बेल दबाते ही छोटा भाई दरवाजा खोलता है। सुभद्रा के चेहरे पर परेशानी के भाव देख पूछता है, क्या बात है मौसी, परेशान नजर आती हैं?

बाबू, मेरे पति बीमार हैं अगले कुछ दिनों तक काम करने नहीं आ पाऊंगी। महीना पूरे महीने में चार दिन बाकी है। अगर कुछ रुपए काटकर पगार दे देते तो अच्छा होता।

मौसी की बातें सुन अंकित बाबू ने कहा, मौसी, अंकल की तबीयत ठीक नहीं होने से कुछ दिन आप नहीं आ पाएंगी, यही न; मैं पूरे महीने का पगार और एक महीने का अग्रिम आपको देता हूं। अंकल का इलाज करा लेना, और जब अंकल ठीक हो जाएं तो फिर काम पर आ जाना।

मौसी की आंखें आंसुओं से भर गई।

अंकित बाबू ने पांच हजार रुपए मौसी को देते हुए कहा, मौसी आपके हाथों बनाए खाने में घर का स्वाद मिल जाता है।

बाबू मैं भी संतुष्ट हूं कि आप दोनों भाईयों को मेरे हाथों बना खाना पसंद है।

– **निर्मल कुमार दे**

जिनको अपना, समझ रहा था

सबकी खातिर, जीकर देखा,
खुद की खातिर जीना होगा।
जिनको अपना, समझ रहा था,
उनसे ही विष पीना होगा।।
परिवर्तन का, दंभ भरा था।
संवेदना का, दर्द हरा था।
कदम-कदम, ठोकर खाकर भी,
नहीं कभी, संघर्ष मरा था।
अपेक्षा सभी की, पूरी न होतीं,
सबकुछ कर, कमीना होगा।
जिनको अपना, समझ रहा था,
उनसे ही विष पीना होगा।।
लीक से हटकर, चलता है जो।
समाज का कंटक बनता है वो।
उपलब्धि कितनी भी पा ले,
अंत में अकेला, मरता है वो।
करनी नहीं, किसी से आशा,
बहाना खुद ही, पसीना होगा।
जिनको अपना, समझ रहा था,
उनसे ही विष पीना होगा।।
अकेले, फिर से बढ़ना होगा।
थकान मिटा, फिर चढ़ना होगा।
निराश मिटा, जिंदा दिल बन,
कर्म का पाठ, फिर पढ़ना होगा।
चिंता छोड़, चिंतन भी तज तू,
कर्म ही तेरी हसीना होगा।
जिनको अपना, समझ रहा था,
उनसे ही विष पीना होगा।।

– **डॉ. संतोष गौड़ राष्ट्रप्रेमी**

कूड़ा

इमरो ने शब्बो को कहा क्यों उठा रही है। भला यह कूड़ा भी उठाने का है। यह कोई कूड़े में थोड़ी बिकता है। तुझे इतने दिन हो गए कूड़ा बीनते-बीनते तो भी तुझे अक्ल ना आई।

शब्बो ने पूछा कि इसमें क्या है यह भी तो पन्नी जैसा ही है। हम एक-एक पन्नी बीन कर ही तो कूड़ा इकट्ठा करते हैं।

इस पर इमरो ने कहा कि तुझे उस दिन भी बताया था कि यह मास्क है और वैसे भी अस्पताल की भी चीजे नहीं उठानी चाहिए। पता है इनसे बीमारियां लग जातीं हैं। अमरो बोली ओहो बड़ी आई मास्टरनी। हम कूड़ा न उठाए तो पेट कैसे भरें और यदि यही कूड़ा फैला ही रहे तो हम तो नहीं पर ये फैलाने वाले जरूर बीमार हो जाएंगे।

यह कूड़ा तो हमारी रोजी रोटी है और हम तो इसके आदि भी हो गए हैं।

– **डॉ. वेद व्यथित**

सस्पेंड आईपीएल का नफा नुकसान

कोरोना महामारी की दूसरी लहर के सर उठाने के साथ ही देश में मौत के नंगे नाच के बीच लोगों को ये काफी बुरा लग रहा था। बाद में विदेशी खिलाड़ी वापस जाने की जिद करने लगे। भारत के माहौल से डरे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने तो अपनी सरकार से भी सुरक्षित वापस बुलाने की गुहार लगाई। इस बीच देश में कोरोना के हालात में सबसे सुरक्षित बताया जा रहा आईपीएल का बायो बबल भी धवस्त हो गया। कुछ खिलाड़ी और स्टाफ संक्रमित पाए गए। संक्रमण के और नए केस सामने आ रहे हैं। लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिहाज से बीसीसीआई ने फिलहाल सीजन को सस्पेंड करने का फैसला लिया।

आईपीएल रोका गया है रद्द नहीं किया गया। लीग के चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने कहा भी कि इसे जल्द ही पूरा करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन कब और कैसे यह साफ नहीं है। आईपीएल सस्पेंड होने के साथ अलग-अलग फ्रंट पर बहुत कुछ दांव लगा था। आईपीएल सस्पेंड होने का सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि बायो बबल (सुरक्षा चक्र) टूटने की वजह से खिलाड़ी महामारी की चपेट से दूर हो रहेंगे। वैसे भी बायो बबल टूटने के साथ खिलाड़ी और स्टाफ कोरोना के खतरे के नजदीक थे। अब तक कई खिलाड़ी और स्टाफ पॉजीटिव पाए गए हैं। आईपीएल सस्पेंड होने से तीन टीमों को बड़ा फायदा मिल सकता है। ये टीमें हैं- पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स। पंजाब किंग्स के एक सबसे बड़े खिलाड़ी केएल राहुल को सर्जरी की वजह से बाहर थे। 10 मई को वापस आने तक लीग स्टेज में राहुल के बिना पंजाब के तीन-चार मैच हो जाते। अब ऐसा नहीं होगा। उनकी मौजूदगी से टीम को लीग स्टेज में मजबूती मिलेगी। इंजरी की वजह से दिल्ली कैपिटल के कप्तान श्रेयस अय्यर टूर्नामेंट से बाहर थे। मई तक खत्म हो रहे सीजन में उनके ना खेलने की आशंका थी। लेकिन सीजन सस्पेंड होने से उनके अब वापसी की उम्मीद है। आर आश्विन भी परिवार में कोविड-19 केसेस की वजह से बाहर हो गए थे। वे भी बचे मैचों में खेल सकते हैं।

सीजन के पहले मैच में फिंगर इंजुरी की वजह से राजस्थान रॉयल्स के ऑल राउंडर बेन स्टोक को बाहर जाना पड़ा था। जोफ्रा आर्चर भी बाहर थे। सीजन सस्पेंड होने की वजह से अब दोनों खिलाड़ियों का लाभ दिल्ली कैपिटल्स टीम को मिल सकता है। जाहिर तौर पर दोनों दुनिया के बड़े खिलाड़ी हैं। आईपीएल के 14वें सीजन का इकोसिस्टम वैल्यू कितने करोड़ का था यह कंफर्म नहीं है, मगर पिछली बार यह 45,800 करोड़ रुपए का था जो 2019 के 47,500 करोड़ के मुकाबले 3.6 प्रतिशत कम था। इकोसिस्टम वैल्यू में आईपीएल से जुड़ा नफा-नुकसान का समूचा कारोबार शामिल होता है। 14वां सीजन 52 दिन का था जिसमें से 24 दिन का खेल हुआ है। इस आधार पर अनुमान लगाए जा रहे हैं कि करीब आधे से कुछ ज्यादा का नुकसान होगा। एड, मार्केटिंग और एंटरटेनमेंट दुनिया में नुकसान बीसीसीआई से लेकर टीम फ्रेंचाइजी, ब्रॉडकास्टर्स, एसोसिएट ब्राडकास्टर, ऑफिशियल स्पोंसर, एसोसिएट स्पोंसर और विज्ञापनदाताओं को होगा। लगभग आधे से ज्यादा।

वीवो आईपीएल का प्रमुख स्पोंसर है। अन्य आधिकारिक स्पॉन्सर्स में अपस्टॉक्स, ड्रीम 11, अनएकेडमी, टाटा मोटर्स और क्रेड, बायजू, फोनपे, जस्ट डायल, विमल इलायची, बिंगो, हैवल्स फैन्स, फार्मईजी जैसे और स्पॉन्सर भी हैं। 14वें सीजन में रद्द होने तक सिर्फ 24 मैच खेले गए हैं। मोटे तौर पर अनुमान है कि बीसीसीआई को करीब दो हजार से ढाई हजार करोड़ का नुकसान होगा। ब्राडकास्टिंग और स्पोंसरशिप से करीब 4 हजार करोड़ की कमाई का अनुमान था। स्टार को 1600 करोड़ से ज्यादा का सीधे-सीधे नुकसान होगा। स्टार ने बीसीसीआई से पांच साल के लिए प्रसारण करार किया है। उसके एक सीजन का खर्च करीब 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा है। 14वें सीजन के लिए स्टार ने 18 एसोसिएट ब्रॉडकास्टर और 100 एडवर्टाइजर से करार किया था। खिलाड़ियों के वेतन और दूसरे खर्चों के आधार पर टीम फ्रेंचाइजियों को भी आधे से ज्यादा नुकसान का झटका लगेगा। हालांकि ये कितना होगा अभी कंफर्म नहीं है। अगर आईपीएल के रुके मैच शुरू हुए तो कारोबारी नुकसान से बचा जा सकता है। लेकिन तब सबसे बड़ी दिक्कत शेड्यूल को लेकर खड़ी हो जाएगी। यह कब और कैसे होगा इस बारे में कुछ साफ नहीं। निश्चित ही इससे दुनियाभर का क्रिकेट कैलेंडर प्रभावित होगा।

● आशीष नेमा

डिजिटल फर्स्ट को तगड़ा झटका

फिलहाल तो सबसे ज्यादा झटका एजुकेशन, गेमिंग, एंटरटेनमेंट की डिजिटल फर्स्ट कंपनियों को होगा। दरअसल, आईपीएल की टार्गेट ऑडियंस का करीब 38 प्रतिशत हिस्सा 21 साल से कम एज ग्रुप का है। इसे ध्यान में रखते हुए एड और मार्केटिंग के आक्रामक कैंपेन तैयार हुए थे। कंपनियों ने इसके लिए काफी पैसा निवेश किया था। एंटरटेनमेंट, एडुटेक कंपनियों (ग्रेड अप, बाईजू, अनअकेडमी, ड्रीम-11, एमपीएल आदि) ने बड़े पैमाने पर स्पोंसरशिप ली थीं। अलग-अलग एडटेक प्लेटफॉर्म्स ने मिलकर सीजन के कुल एड रेवेन्यू का 15 प्रतिशत कंट्रीब्यूट किया था। टूर्नामेंट बीच में ही रुकने से मार्केटिंग स्ट्रेटजी, कैंपेन और निवेश को फिलहाल जोरदार झटका लगा है।

6 करोड़ फीस मांगने की वजह से सनी के हाथ से निकल गई थी 'कलयुग'

बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी 40 साल की हो गईं। सनी का जन्म 1981 को सर्निया ओंटारियो, कनाडा में पंजाबी सिख परिवार में हुआ था। उनका असली नाम करनजीत कौर वोहरा है। कैरियर के शुरुआती दौर में सनी ने एक जर्मन बेकरी और टैक्स एंड रिटायरमैंट फर्म में काम किया था।

ऑफर हुई थी कलयुग

कम ही लोग जानते हैं कि सनी को पहली बार फिल्म मेकर मोहित सूरी ने अपनी फिल्म कलयुग (2005) के लिए अप्रोच किया था। दरअसल, सनी के रियलिटी शो बिग बॉस-5 (2011) में आने से पहले ही उनके बॉलीवुड में चर्चे होने लगे थे। यही वजह रही कि मोहित सूरी ने सबसे पहले उन्हें कलयुग में कास्ट करने का मन बनाया था। लेकिन बात फीस पर आकर अटक गई। सनी ने इस फिल्म के लिए मोहित से फीस के तौर पर 6 करोड़ रुपए की मांग की थी। कलयुग 2005 में आई थी उस वक्त के हिसाब से ये इतनी फीस मोहित को अपने बजट से बाहर लगी थी। इसीलिए मोहित ने सनी को फीस देने के साफ इंकार कर दिया था। बाद में मोहित ने फिल्म अपनी बहन स्माइली सूरी, दीपल शॉ और अमृता सिंह जैसी हीरोइनों के साथ बनाई। साथ ही इसमें कुणाल खेमू और इमरान हाशमी लीड रोल में रहे थे।

फिर 7 साल बाद सनी ने किया डेब्यू

कलयुग की रिलीज के करीब 7 साल बाद सनी लियोनी ने भट्ट कैंप की फिल्म जिस्म-2 (2012) से डेब्यू किया। पूजा भट्ट के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में सनी के अपोजिट बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा नजर आए थे। फिल्म तो कुछ खास नहीं चली, लेकिन इसमें सनी के काम को नोटिस किया गया। इसकी वजह से उन्हें बैक टू बैक फिल्में मिलती गईं। सनी ने 2011 में रियलिटी शो बिग बॉस के सीजन 5 में वाइल्ड कार्ड एंट्री ली थी। यहीं से उन्हें बॉलीवुड में एंट्री करने का मौका मिला। दरअसल, शो के एक एपिसोड के दौरान डायरेक्टर महेश भट्ट मेहमान बनकर आए थे और सनी को अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए सिलेक्ट कर लिया था।

युवराज की शूटिंग देखने पहुंची थीं जरीन खान, सलमान की नजर पड़ी तो बना दिया हीरोइन

मुंबई में जन्मी बॉलीवुड अभिनेत्री जरीन खान 34 साल की हो गई हैं। 22 साल की उम्र में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाली जरीन आज भी बड़ी कामयाबी की तलाश में हैं। नाकाम होती फिल्मों के चलते उनका कैरियर बहुत धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है।

जरीन को अपनी पहली फिल्म वीर बड़े ही आश्चर्यजनक तरीके से मिली थी। सलमान खान की फिल्म युवराज की शूटिंग के दौरान बतौर फैन शूटिंग देखने पहुंचीं जरीन खान की किस्मत रातों-रात चमक गई थी। एक्ट्रेस एक उत्सुक फैन की तरह सलमान से मिलने पहुंची थी। बातचीत के दौरान जरीन सलमान को पसंद आ गईं और सलमान ने उनसे तस्वीरें मांगी। जरीन उन्हें अपने फोन की तस्वीरें दिखाने लगीं लेकिन एक्टर को उनकी पोर्टफोलियो चाहिए थी। बाद में सलमान ने सब अरेंज करवाते हुए जरीन से अपनी अगली फिल्म वीर के लिए ऑडिशन देने को कहा। डायरेक्टर अनिल शर्मा देखना चाहते थे कि जरीन फ्लूएंट हिंदी बोल सकती हैं या नहीं। बाद में जब जरीन ने ऑडिशन दिया तो उन्हें तुरंत ही साइन कर लिया गया।

गीता बसरा ने किया खुलासा, कहा- मेरी फिल्म के पोस्टर में मुझे देखकर दिल दे बैठे थे हरभजन

एक्ट्रेस गीता बसरा ने हरभजन सिंह के साथ अपने रिलेशनशिप पर बात की। उन्होंने कहा- जब मेरी फिल्म द ट्रेन का पोस्टर रिलीज हुआ था, तभी हरभजन ने मुझे उसमें देख कर अपना दिल दे दिया था। दोनों 29 अक्टूबर 2015 में शादी के बंधन में बंध गए थे। उनकी शादी जालंधर में हुई थी। उनकी एक बेटी है जिसका नाम हिनाया है और जल्द ही जुलाई में गीता अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली हैं। गीता ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, मेरी फिल्म के पोस्टर में मुझे देखकर हरभजन ने मुझे पसंद कर लिया था। इसके बाद उन्होंने मेरे बारे में पता करना शुरू किया। फिर मेरी फिल्म का गाना रिलीज हुआ वो अजनबी और उसके बाद उन्होंने यह पूछना शुरू कर दिया कि कौन है ये लड़की? वहीं मैंने कभी कोई क्रिकेट मैच नहीं देखा था, इसलिए मुझे नहीं पता था कि हरभजन सिंह कौन हैं? गीता ने साल 2006 में फिल्म दिल दिया है से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उनकी दूसरी फिल्म द ट्रेन साल 2007 में रिलीज हुई थी और उसका सुपरहिट गाना वो अजनबी था। गीता को आखिरी बार साल 2016 में एक पंजाबी फिल्म में देखा गया था।

लोटा-पुराण

पहले ही कहा जा चुका है कि लोटा किसी भी दिशा में लुढ़क-पुढक सकता है, इसीलिए वह 'लोटा' है। इस विशेष गुणवत्ता के लिए उसका बेपेंदी का होना ही चमत्कारिक गुण है। इसी चमत्कार के कारण वह 'लोटा' नामधारी विशेष संज्ञा से अभिहित किया जाता है। लोटे की इसी गुण से प्रेरणा लेकर जो कुर्सियां चार-चार पांव धारण करती थीं, वे एक ही स्थान पर जमी किसी भी दिशा में घूमने लगीं।

हम सभी यह अच्छी तरह से जानते हैं कि लोटा तो लोटा ही है। यदि लोटे को परिभाषित किया जाए तो 'लोटा वही है जिसे हर दिशा में लोटने की सुविधा प्राप्त हो।' लोटा अपने रंग, रूप, आकार और प्रकार में अन्य भाण्डों से कुछ इतर और भिन्न ही होता है। परंतु एक समानता सभी लोटों में समान रूप से पाई जाती है, वह है उसके हर एक दिशा में लोट पाने और पुन: उसी रूप में जम जाने का गुण।

लोटे की विविध रूपिणी विशेषताओं का यदि सूक्ष्म अध्ययन किया जाए तो वह बहु आयामीय होता है। वह प्राय: गोल मटोल और सदैव सुडौल ही होता है। उसका ऊपर का मुंह सदा खुला रहता है। उसमें नीचे कोई मुंह नहीं होता। क्योंकि यदि ऐसा होगा तो वह अपने भीतर जिस अपार क्षमता का धारक और वाहक होता है, वह समाप्त ही हो जाएगी। इसलिए यह सिद्धांत सर्वमान्य और सर्व स्वीकार्य है कि लोटे का मुंह सदा खुला रहता है। जब उसका मुंह सदैव खुला रहेगा तो यह भी स्वयं सिद्ध है कि उसमें कोई भी चीज कभी भी डाली जा सकती है। अर्थात् वह रात-दिन, सुबह-शाम, अंधेरे-उजाले कभी भी कुछ भी ग्रहण कर लेने की असीम क्षमता से युक्त होता है।

इस ढक्तन रहित लोटे की देह सदैव चिकनी रहती है। कब कहां फिसल जाए यह प्राकृतिक सुविधा उसे जन्म से ही प्राप्त है। वह अपने को इस प्रकार सज-संवार कर रखता है कि कोई भी उस पर फिसले तो उसे कभी भी कोई आपत्ति नहीं है, इंकार नहीं है। लोटे पर फिसलने वाला सदैव उसके मुंह के अंदर होता हुआ उसके असीम गहराई से युक्त उदर में समा जाता है। जब उदर की बात चली है, तो यहां पर यह स्पष्ट कर देना भी उचित प्रतीत होता है कि लोटे का उदर अनंत गहराइयों से युक्त एक अंधेरी गुफा की तरह है, जिसके समस्त रहस्यों का अभिज्ञान स्वयं लोटे को भी नहीं है।

पहले ही कहा जा चुका है कि लोटा किसी भी दिशा में लुढ़क-पुढक सकता है, इसीलिए वह 'लोटा' है। इस विशेष गुणवत्ता के लिए उसका बेपेंदी का होना ही चमत्कारिक गुण है। इसी चमत्कार के कारण वह 'लोटा' नामधारी विशेष संज्ञा से अभिहित किया जाता है। लोटे की इसी गुण से प्रेरणा लेकर जो कुर्सियां चार-चार पांव धारण करती थीं, वे एक ही स्थान पर जमी किसी भी दिशा में घूमने लगीं। वे अपने चारों पांवों को खो बैठीं। जीव विज्ञान का यह एक विशेष सिद्धांत है कि हम अपने जिस अंग का प्रयोग नहीं करते, शनै: शनै: विलुप्त हो जाता है। कहा गया है मानव पहले एक पशु है, बाद में मनुष्य। उसके भी पशुवत एक पूंछ कमर के नीचे गाय, भैंस, बंदर, गधा, घोड़ा की तरह लटकती रहती थी। उसने आलस्यवश अथवा अप्रयोग वश काम में नहीं लिया, इसलिए कालांतर में वह विलुप्त ही हो गई।

आपकी जानकारी के लिए यहां पर यह बता देना भी आवश्यक प्रतीत होता है कि पहले जमाने के लोटे पेंदी वाले ही हुआ करते थे। लेकिन जब लोटे ने देखा कि इस पेंदी की कोई विशेष उपयोगिता नहीं है, इसलिए उसने उसका प्रयोग करना ही बंद कर दिया। पहले के पेंदी वाले लोटों की अपनी एक अलग ही मान मर्यादा थी, जिसका अनुपालन करते हुए वे जब मनचाहा, लुढ़कते-पुढ़कते नहीं थे। एक जगह जमकर अपने कार्य का निष्पादन करते थे। पर अब क्या? अब तो रातों रात वे कायाकल्प कर लेते हैं। शाम को उनमें पीला-पीला बेसन भरा था, पर सुबह होते-होते उनमें देशी घी, मक्खन, रबड़ी और इसी प्रकार के मधुर सुस्वाद व्यंजन भरे दिखाई देते हैं। उनके इस रहस्य को थालियां, कटोरियां क्या समझें? हां, उनके समीपस्थ सेवक चमचे, चमच्चियां अवश्य जान समझ लेते हैं। क्योंकि इस उलट-पुलट में उनका अहम योगदान भी रहता है।

जब 'लोटा-पुराण' का पारायण किया ही जा रहा है, तो यह स्पष्ट कर देना भी आवश्यक है कि इन लोटों की अनेक श्रेणियां और प्रकार हैं। यद्यपि यह पृथक रूप से शोध का विषय है, तथापि एल्युमिनियम, लोहा, स्टील, पीतल, तांबा, चांदी, सोना आदि अनेक प्रकार के लोटे पाए जाते हैं। आज के युग में एल्युमिनियम और लोहे के लोटे का प्रचलन क्षीण हो गया है, इसलिए चमक-दमक वाले उच्च गुणवत्ताधारी लोटे ही प्रचलन में हैं। स्टील से कम तो शायद कोई लोटा मिलना ही दुर्लभ है। अपनी लोटा-यात्रा में ये स्टील, पीतल और तांबे के लोटे चांदी के लोटों में बदल जाते हैं। ये विज्ञान का नहीं, ज्ञान का चमत्कार है। अन्यथा पीतल, लोहा, तांबा को चांदी में बदलते हुए नहीं देखा सुना गया। जब लोटा चांदी के महिमावान स्तर को प्राप्त कर लेता है, तो उसका दर्जा सामान्य लोटे से असामान्य लोटे में आगणित किया जाता है। अब दचके-पिचके, छेद दार लोटों का युग नहीं है।

लोटों की नि:शुल्क यात्रा पूरे देश में अनवरत चलती रहती है। लोटा जितना चलता है, उतना ही बजता है। बजता अर्थात् बोलता है, मुंह तो उसका पहले से ही खुला हुआ है, इसलिए बिना ढक्कन, बिना धक्का धकापेल बोलता है। जो वह बोलता है, उसे वह ब्रह्मवाक्य मानता है। वस्तुत: लोटे की महिमा अपार है। भले ही यह संसार असार है, पर लोटे के लिए संसार ही सार है, क्योंकि संसार से ही उसका उद्धार है। इसलिए वह लोटे से थाली, परात नहीं बनना चाहता । वह सदा जन्म जन्मांतर तक लोटे की ही योनि में जन्म धारण कर अपने जीवन को धन्य करना चाहता है। इस लोटा योनि में जो स्वर्गिक सुख है, वह कटोरा, चमचा, चम्मच, थाली, परात की योनि में नहीं है। इससे वह स्व-उदर की सेवा सर्वाधिक कर पाने का सौभाग्य बटोर पाता है। धन्य है ये 'लोटा-योनि', जिससे लोटा कभी उऋण नहीं होना चाहता।

इति 'लोटा - पुराणम' समाप्यते।

● **डॉ. भगवत स्वरूप 'शुभम'**

PRISM®
CEMENT

प्रिज़्म® चैम्पियन प्लस

ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.

Toll free: 1800-3000-1444
Email: cement.customerservice@prismjohnson.in

दूर की सोच®

For Any Medical &
Pathology Equipments
Contact Us
Science House Medicals Pvt.Ltd.
17/1, Sector-1, Shanti Niketan, Near Chetak
Bridge, Bhopal (M.P.) INDIA-462023
GST. No. : 23AAPCS9224G1Z5 PH. : +91-0755-4241102, 4257687
Email : shbpl@rediffmail.com Fax : +91-0755-4257687